RNI NO-UPHIN/2023/84340

सबसे तेज प्रयागराज

सब पर नजर, सटीक खबर

नगर संस्करण sabsetejprj2023@gmail.com मंगलवार, 29 सितंबर 2026 वर्ष: 04, अंक: 189 पृष्ठ: 08, मूल्य: 2 रू. प्रयागराज से प्रकाशित हिन्दी दैनिक समाचार पत्र

यूपीआई लेनदेन पर शुल्क लगाने के फैसले पर केंद्र से जवाब तलब

केन्द्र, भारतीय रिजर्व बैंक एवं भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम को नोटिस जारी करके जवाब तलब किया

नई दिल्ली/एजेंसी
उच्चतम न्यायालय ने यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस (यूपीआई) से दो हजार रुपये से अधिक के वाणिज्यिक लेनदेन पर 0.4 प्रतिशत मर्चेंट डिस्काउंट रेट (एमडीआर)शुल्क लगाने के सरकार के निर्णय को चुनौती देने वाली याचिका पर केन्द्र, भारतीय रिजर्व बैंक एवं भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम को नोटिस जारी कर-के जवाब तलब किया।

हालांकि उच्चतम न्यायालय ने केंद्र सरकार के दो हजार रुपये से ज्यादा के लेनदेन के लिए जीरो-मर्चेंट डिस्काउंट रेट (एमडीआर) वाली कानूनी सुरक्षा को वापस लेने के फैसले पर फिलहाल रोक नहीं लगाई है।

उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली पीठ ने इस संबंध में एक याचिका की सुनवाई करते हुए केंद्र सरकार, भारतीय रिजर्व बैंक और भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम को नोटिस जारी करके यह बताने को कहा कि यूपीआई लेनदेन के लिए जीरो-मर्चेंट डिस्काउंट रेट वाली कानूनी सुरक्षा को वापस लेने का आधार क्या है। अदालत ने यह जवाब चार सप्ताह के भीतर दाखिल करने का निर्देश दिया है। याचिका में यह भी सवाल उठाया गया है कि

जब रुपे डेबिट कार्ड पर बिना किसी सीमा के निशुल्क लेनदेन की सुविधा जारी है, तो यूपीआई पर शुल्क लगाना भेदभावपूर्ण है। याचिका वकील अंजनी दत्ता ने दायर की है जिसमें 15 अक्टूबर से प्रभावी होने वाले प्रस्तावित यूपीआई लेनदेन पर शुल्क लगाने का विरोध किया गया है। याचिका में कहा गया है कि दो हजार रुपये से ऊपर के यूपीआई भुगतान पर लेवी लगाई गई है, वहीं बिना किसी मौद्रिक सीमा के रुपे संचालित डेबिट कार्ड पर समान नो-चार्ज सुरक्षा जारी रखी गई है। याचिका में देश भर में अनिवार्य भुगतान का बोझ डालने को चुनौती देते हुए कहा गया है, जिसमें लागत से जुड़े शोध, इसके पीछे की कार्यप्रणाली या लागत का बोझ ग्राहकों पर डालने से रोकने वाले मजबूत सुरक्षा उपायों का खुलासा नहीं किया गया है। याचिका में कहा गया है कि भले ही आधिकारिक तौर पर यह कहा गया हो कि व्यापारी इन लागतों का बोझ ग्राहकों पर नहीं डाल सकते, लेकिन रसीदों पर लगने वाली फीस आखिरकार कीमतों में शामिल हो ही जाएगी।

यूपीआई लेनदेन पर शुल्क लगाने का फैसला 15 अक्टूबर से लागू करने का फैसला किया

याचिका में कहा गया है कि भले ही आधिकारिक तौर पर यह कहा गया हो कि व्यापारी इन लागतों का बोझ ग्राहकों पर नहीं डाल सकते, लेकिन रसीदों पर लगने वाली फीस आखिरकार कीमतों में शामिल हो ही जाएगी। इससे कार्यशील पूंजी कम हो सकती है या कम मार्जिन वाले व्यापारी यूपीआई भुगतान लेने से इनकार कर सकते हैं या लेनदेन को कई हिस्सों में बांट सकते हैं।

सरकार ने यूपीआई लेनदेन पर शुल्क लगाने का फैसला 15 अक्टूबर से लागू करने का फैसला किया है। दो हजार रुपये से अधिक के व्यक्ति-से-व्यापारी लेनदेन पर 0.4 प्रतिशत एमडीआर शुल्क लगेगा। यह शुल्क सीधे सरकार के राजस्व में नहीं जाएगा, बल्कि इसे बैंक और पेमेंट एग्रीगेटर सेवा शुल्क के रूप में वसूलेंगे। उल्लेखनीय है कि पिछले लगभग छह वर्षों से यूपीआई भुगतान पूरी तरह निशुल्क थे। सरकार का कहना है कि एमडीआर एक सेवा शुल्क है, जो डिजिटल भुगतान प्रणाली को टिकाऊ बनाने और बैंकों एवं एग्रीगेटरों की लागत को संतुलित करने के लिए आवश्यक है। नई व्यवस्था में कुछ विशेष क्षेत्रों जैसे रेलवे, बीमा, दूरसंचार, ईंधन और कृषि इनपुट पर केवल 5 रुपए का एकसमान शुल्क लगेगा, जबकि म्यूचुअल फंड और सिक्योरिटीज में निवेश जैसे लेनदेन पर 0.02 प्रतिशत एमडीआर लगेगा, जिसे 300 रुपए तक सीमित किया गया है। वहीं, व्यक्ति-से-व्यक्ति लेनदेन और छोटे भुगतान पूरी तरह निशुल्क रहेंगे।

तीन भाषा नीति : छठी कक्षा के बच्चों को भी मिले इस साल छूट

नई दिल्ली। उच्चतम न्यायालय ने केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (सीबीएसई) की तीन भाषा नीति में कहा है कि इस साल छठी कक्षा के बच्चों को भी वही छूट दी जाए, जो सातवीं कक्षा के बच्चों को दी गई है। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली बेंच ने केंद्र सरकार की इस दलील को खारिज कर दिया कि देश के अधिकांश शिक्षण संस्थान इसी सत्र से इसे लागू करने के पक्ष में हैं। उच्चतम न्यायालय के इस आदेश का मतलब यह है कि सीबीएसई की तीन भाषा नीति पूरे तरीके से 2027-28 के शिक्षण सत्र से ही लागू हो सकेगी। इससे पहले 17 सितंबर को भी कोर्ट ने कक्षा 6 के छात्रों को राहत देने पर विचार करने को कहा था। कोर्ट ने कहा था कि चूंकि ये एक राष्ट्रीय नीति है, इसलिए इसमें एक तय संस्थागत ढांचा काम करता है। अगर कक्षा 7 से 10 तक के छात्रों को छूट दी गई है तो कक्षा 6 के छात्रों को ये राहत क्यों नहीं दी जा सकती। सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार ने कहा था कि कक्षा 6 के छात्रों को चार साल बाद बोर्ड परीक्षा का सामना करना है, इसलिए उन्हें अभी से तैयार करने की जरूरत है।

तीन भाषा नीति से जुड़ी व्यावहारिक समस्याओं पर विचार करने के लिए एक विशेष कमेटी का गठन किया गया

सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार ने कहा था कि कक्षा 6 के छात्रों को चार साल बाद बोर्ड परीक्षा का सामना करना है, इसलिए उन्हें अभी से तैयार करने की जरूरत है।

केंद्र सरकार ने कहा कि इस पूरे मामले और तीन भाषा नीति से जुड़ी व्यावहारिक समस्याओं पर विचार करने के लिए एक विशेष कमेटी का गठन किया गया है। याचिका छात्रों, अभिभावकों और शिक्षकों की ओर से दायर की गई थी। याचिका में कहा गया था कि सीबीएसई की नई तीन भाषा नीति में नौंवी कक्षा से दो और भाषाओं को पढ़ना अनिवार्य बनाया गया है। इन तीन भाषाओं में दो भारतीय भाषाओं का अध्ययन करना जरूरी है। याचिका में कहा गया था कि अचानक कक्षा नौ के छात्रों को दो अतिरिक्त भाषाओं का अध्ययन अनिवार्य करना उनकी दसवीं बोर्ड की तैयारी प्रभावित कर सकता है। वे अचानक दो भाषाएं कैसे सीख जाएंगे और दसवीं में उनकी परीक्षा देंगे। इससे छात्रों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ेगा।

पैक्ड फूड में ज्यादा चीनी-नमक और वसा का मामला, सुप्रीम कोर्ट का फैसला सुरक्षित

नई दिल्ली/एजेंसी
उच्चतम न्यायालय ने पैक्ड फूड में चीनी, नमक और वसा की अधिक मात्रा से बच्चों के स्वास्थ्य पर पड़ रहे बुरे प्रभावों के मामले में फैसला सुरक्षित रख लिया है। जस्टिस जेबी पारदीवाला की बेंच ने भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण (एफएसएसएआई) की ओर से अनुपालन के लिए एक साल का समय मांगने पर सवाल उठाया। इसके साथ ही कोर्ट ने एडेड शुगर की परिभाषा पर भी सवाल उठाया। कोर्ट ने सभी पक्षों को एक हफ्ते में लिखित दलीलें दाखिल करने का निर्देश दिया। सुनवाई के दौरान जब एफएसएसएआई की ओर से चेतावनी सम्बन्धी दिशा-निर्देश लागू करने के लिए एक साल का समय मांगा गया, तो कोर्ट ने पूछा कि ये नागरिकों के स्वास्थ्य से जुड़ा हुआ है, ऐसे में आप इतना लम्बा समय क्यों मांग रहे हैं। कोर्ट ने कहा कि हम यह पूरी कवायद देश के नागरिकों के हित में कर रहे हैं और हम उम्मीद करते हैं कि एफएसएसएआई कोर्ट के आदेश को वास्तविक भावना के रूप में स्वीकार करेगा। इससे पहले 10 सितंबर को भी सुनवाई के दौरान उच्चतम न्यायालय ने पैक्ड फूड से बच्चों की सेहत पर पड़ रहे बुरे प्रभावों पर चिंता जताई थी।

सोलर पैनल चोरी का खुलासा, चार आरोपी गिरफ्तार

19 सोलर प्लेट और घटना में प्रयुक्त लोडर बरामद

हनुमान प्रसाद शुक्ल

कौशाम्बी। सैनी पुलिस और सीआईडब्लू की संयुक्त टीम ने सोलर पैनल चोरी की दो घटनाओं का खुलासा करते हुए चार आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से चोरी किए गए 19 सोलर पैनल और वारदात में प्रयुक्त लोडर वाहन बरामद किया है। पुलिस के मुताबिक, आरोपी चोरी के सोलर पैनल बेचने के लिए प्रयागराज जा रहे थे।

पुलिस के अनुसार, 13 सितंबर 2026 को सैनी थाना क्षेत्र के डोरमा गांव में हाईवे किनारे स्थित आटा चक्की/तेल कारखाने से 16 सोलर पैनल चोरी कर लिए गए थे। मामले में नीरज पाण्डेय की तहरीर पर थाना सैनी में मुकदमा दर्ज किया गया था। इसके अगले दिन 14 सितंबर को चरवा थाना क्षेत्र के पकसराई गांव में जल जीवन मिशन के तहत बनी पानी की टंकी परिसर से भी सोलर पैनल चोरी होने की शिकायत मिली थी। इस मामले में संतोष कुमार केशरी की तहरीर पर मुकदमा दर्ज किया गया था।

लगातार हुई चोरी की घटनाओं को गंभीरता से लेते हुए पुलिस अधीक्षक कौशाम्बी सत्यनारायण ने घटनाओं के शीघ्र अनावरण और आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए तीन पुलिस टीमों का गठन किया था। जांच के दौरान सीसीटीवी फुटेज, सर्विलांस और स्थानीय लोगों से पूछताछ के आधार पर पुलिस को आरोपियों के बारे में सुराग मिला। मुखबिर की सूचना पर सीआईडब्लू और थाना सैनी पुलिस की संयुक्त टीम ने नेशनल हाईवे की सर्विस रोड से अलीपुरजीता जाने वाले मार्ग पर चार आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार आरोपियों की पहचान मोहित मौर्या, सोनू मौर्या और प्रांजुल कुमार, निवासी टेसाही बुजुर्ग, थाना खागा, जनपद फतेहपुर तथा पिन्टू लाल, निवासी बड़ी बाग मजरा कसराव, थाना हथिगांव, जनपद फतेहपुर के रूप में हुई है।

पूछताछ में आरोपियों ने बताया कि उन्होंने 12 सितंबर की रात डोरमा गांव में हाईवे किनारे स्थित आटा चक्की की छत पर पीछे के रास्ते से चढ़कर वहां लगे 16 सोलर पैनल खोलकर चोरी किए थे। इसके बाद पैनलों को लोडर में लादकर ले गए। अगले दिन चरवा क्षेत्र में सरकारी टंकी के पास लगे ट्यूबवेल से तीन और सोलर पैनल चोरी किए।

चोरी किए गए पैनलों को पिन्टू लाल के घर पर रखा गया था। आरोपी इन सभी पैनलों को बेचने के लिए प्रयागराज ले जा रहे थे।

पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से कुल 19 सोलर प्लेट और एक लोडर वाहन बरामद किया है। आरोपियों के खिलाफ विधिक कार्रवाई पूरी करने के बाद उन्हें न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है।

जनपद में चला अभियान 17 वारंटी गिरफ्तार

सबसे तेज प्रयागराज

कौशांबी। पुलिस अधीक्षक सत्यनारायण के निर्देश पर जनपद में आपरेशन चक्रव्यूह के तहत जनपद कौशाम्बी के थाना सराय अकिल पुलिस टीम द्वारा चोरी से सम्बन्धित एक वांछित अभियुक्त तथा थाना मंझनपुर, पश्चिम शरीरा, महेवाघाट, कौशाम्बी, सराय अकिल, चरवा, पिपरी, कोखराज व सैनी पुलिस टीम द्वारा 17 वारण्टी अभियुक्तों (कुल 18 अभियुक्तों) को गिरफ्तार किया गया ।

पुलिस ने दो वारंटी को गिरफ्तार कर भेजा जेल

सबसे तेज प्रयागराज

फतेहपुर । पुलिस अधीक्षक फतेहपुर अभिमन्यु मांगलिक के निर्देशन में वांछित/वारण्टियों की गिरफ्तारी एवं अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में सोमवार को थाना राधानगर पुलिस द्वारा डीपी से सम्बन्धित वारण्टी अभियुक्त रामविकास पुत्र रामचन्द्र निवासी ग्राम भोकरी मजरे जखनी थाना राधानगर जनपद फतेहपुर उम्र करीब 28 वर्ष को गिरफ्तार किया गया।

इसी प्रकार थाना सुल्तानपुर घोष पुलिस द्वारा से सम्बन्धित वारण्टी अभियुक्त हरिश्चन्द्र पुत्र छत्रपाल मौर्य निवासी ग्राम नयापुरवा मजरे शेखमऊ थाना सुल्तानपुर घोष जनपद फतेहपुर को गिरफ्तार किया गया।

सीडीओ की अध्यक्षता में राष्ट्रीय डिजिटल पशुधन मिशन की जिला स्तरीय क्रियान्वयन समिति की बैठक सम्पन्न

पशु चिकित्सा अधिकारी गौशालाओं का निरीक्षण कर कमियों का निस्तारण करायें

सबसे तेज प्रयागराज

प्रयागराज। डीएम मनीष कुमार वर्मा के निर्देशन एवं मुख्य विकास अधिकारी हर्षिका सिंह की अध्यक्षता में सोमवार को संगम सभागार में राष्ट्रीय डिजिटल पशुधन मिशन के जिला स्तरीय क्रियान्वयन समिति की बैठक आयोजित की गई। बैठक में मुख्य विकास अधिकारी ने कहा कि मा0 मुख्यमंत्री जी गौ संरक्षण के प्रति काफी संवेदनशील है अतएव सभी अधिकारी अपने दायित्वों का जिम्मेदारी के साथ निर्वहन करें, इसमें किसी भी प्रकार की लापरवाही क्षम्य नही होंगी, अगर किसी के द्वारा भी इस संबंध में लापरवाही बरती गई तो संबंधित के विरुद्ध कार्रवाई के लिए शासन को पत्र प्रेषित किया जाएगा।

मुख्य विकास अधिकारी ने गौशालाओं में संरक्षित गौवंशो की जियो टैगिंग कराए जाने के लिए कहा है। उन्होंने कहा कि प्रत्येक गौशालाओ में पर्याप्त मात्रा में भूसा, हरा चारा, चोकर साइनेज आदि की उपलब्धता सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने कहा कि अगर हरे चारे की उपलब्धता पर्याप्त मात्रा में नहीं हो पा रही है तो उसकी जगह पर साइलेज दिया जाए। कहा कि सभी गौ आश्रय स्थलों पर पशु आहार, जियो टैगिंग, मूवमेंट रजिस्टर, पशु टीकाकरण आदि का रजिस्टर बनाकर रखा जाए। पशु चिकित्सा अधिकारी गौशालाओं का निरीक्षण करें, जो कमियां हो उसका निस्तारण कराएं। मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी ने कहा कि गौशालाओं में वृक्षारोपण अभियान के तहत लगाए गए पौधे, जिनकी जियो टैगिंग नहीं हुई है उनकी समय से टैगिंग करा ली जाए। बैठक में मुख्य पशु चिकित्साधिकारी, खंड विकास अधिकारीगण व अन्य सम्बन्धित अधिकारी उपस्थित रहें।

फर्जी पुलिस अधिकारी बनकर ठगी करने वाले गिरोह के तीन सदस्य गिरफ्तार

सबसे तेज प्रयागराज

फतेहपुर। जनपदीय साइबर सेल और थाना जहानाबाद पुलिस ने फर्जी पुलिस अधिकारी व अन्य जांच एजेंसियों का अधिकारी बनकर लोगों को गिरफ्तारी और आजीवन कारावास का भय दिखाकर साइबर ठगी करने वाले गिरोह का भंडाफोड़ किया है। पुलिस ने गिरोह के तीन सदस्यों को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से घटना में प्रयुक्त मोबाइल फोन, सिम कार्ड और लैपटॉप बरामद किए हैं।

पुलिस के अनुसार, समन्वय पोर्टल पर प्राप्त साइबर फ्रॉड की शिकायतों के संबंध में 27 सितंबर को संदिग्ध मोबाइल नंबरों, बैंक खातों और संदिग्ध व्यक्तियों की जांच एवं सत्यापन किया गया। अभिलेखीय और इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्यों के आधार पर थाना जहानाबाद क्षेत्र के ग्राम नारायणपुर में फर्जी पुलिस अधिकारी बनकर लोगों को फोन करने वाले गिरोह की गतिविधियों का पता चला।

जांच में सामने आया कि गिरोह के सदस्य आम लोगों को फोन कर स्वयं को पुलिस अधिकारी या कर्मचारी बताते थे। इसके बाद मुकदमा दर्ज होने, गिरफ्तारी, आजीवन कारावास और अन्य कानूनी कार्रवाई का भय दिखाकर पीड़ितों से वित्तीय धोखाधड़ी करते थे।

पुलिस ने कार्रवाई करते हुए ग्राम नारायणपुर मजरे कलाना, थाना जहानाबाद निवासी अंकित सिंह (27) पुत्र रामशंकर, संतोष (21) पुत्र सूरजभान और सनी उर्फ दीपक (24) पुत्र स्व. करन सिंह को गिरफ्तार किया।

पुलिस के मुताबिक पूछताछ में आरोपियों ने फर्जी पुलिस अधिकारी व कर्मचारी बनकर लोगों को फोन करने तथा मुकदमा दर्ज होने और गिरफ्तारी समेत अन्य कानूनी कार्रवाई का भय दिखाकर आर्थिक धोखाधड़ी करने की बात बताई।

यह कार्रवाई पुलिस अधीक्षक फतेहपुर अभिमन्यु मांगलिक के निर्देशन, अपर पुलिस अधीक्षक के पर्यवेक्षण तथा क्षेत्राधिकारी नगर/साइबर के नेतृत्व में जनपदीय साइबर सेल एवं थाना जहानाबाद पुलिस टीम ने की।

गिरफ्तार तीनों आरोपियों को न्यायालय के आदेश के अनुपालन में जिला कारागार भेज दिया गया।

गैर इरादतन हत्या का अभियुक्त गिरफ्तार, निशांदेही से आलाकत्ल डन्डा बरामद

सबसे तेज प्रयागराज

कौशांबी । दिनांक 26 सितंबर को वादी धर्मपाल सिंह पुत्र नवाब सिंह निवासी म0न0 1337 चांदपुर रोड थाना कोतवाली नगर जनपद बुलन्दशहर ने थाना कोतवाली देहात पर तहरीर दी कि पिंटू पर शक है कि पिंटू ने ही उसके पुत्र रोमिल की मारपीट कर दी है जिसमें आयी चोटों के कारण उसकी मृत्यु हो गयी है। उक्त घटना के क्रम मे प्रकाश में आये अभियुक्त शिवम को सोमवार को थाना कोतवाली देहात पुलिस द्वारा को अडौली नहर पुल के पास से गिरफ्तार किया गया तथा उसकी निशांदेही पर आलाकत्ल डन्डा (बल्ली) बरामद की गयी है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम पता

शिवम पुत्र कन्हैया निवासी ग्राम काहिरा थाना कोतवाली देहात जनपद बुलन्दशहर ।

इंडी गठबंधन को चुनाव आयोग पर आरोप लगाने से पहले यह बताना चाहिए कि उसके आरोपों का ठोस प्रमाण क्या है- धर्मराज मौर्य

ब्यूरो चीफ सबसे तेज प्रयागराज

कौशांबी। भारतीय जनता पार्टी जिला कार्यालय मंझनपुर में इंडी गठबंधन द्वारा झूंठ भ्रम और अफवाह की राजनीति व लगातार लगाए जा रहे बेबुनियाद आरोपों को लेकर आयोजित प्रेस वार्ता को जिलाध्यक्ष धर्मराज मौर्य ने संबोधित किया।

आयोजित प्रेस वार्ता को जिलाध्यक्ष धर्मराज मौर्य ने संबोधित करते हुए कहा कि भारतीय जनता पार्टी का स्पष्ट मत है कि चुनाव लोकतंत्र का उत्सव हैं और चुनावी प्रक्रिया में जनता का विश्वास सर्वोपरि है। यदि किसी दल के पास मतदाता सूची अथवा चुनाव प्रक्रिया को लेकर कोई ठोस आपत्ति है तो उसे संवैधानिक और कानूनी प्रक्रिया के माध्यम से प्रमाण सहित सामने रखना चाहिए,न कि जनता के बीच भ्रम और अविश्वास का वातावरण बनाने का प्रयास करना चाहिए।इंडी गठबंधन को चुनाव आयोग पर आरोप लगाने से पहले यह बताना चाहिए कि उसके आरोपों का ठोस प्रमाण क्या है? केवल राजनीतिक बयान,प्रेस कॉन्फ्रेंस और सोशल मीडिया के दावों से संवैधानिक संस्थाओं की विश्वसनीयता पर प्रश्नचिह्न नहीं लगाया जा सकता। लोकतंत्र में सवाल पूछने का अधिकार सभी को है,लेकिन सवाल के साथ तथ्य और प्रमाण देना भी उतना ही आवश्यक है।जनता के बीच भ्रम फैलाकर चुनावी व्यवस्था के प्रति अविश्वास पैदा करना लोकतांत्रिक विमर्श को मजबूत नहीं करता। चुनाव आयोग की कार्यप्रणाली पर कोई ठोस शिकायत है तो उसके लिए कानून में निर्धारित प्रक्रियाएं मौजूद हैं। विपक्ष को उन संवैधानिक प्रक्रियाओं का सहारा लेना चाहिए,न कि बिना प्रमाण के आरोपों को राजनीतिक हथियार बनाना चाहिए। लोकतंत्र केवल चुनाव जीतने या हारने का नाम नहीं है,बल्कि लोकतांत्रिक संस्थाओं के सम्मान और जनादेश की मयार्दा बनाए रखने का भी नाम है। हार-जीत लोकतंत्र का हिस्सा है।चुनाव आयोग की आधिकारिक सफाई के बाद भी यदि बिना प्रमाण आरोप दोहराए जाते हैं,तो यह लोकतांत्रिक विमर्श को मजबूत करने के बजाय उसे कमजोर करता है।भाजपा संविधान,लोकतंत्र और चुनावी संस्थाओं की गरिमा के प्रति पूरी तरह प्रतिबद्ध है। जनता के जनादेश का सम्मान करना और चुनावी प्रक्रिया में विश्वास बनाए रखना हर राजनीतिक दल की जिम्मेदारी है।इस मौके पर जिला पंचायत अध्यक्ष कल्पना सोनकर,नगर पालिका अध्यक्ष मंझनपुर बीरेंद्र सरोज फौजी,भरवारी कविता पासी,चेयरमैन अजुहा शांति कुशवाहा,सिराथू राजेंद्र कुमार।

भारतीय डॉक्टर किसी भी स्तर पर कम नहीं : डॉ. विनोद सिंह

मौजी लाल रावत

फूलपुर। सहसों में रविवार को व्यापारियों की गोष्ठी आयोजित की गई। इसमें मनोहर दास आई हॉस्पिटल, प्रयागराज के वरिष्ठ नेत्र सर्जन डॉ. विनोद सिंह ने अमेरिका की चिकित्सा व्यवस्था और भारतीय चिकित्सा पद्धति से जुड़े अपने अनुभव साझा किए। उन्होंने कहा कि चिकित्सा ज्ञान, दक्षता और क्षमता के मामले में भारतीय डॉक्टर किसी भी स्तर पर कम नहीं हैं।

डॉ. विनोद सिंह ने बताया कि सात से 14 सितंबर तक उन्होंने अमेरिका की प्रतिष्ठित जॉन्स हॉपकिन्स यूनिवर्सिटी से रेटिना में फैलोशिप प्राप्त की। इस दौरान उन्होंने अपने मॉनिटर को भगवद्गीता की पुस्तक भी भेंट की।

उन्होंने कहा कि भारत और अमेरिका की चिकित्सा व्यवस्था में मुख्य अंतर मरीजों की संख्या और उपलब्ध सुविधाओं का है। भारत के सरकारी अस्पतालों में एक डॉक्टर को प्रतिदिन 500 से 800 और कई बार 1000 तक मरीज देखने पड़ते हैं, जबकि अमेरिका में एक डॉक्टर करीब 25 से 30 मरीजों को देखने के साथ आठ से 10 ऑपरेशन करता है।

डॉ. सिंह ने बताया कि अमेरिका में मरीज की बीमारी के साथ उसकी मानसिक स्थिति, चिंता और परेशानी को समझने पर भी विशेष जोर दिया जाता है। मरीज से आत्मीयता से बात करना और उसे भरोसा देना उपचार का महत्वपूर्ण हिस्सा माना जाता है। उन्होंने जूनियर डॉक्टरों, नर्सों और वार्ड बॉय को भी मरीजों के प्रति संवेदनशील और आत्मीय व्यवहार अपनाने की सलाह दी।

गोष्ठी में व्यापार मंडल के जिला महामंत्री भोलानाथ केसरवानी, शाश्वत तिवारी, संजय सिंह, अमन प्रकाश केसरवानी, ओम प्रकाश, लालजी केसरवानी, राजेश केसरवानी, विजय कुमार आदि उपस्थित रहे।

विकास खंड बहादुरपुर में सेवा संकल्प अभियान के तहत 'आंगन मिलन उत्सव' का भव्य आयोजन

राम सिंह यादव

झूंसी। विकास खंड बहादुरपुर में सेवा संकल्प अभियान के अंतर्गत आंगन मिलन उत्सव कार्यक्रम का आयोजन किया गया। बतौर मुख्य अतिथि विधायक फूलपुर दीपक पटेल ने दीप प्रज्वलन के साथ कार्यक्रम की शुरूआत की तथा विभिन्न विभागों द्वारा लगाए गए स्टाल का निरीक्षण भी किया कार्यक्रम को संबोधित करते हुए विधायक दीपक पटेल ने कहा कि समाज के अंतिम व्यक्ति तक स्वास्थ्य और पोषण की मूलभूत सुविधाएं पहुंचाने में आंगनवाड़ी कार्यकताओं की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है प्रयास करें कि हर घर तक सरकार योजना पहुंचे कोई भी इससे वंचित न रहे उन्होंने उत्कृष्ट कार्य करने वाली आंगनवाड़ी कार्यकताओं को सम्मानित किया और उनके समर्पण की सराहना की। मीडिया प्रभारी उमेश तिवारी ने बताया कि इस अवसर पर विधायक ने नन्हे-मुन्ने बच्चों का अन्नप्राशन कराया गया तथा गर्भवती माताओं की विधि-विधान से गोद भराई की रस्म भी पूरी की। मुख्य अतिथि ने माताओं और बच्चों को पोषण किट वितरित करते हुए उनके बेहतर स्वास्थ्य, समुचित पोषण और उज्वल भविष्य की मंगलकामना की। उन्होंने राज्य व केंद्र सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं की जानकारी देते हुए महिलाओं से इनका अधिक से अधिक लाभ उठाने का आह्वान किया।

कार्यक्रम में ब्लॉक प्रमुख बहादुरपुर अरुणेंद्र यादव ह्यडब्बूह्व ने बहादुरपुर क्षेत्र में चलाए जा रहे विकास एवं पोषण अभियानों पर प्रकाश डाला। इस दौरान पार्षद अरुण मिश्र, मंडल अध्यक्ष रणविजय सरोज, शीतला प्रसाद, आदित्य त्रिपाठी, भूपेन्द्र पांडेय सहित ब्लॉक के विभागीय अधिकारी कर्मचारी तथा भारी संख्या में आंगनवाड़ी कार्यकर्ता व अन्य लोग मौजूद रहे।

एडीएम नगर की अध्यक्षता में अभियोजन कार्यों की मासिक समीक्षा बैठक सम्पन्न

महिला अपराध, पॉक्सो एक्ट एवं अन्य गंभीर मामलों में त्वरित निस्तारण हेतु प्रभावी पैरवी करने के लिए कहा

सबसे तेज प्रयागराज

प्रयागराज। डीएम मनीष कुमार वर्मा के निर्देशन व अपर जिलाधिकारी नगर मंगलेश कुमार दुबे की अध्यक्षता में सोमवार को संगम सभागार में अभियोजन कार्यों की मासिक समीक्षा बैठक आयोजित की गयी। बैठक में जनपद में लंबित अभियोजन प्रकरणों, गंभीर अपराधों से संबंधित मामलों तथा न्यायालयों में लम्बित वादों के सम्बंध में विस्तार से समीक्षा की गई। बैठक में पिछले माह गंभीर अपराधों में कितने बरी हुए तथा कितने में अपील हुई, के संबध में विस्तार से चर्चा की गई।

अपर जिलाधिकारी ने उपस्थित समस्त शासकीय अधिवक्ताओं व अभियोजन संवर्ग के अधिकारियों को जघन्य अपराधों में प्रभावी पैरवी सुनिश्चित करने के लिए कहा। बैठक में अपर जिलाधिकारी ने संबंधित को निर्देशित किया कि शासन की मंशा के अनुरूप सभी प्रकरणों में प्रभावी पैरवी सुनिश्चित की जाए। उन्होंने विशेष रूप से महिला अपराध, पॉक्सो एक्ट, मादक पदार्थों से संबंधित प्रकरणों एवं अन्य गंभीर मामलों में त्वरित निस्तारण हेतु प्रभावी पैरवी करने के लिए कहा है। उन्होंने कहा कि जिन प्रकरणों में सम्मन/तामीला नहीं हो रहा है, उन प्रकरणों में अधिक से अधिक सम्मन तामीला कराकर प्रकरण का निस्तारण सुनिश्चित कराया जाये।

अपर जिलाधिकारी ने लंबित मामलों के कारणों की समीक्षा करते हुए संबंधित अधिकारियों को आवश्यक अभिलेख समय से न्यायालय में प्रस्तुत करने के लिए कहा। बैठक में संयुक्त निदेशक अभियोजन, जिला शासकीय अधिवक्ता सहित संबंधित अधिकारी उपस्थित रहे।

डांट से नाराज किशोरी अपने दो छोटे भाई-बहनों को लेकर लापता।

बहला-फुसलाकर ले जाने की आशंका में प्राथमिकी दर्ज

सबसे तेज प्रयागराज

बहरिया । थाना क्षेत्र के रैनी गांव से एक ही परिवार के तीन बच्चे संदिग्ध परिस्थितियों में लापता हो गए हैं। बच्चों की मां की तहरीर पर पुलिस ने गांव के ही एक युवक के खिलाफ मामला दर्ज कर बच्चों की तलाश शुरू कर दी है।

?मिली जानकारी के अनुसार, रैनी गांव निवासी मीना देवी पत्नी पवन कुमार गौतम ने पुलिस को दी तहरीर में बताया कि उनकी 17 वर्षीय बेटी ममता गांव के ही दीपक उर्फ राजा (पुत्र जयराम उर्फ कल्लू) से पिछले करीब दो वर्षों से बातचीत करती थी। इस बात को लेकर उन्होंने 23 और 24 सितंबर को अपनी बेटी को समझाया-बुझाया तथा डांटा था। डांट से नाराज होकर ममता 24 सितंबर को अपनी 14 वर्षीय बहन नीता और 10 वर्षीय भाई अर्जुन को साथ लेकर अपने पिता से मिलने के बहाने घर से निकल गई। बच्चों के साथ उनकी मां भी घर से निकली थीं। वे सभी गांव के ही एक ऑटो से फूलपुर पहुंचे। फूलपुर में सुबह लगभग 9:30 बजे ममता ने अपनी मां से कहा कि वह छोटे भाई और बहन के साथ दूसरे ऑटो से प्रयागराज जाएगी।

अंतरजनपदीय बैटरी चोर गिरोह का पदार्फाश, चार गिरफ्तार

27 चोरी की बैटरियां, दो कारें, चोरी के उपकरण और 6,040 रुपये बरामद; पुलिस टीम को 25 हजार का इनाम

हनुमान प्रसाद शुक्ल

फतेहपुर। थाना चांदपुर पुलिस ने अंतरजनपदीय बैटरी चोर गिरोह का पदार्फाश करते हुए चार शातिर अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने उनके कब्जे से विभिन्न कंपनियों की चोरी की 27 छोटी-बड़ी बैटरियां, चोरी में प्रयुक्त दो चार पहिया वाहन, उपकरण और 6,040 रुपये नकद बरामद किए हैं। गिरोह के खुलासे से थाना चांदपुर, जाफरगंज, सुल्तानपुर घोष और खागा क्षेत्र में हुई बैटरी चोरी की कई घटनाओं का अनावरण हुआ है।

पुलिस अधीक्षक फतेहपुर अभिमन्यु मांगलिक के निर्देशन में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के तहत यह कार्रवाई की गई। पुलिस के अनुसार, विवेचना, सुरागरसी-पतारसी और मुखबिर की सूचना के आधार पर 27 सितंबर 2026 की रात गश्त एवं चेकिंग के दौरान मकरन्दपुर चौराहा के पास चार अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्तों की पहचान आकिब पुत्र साबिर (22), निवासी बड़ा कुआं जहानपुर, थाना बिंदकी; आमिर पुत्र अजहर (24), निवासी लंका रोड बिंदकी; जावेद पुत्र गुलाम मोहम्मद (28), निवासी जहानपुर, थाना बिंदकी; तथा रवि गुप्ता पुत्र सुरेश चन्द्र गुप्ता (28), निवासी मदनपुर, थाना राधानगर के रूप में हुई है।

दो कारों से करते थे चोरी

पुलिस के मुताबिक, अभियुक्त चोरी की घटनाओं में सफेद रंग की ऑरा और ब्रेजा कार का इस्तेमाल करते थे। इनके पास से तीन पाना, 10 छोटे-बड़े रिंच, एक पकड़, एक प्लास और दो पेचकस भी बरामद हुए हैं।

इन घटनाओं का हुआ खुलासा

पुलिस के अनुसार, गिरोह ने चांदपुर थाना क्षेत्र में ई-रिक्शा और फैक्ट्री से बैटरी चोरी की चार घटनाओं को अंजाम दिया था। इसके अलावा जाफरगंज क्षेत्र में ई-रिक्शा से चार बैटरियां, सुल्तानपुर घोष क्षेत्र में ई-रिक्शा से चार बैटरियां तथा खागा क्षेत्र में ई-रिक्शा और सोलर पंप से बैटरियां चोरी की गई थीं।

पूछताछ में अभियुक्तों ने फतेहपुर के अलावा हमीरपुर जनपद के कोतवाली नगर और मौदहा थाना क्षेत्रों में भी बैटरी चोरी करने की बात पुलिस को बताई है। पुलिस अब इन घटनाओं और चोरी के माल की खरीद-फरोख्त से जुड़े अन्य लोगों के संबंध में भी जांच कर रही है।

कबाड़ कारोबारी को बेचते थे चोरी की बैटरियां

पुलिस के अनुसार, अभियुक्त संगठित गिरोह के रूप में सड़क किनारे खड़े ई-रिक्शा, सोलर पंप और अन्य वाहनों से बैटरियां चोरी

आत्मनिर्भर यूपी की राह में युवाओं के नवाचार को नई उड़ान, अलीगढ़ में यूपी राइज 2026

आरएमपीएसयू में 2,300 से अधिक छात्रों ने लिया हिस्सा, डिजिटल पहुंच 50 हजार पार

लखनऊ, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश के विजन को युवाओं के नवाचार, उद्यमिता और करियर अवसरों से जोड़ने की दिशा में राजा महेंद्र प्रताप सिंह स्टेट यूनिवर्सिटी, अलीगढ़ में यूपी राइज 2026 का आयोजन किया गया। प्रदेश सरकार के इस प्रमुख कैंपस इनोवेशन और करियर अभियान का आयोजन टाइम्स नेटवर्क और जूम के सहयोग से किया गया। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में विद्यार्थियों ने हिस्सा लेकर अपने नए विचारों और समाधान को मंच प्रदान किया।

अलीगढ़ में 2300 से अधिक छात्रों की भागीदारी

अलीगढ़ चरण में पंजीकरण, सीएम-युवा योजना से जुड़े जागरूकता कार्यक्रम और सभागार सत्र समेत 2,300 से अधिक छात्रों ने हिस्सा लिया। कार्यक्रम की डिजिटल पहुंच 50 हजार से अधिक रही, जबकि ऑफलाइन पहुंच भी 5 हजार से अधिक दर्ज की गई। विश्वविद्यालय में आयोजित इस कार्यक्रम ने युवाओं के बीच नवाचार और उद्यमिता को लेकर उत्साह को सामने रखा। आरएमपीएसयू स्वयं रचनात्मक

प्रतिभा, वैज्ञानिक सोच और विद्यार्थियों के करियर विकास को बढ़ावा देने पर जोर देता है।

बिल्ड फॉर यूपी पिच फाइनल में दिखी प्रतिभा

यूपी राइज 2026 के तहत परिसर में सीएम-युवा योजना जागरूकता स्टॉल, स्पिन द व्हील गतिविधि और ऑक्टोनॉर्म मेंटरशिप जोन लगाए गए। लॉबी और गलियारों में आयोजित इन गतिविधियों के माध्यम से विद्यार्थियों को योजनाओं, करियर विकल्पों और अपने विचारों को व्यावहारिक रूप देने के अवसरों से परिचित कराया गया। इसके बाद सभागार में बिल्ड फॉर यूपी पिच प्रतियोगिता का फाइनल आयोजित हुआ।

13 छात्र टीमों ने पेश किए नवाचार आधारित समाधान

प्रतियोगिता में चयनित 13 छात्र टीमों ने निर्णायकों और उपस्थित विद्यार्थियों के सामने अपने विचार प्रस्तुत किए। प्रतिभागियों ने स्थानीय समस्याओं के व्यावहारिक समाधान, नए व्यवसाय मॉडल और सामाजिक उपयोगिता से जुड़े प्रस्ताव रखे। प्रतियोगिता का विजेता प्रस्ताव तेज रोशनी वाली हेडलाइट्स के कारण होने वाली सड़क दुर्घटनाओं को कम करने के उद्देश्य से तैयार सुरक्षा-केंद्रित समाधान पर आधारित रहा। विजेता टीम को मंच पर 25 हजार रुपये का नकद पुरस्कार प्रदान किया गया, जबकि फिक्सेज ग्रुप को उपविजेता घोषित किया गया। यूपी राइज के पहले के चरणों में भी विद्यार्थियों के स्टार्टअप विचारों को पिचिंग और पुरस्कार के माध्यम से प्रोत्साहित किया गया है।

सात शहरों के बाद अलीगढ़ पहुंचा यूपी राइज

कार्यक्रम में भाजपा उत्तर प्रदेश के मंत्री एवं राज्य मीडिया प्रभारी यतेंद्र शर्मा मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद रहे। उन्होंने विद्यार्थियों के नवाचार, रचनात्मक सोच और उद्यमशीलता को प्रोत्साहित किया। अलीगढ़ चरण के साथ यूपी राइज 2026 का विश्वविद्यालय दौरा कानपुर, आगरा, लखनऊ, रायबरेली, मथुरा, बरेली और सहारनपुर तक पहुंच चुका है।

भंडारे में गाड़ी निकालने पर विवाद, पूर्व उपसभापति ने पिस्टल अड़ाकर धमकाने का लगाया आरोप

चमनगंज में प्रसाद वितरण के दौरान चार पहिया वाहन निकालने को लेकर हुई घटना, वीडियो वायरल

झांसी, उत्तर प्रदेश के झांसी में सीपरी बाजार थाना क्षेत्र के चमनगंज में गणेश उत्सव के बाद आयोजित भंडारे के दौरान चार पहिया वाहन निकालने को लेकर विवाद हो गया। वाहन रोकने को लेकर शुरू हुआ विवाद मारपीट तक पहुंच गया। भाजपा पार्षद बंटी बुंदेला ने वाहन सवार युवक और उसके साथियों पर मारपीट करने तथा पिस्टल अड़ाकर धमकाने का आरोप लगाया है। दोनों पक्षों की ओर से पुलिस को शिकायत दी गई है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। फिलहाल एक दिन बाद अब सोशल मीडिया पर घटना का वीडियो जमकर वायरल हो रहा है।

सीपरी बाजार थाना क्षेत्र के चमनगंज की केवल दुग्ध वाली गली में कई वर्षों से गणेश उत्सव का आयोजन होता आ रहा है। इस वर्ष भी आयोजक समिति ने गणेश प्रतिमा स्थापित की थी। रविवार को प्रतिमा विसर्जन के बाद भंडारा प्रसाद वितरण का कार्यक्रम चल रहा था।

देर रात भंडारा स्थल से चार पहिया वाहन निकालने का प्रयास किया गया। आयोजकों ने भीड़ और भंडारे के चलते वाहन निकालने से मना किया। इसी बात को लेकर वाहन सवार युवक और आयोजकों के बीच कहासुनी हो गई। विवाद बढ़ने पर दोनों पक्षों में हाथापाई हो गई।

इसी दौरान क्षेत्रीय भाजपा पार्षद बंटी बुंदेला भी मौके पर पहुंचे। आरोप है कि वाहन सवार युवक ने अपने कुछ साथियों को बुला लिया, जिसके बाद दोनों पक्षों के बीच विवाद और बढ़ गया। सूचना मिलने पर सीपरी बाजार थाने का पुलिस बल मौके पर पहुंचा और दोनों पक्षों को समझाकर मामला शांत कराया।

बाद में पार्षद बंटी बुंदेला ने पुलिस को शिकायती आवेदन देकर वाहन सवार युवक और उसके साथियों पर मारपीट करने तथा पिस्टल अड़ाकर धमकाने का आरोप लगाया। दूसरे पक्ष की ओर से भी पुलिस को शिकायत दी गई है।

संवैधानिक संस्थाओं पर आरोप लगाना कांग्रेस की हताशा का प्रतीक: बिहारीलाल आर्य

कांग्रेस संवैधानिक विषयों को राजनीतिक ढाल बनाकर भ्रम फैला रही: पवन गौतम

झांसी, भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) कार्यालय में सोमवार को आयोजित पत्रकार वार्ता में महापौर बिहारीलाल आर्य और जिला पंचायत अध्यक्ष पवन गौतम ने कांग्रेस पर संवैधानिक संस्थाओं को लेकर भ्रम फैलाने का आरोप लगाया।

महापौर बिहारीलाल आर्य ने कहा कि लगातार चुनावी पराजय से कांग्रेस हताश है और अपनी राजनीतिक नाकामियों को छिपाने के लिए चुनाव आयोग समेत संवैधानिक संस्थाओं पर बेबुनियाद आरोप लगा रही है।

उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग के संयुक्त बयान के बाद कांग्रेस और विपक्षी गठबंधन की ओर से लगाए जा रहे कई आरोपों पर स्थिति स्पष्ट हो चुकी है। उनके अनुसार मुख्य चुनाव आयुक्त और दोनों चुनाव आयुक्तों की सर्वसम्मति से एसआईआर समेत चुनाव संबंधी निर्णय पारदर्शी तरीके से लिए गए हैं।

उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट भी चुनावी प्रक्रिया से जुड़े मामलों में वैधानिक पहलुओं को स्पष्ट कर चुका है।

बिहारीलाल आर्य ने आरोप लगाया कि राहुल गांधी और कांग्रेस नेतृत्व लगातार ईवीएम, न्यायपालिका और चुनाव आयोग जैसे संस्थानों की विश्वसनीयता पर सवाल उठाकर जनता के बीच भ्रम की स्थिति पैदा करने का प्रयास कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि लोकतांत्रिक संस्थाओं की गरिमा बनाए रखना सभी राजनीतिक दलों की जिम्मेदारी है।

जिला पंचायत अध्यक्ष पवन गौतम ने कहा कि जब विपक्ष जनता की अदालत में पराजित होता है तो वह अपनी राजनीतिक कमजोरियों की समीक्षा करने के बजाय लोकतांत्रिक संस्थाओं पर आरोप लगाने लगता है। उन्होंने कांग्रेस से संगठनात्मक कमियों पर आत्ममंथन करने की बात कही। साथ ही संवैधानिक संस्थाओं और जनता से कथित दुष्प्रचार के लिए बिना शर्त माफी मांगने की मांग की।

उत्तर प्रदेश के फतेहपुर में सिलेंडर फटने से दो मंजिला मकान ढहा, 4 की मौत

फतेहपुर, उत्तर प्रदेश के फतेहपुर जिले में सोमवार की शाम को खाना बनाते समय सिलेंडर में अचानक आग लगने से तेज विस्फोट हो गया। धमाका इतना जोरदार था कि दो मंजिला मकान भर-भराकर ढह गया। इस घटना में एक ही परिवार के चार लोगों की मौत हो गई, जबकि तीन अन्य लोग घायल हो गये, जिन्हें मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया ।

मलवां थाना क्षेत्र स्थित कस्बा मलवां निवासी कस्बा निवासी सूरज गुप्ता के घर में खाना बनाते समय सिलेंडर में आग लग गई, जिससे सिलेंडर फटने से मकान भरभरा कर ढह गया। मौके पर परिवार के लोग मौजूद थे। मकान ढहने से कितने लोग मलबे में दबे हैं, इसकी जानकारी की अभी तक नहीं हो पा रही है। ग्रामीणों ने तुरंत बचाव कार्य शुरू किया। सूचना मिलते ही पुलिस और फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंच गई और मलबे में दबे लोगों को निकालने का प्रयास शुरू किया जा रहा है। अभी तक 07 लोगों को निकाला जा चुका है, जिनमें 04 लोगों की मौत हो गई। 03 लोग घायल हैं, जिन्हें अल्लीपुर मेडिकल कालेज भेजा गया। प्रशासनिक अधिकारी भी मौके पर पहुंच रहे हैं। रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है पुलिस अधीक्षक अभिमन्यु मांगलिक ने बताया कि सिलेंडर फटने की घटना की सूचना पर पीआरवी व मलवां थाने का फोर्स मौके पर पहुंच कर राहत व बचाव कार्य तेजी से शुरू किया है।

यह वह भारत है जहां गरीब अब केवल सहायता का पात्र नहीं,बल्कि सम्मान के साथ आगे बढ़ने का अधिकारी है– धर्मराज

ब्यूरो चीफ सबसे तेज प्रयागराज

कौशांबी। विधानसभा सिराथू के विकास खण्ड सिराथू एवं विधानसभा मंझनपुर के विकास खण्ड मंझनपुर में सेवा संकल्प अभियान के तहत लगे सात दिवसीय सेवा सेतु शिविर का जिलाध्यक्ष धर्मराज मौर्य ने फीता काट शुभारंभ किया व लगे स्टॉलों का अवलोकन एवं नवजात शिशुओं को अन्नप्राशन करा कर संबोधित किया।

जिलाध्यक्ष धर्मराज मौर्य ने धात्री महिलाओं को पोषण पोटली एवं उत्कृष्ट कार्य करने वाली आंगनवाड़ी बहनों को आँगन मिलन सेवा का प्रशस्ति पत्र वितरण कर संबोधित करते हुए कहा कि हमारी डबल इंजन सरकार की नीति का मूल मंत्र रहा है सबका साथ,सबका विकास,सबका विश्वास और सबका प्रयास। सरकार का प्रयास रहा है कि विकास का लाभ समाज की अंतिम पंक्ति में खड़े व्यक्ति तक पहुंचे और कोई भी परिवार मूलभूत सुविधाओं से वंचित न रहे।पहले गरीब के लिए बैंक खाता एक सपना था,आज जनधन खाते के माध्यम से वह बैंकिंग व्यवस्था से जुड़ रहा है।पहले बीमारी गरीब परिवार की वर्षों की कमाई छीन लेती थी,आज आयुष्मान भारत जैसी योजनाओं ने पात्र परिवारों को स्वास्थ्य सुरक्षा का सहारा दिया है।पहले गरीब परिवार के लिए पक्का मकान एक सपना था,आज प्रधानमंत्री आवास योजना सम्मान और सुरक्षित जीवन का माध्यम बन रहा है।पहले हमारी माताएं-बहनें धुएं से भरे चूल्हे पर खाना बनाने को मजबूर थीं,आज उज्ज्वला योजना के माध्यम से स्वच्छ ईंधन तक उनकी पहुंच बढ़ी है।पहले गांव की बहनों को पानी के लिए दूर-दूर तक जाना पड़ता था,आज हर घर जल के संकल्प के साथ नल से जल पहुंचाने का अभियान चल रहा है।इस मौके पर क्षेत्रीय उपाध्यक्ष अनीता त्रिपाठी,चेयरमैन सिराथू राजेंद्र कुमार यादव,बब्लू श्रीवास्तव,मण्डल अध्यक्ष कसिया जितेंद्र मौर्य,मण्डल अध्यक्ष मंझनपुर मनमोहन कुशवाहा,ब्लॉक प्रमुख प्रतिनिधि हुबलाल दिवाकर,मण्डल महामंत्री विपिन यादव,ज्ञानू मौर्य सहित सम्मानित कार्यकर्तागण एवं माताएं बहनें उपस्थित रहीं।

प्रदेश अध्यक्ष रोहित मिश्रा का कार्यकताओं ने किया स्वागत

सबसे तेज प्रयागराज

नवाबगंज। सोमवार को लखनऊ से प्रयागराज जाते समय कौड़िहार चौराहे पर युवा मोर्चा के भाजपा प्रदेश अध्यक्ष रोहित मिश्रा का भाजपा कार्यकताओं ने फूल मालाओं के साथ जोरदार स्वागत किया।

इस मौके पर राम कैलाश सरोज ,मंडल अध्यक्ष भाजपा कुलदीप शुक्ला, मंडल अध्यक्ष युवा मोर्चा कौड़िहार आनंद पाण्डेय मुखिया, संदीप मोदनवाल, महामंत्री युवा मोर्चा कुलदीप गिरी मंडल उपाध्यक्ष प्रवीण शंकर दुबे विवेक केसरवानी मोनू सिंह अंजनी यादव अंजनी उपाध्याय रवि केसरवानी प्रधान कौड़िहार राजू पाण्डेय रोहित शुक्ला प्रवीण शुक्ला राम शिरोमणि दुबे बांके शाहू प्रमोद मिश्रा गुरु, शैलेश शुक्ला दिलीप मिश्रा प्रधान आदमपुर बच्चे लाल शुक्ला आनंद मोदनवाल ,बिपिन कसेरा, दीपक कसेरा आदि मौजूद रहे।

गंदगी और प्रदूषण फैलाने पर टकसाल सिनेमा प्रबंधन पर 04 हजार रुपये का जुमार्ना

वाराणसी, उत्तर प्रदेश के वाराणसी शहर में स्वच्छता और पर्यावरण संरक्षण को लेकर नगर निगम की ओर से चलाए जा रहे अभियान के तहत सार्वजनिक मार्ग पर गंदगी फैलाने के मामले में टकसाल सिनेमा प्रबंधन के खिलाफ कार्रवाई की गई है। नगर निगम ने नदेसर राजा बाजार स्थित टकसाल सिनेमा परिसर में ध्वस्तीकरण के दौरान सड़क पर मलबा और मिट्टी फैलाने पर चार हजार रुपये का जुमार्ना लगाया है। ताज होटल के सामने स्थित टकसाल सिनेमा परिसर में इन दिनों तोड़-फोड़ और ध्वस्तीकरण का कार्य चल रहा है। आरोप है कि ध्वस्तीकरण से निकलने वाले मलबे और मिट्टी को उचित तरीके

से हटाने के बजाय सड़क और आसपास के मार्ग पर फैला दिया गया। इससे क्षेत्र में गंदगी के साथ ही धूल और प्रदूषण की स्थिति उत्पन्न हो गई।

नगर निगम के स्वास्थ्य विभाग के स्वच्छता निरीक्षण के दौरान मामला सामने आने पर नगर आयुक्त हिमांशु नागपाल के निर्देश पर तत्काल कार्रवाई की गई। उत्तर प्रदेश ठोस अपशिष्ट प्रबंधन, संचालन एवं स्वच्छता नियमावली-2021 की धारा 46 के तहत आकाश राय (टकसाल) के खिलाफ मौके पर चार हजार रुपये का स्थलीय जुमार्ना लगाते हुए चालान काटा गया।

कार्रवाई के साथ ही नगर निगम की ओर से संबंधित स्थल और मार्ग पर सफाई व्यवस्था भी शुरू करा दी गई।

नगर आयुक्त ने स्पष्ट किया कि सार्वजनिक स्थानों पर गंदगी फैलाने और स्वच्छता एवं पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने वालों के खिलाफ नगर निगम आगे भी कार्रवाई जारी रखेगा। उन्होंने कहा कि शहर की स्वच्छता व्यवस्था से खिलवाड़ करने वाले किसी भी व्यक्ति या संस्थान को बख्शा नहीं जाएगा।

जिलाजज, डीएम,कप्तान ने जनपद कारागार का किया निरीक्षण, बंदियों की खानपान व्यवस्था को देखा

सबसे तेज प्रयागराज

फतेहपुर । सोमवार को जिला न्यायाधीश सुधीर कुमार-श, जिलाधिकारी फतेहपुर श्रीमती निधि गुप्ता वत्स एवं पुलिस अधीक्षक फतेहपुर अभिमन्यु मांगलिक द्वारा संयुक्त रूप से जिला कारागार फतेहपुर का औचक निरीक्षण किया गया।

निरीक्षण के दौरान कारागार की सुरक्षा व्यवस्था, साफ-सफाई, बंदियों के आवासीय बैरकों, खान-पान तथा अन्य व्यवस्थाओं का गहनता से परीक्षण किया गया। अधिकारियों द्वारा कारागार प्रशासन को सुरक्षा व्यवस्था को और अधिक सुदृढ़ बनाए रखने, बंदियों को नियमानुसार सुविधाएं उपलब्ध कराने तथा अनुशासन बनाए रखने हेतु आवश्यक दिशा-निर्देश दिए गए। साथ ही अभिलेखों का भी अवलोकन कर आवश्यक सुधार हेतु निर्देशित किया गया। इस दौरान जेल अधीक्षक सहित अन्य अधिकारी एवं कर्मचारीगण उपस्थित रहे।

पुलिस कार्रवाई की मांग को लेकर विहिप-बजरंग दल कार्यकताओं का प्रदर्शन, एसीपी को सौंपा ज्ञापन

लखनऊ, पुलिस कार्रवाई की मांग को लेकर विश्व हिंदू परिषद (विहिप) और बजरंग दल के सैकड़ों कार्यकताओं ने सोमवार को पुलिस कमिश्नर कार्यालय का घेराव किया। कार्यकताओं ने ठाकुरगंज, दुबग्गा और हसनगंज थाना क्षेत्रों से जुड़े मामलों में कार्रवाई नहीं होने का आरोप लगाते हुए पुलिस प्रशासन के खिलाफ नाराजगी जताई। बाद में पुलिस अधिकारियों के 24 घंटे में कार्रवाई के आश्वासन पर कार्यकताओं ने एसीपी महानगर अंकित कुमार को ज्ञापन सौंपा और शांतिपूर्ण तरीके से लौट गए।

विहिप के संगठन मंत्री समरेंद्र प्रताप ने आरोप लगाया कि पुलिस प्रशासन को कई बार शिकायत और ज्ञापन देने के बावजूद मामलों में अपेक्षित कार्रवाई नहीं हुई। उन्होंने कहा कि तीन दिन पहले भी ज्ञापन दिया गया था, लेकिन कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई, जिसके बाद कार्यकताओं को प्रदर्शन के लिए मजबूर होना पड़ा।

उन्होंने आरोप लगाया कि ठाकुरगंज थाना क्षेत्र में एक बजरंग दल कार्यकर्ता पर हमला किया गया और गोली भी चलाई गई, लेकिन आरोपितों की गिरफ्तारी नहीं हुई।

इसी तरह दुबग्गा थाना क्षेत्र में एक हिंदू युवती के अपहरण का आरोप लगाते हुए उन्होंने कहा कि पुलिस अब तक युवती को बरामद नहीं कर सकी है, जिससे परिवार परेशान है।

दलित मजदूर पर जानलेवा हमला करने वाले आरोपी को नहीं मिली जमानत

झांसी, विशेष न्यायाधीश अनुसूचित जाति अत्याचार निवारण अधिनियम नेत्रपाल सिंह की अदालत ने दलित मजदूर पर जानलेवा हमला करने के आरोपी को जमानत देने से इनकार करते हुए उसका जमानत प्रार्थना पत्र निरस्त कर दिया।

आरोपी पर लाठी-डंडों से हमला कर मजदूर का पैर तोड़ने का आरोप है।

अभियोजन पक्ष की ओर से पैरवी कर रहे शासकीय अधिवक्ता केशवेंद्र प्रताप सिंह ने बताया कि बरुआसागर थाना क्षेत्र में 11 अगस्त 2026 को दलित मजदूर मलखान अहिरवार ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी। आरोप लगाया गया कि रामपाल यादव निवासी संदरी, जिला निवाड़ी (मध्य प्रदेश) ने उस पर जानलेवा हमला किया और लाठी-डंडों से बेरहमी से पीटा। हमले में मजदूर का पैर टूट गया।

शिकायत के आधार पर पुलिस ने संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज कर आरोपी रामपाल यादव को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था।

हत्या के दो दोषियों को आजीवन कारावास की सजा

कोर्ट ने दोनों पर लगाया 50-50 हजार रुपये का जुमार्ना, असलहा अधिनियम में भी अलग-अलग सजा

प्रयागराज, उत्तर प्रदेश के प्रयागराज जिले में स्थित बारा थाने की पुलिस टीम के प्रभावी पैरवी की वजह से सोमवार को हत्या मामले के दो आरोपितों को अपर सत्र न्यायाधीश, कक्ष संख्या-02, ने आजीवन कारावास की सजा से दंडित किया। यह जानकारी पुलिस उपायुक्त यमुनानगर विवेक चन्द्र यादव ने दी।

डीसीपी ने बताया कि प्रयागराज के बारा थाने में 30 अप्रैल 2018 को बारा थाने में चित्रकूट जिले के बड़गड़ थाना क्षेत्र के गाहुर पंडित का पुरवा, निकट कटैया डांडी निवासी अजय पाण्डेय और इसी थाना क्षेत्र के रैपुरा गांव निवासी मनीष शुक्ला के खिलाफ हत्या और आयुध अधिनियम की धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया था। विवेचना पूरी करने के बाद पुलिस ने 10 अप्रैल को पुलिस टीम ने न्यायालय को आरोप पत्र भेज दिया। ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत प्रभावी पैरवी के चलते बारा थाना क्षेत्र के वर्ष 2018 के हत्या के मामले में न्यायालय ने दो अभियुक्तों को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। अपर सत्र न्यायाधीश, कक्ष संख्या-02, प्रयागराज की अदालत ने अभियुक्त अजय पाण्डेय और

मनीष शुक्ला को धारा 302/34 भारतीय दंड संहिता के तहत सश्रम आजीवन कारावास और 50-50 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया।अभियोजन के अनुसार, 30 अप्रैल 2018 को बारा थाने में दोनों के खिलाफ हत्या और आयुध अधिनियम की धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया था। विवेचना पूरी करने के बाद पुलिस ने 10 अगस्त 2018 को न्यायालय में आरोपपत्र दाखिल किया।मामले में अभियोजन विभाग से समन्वय कर पुलिस ने साक्ष्यों और गवाहों को समयबद्ध तरीके से न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत कराया। प्रभावी पैरवी के परिणामस्वरूप 28 सितंबर 2026 को न्यायालय ने दोनों अभियुक्तों को दोषी करार दिया।

अदालत ने मनीष शुक्ला को आयुध अधिनियम की धारा 30 के तहत तीन माह के कारावास और दो हजार रुपये के अर्थदंड की अतिरिक्त सजा सुनाई। वहीं, अजय पाण्डेय को आयुध अधिनियम की धारा 3/25/27 के तहत चार वर्ष के कारावास और आठ हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया गया। पुलिस के अनुसार, घटना के समय वादी का चचेरा भाई सर्वेश ग्राम डाडो में एक शादी समारोह में गया था।

आरोप है कि अजय पाण्डेय ने उससे किसी काम के लिए कहा, लेकिन मना करने पर मनीष शुक्ला की लाइसेंसी बंदूक से सर्वेश को गोली मार दी, जिससे उसकी मौत हो गई।

संपादकीय

पितरों के प्रति कर्तव्य : स्मृति से संस्कार तक

मनुष्य कितना भी आधुनिक क्यों न हो जाए, उसकी जड़ें अपने परिवार, समाज, संस्कृति और पूर्वजों से जुड़ी रहती हैं। वर्तमान का व्यक्तित्व अतीत की अनेक पीढ़ियों के अनुभव, संघर्ष, संस्कार और त्याग से निर्मित होता है। हम जिस परिवार, नाम, संस्कार और सामाजिक पहचान के साथ जीवन जीते हैं, उसके पीछे हमारे माता-पिता और पूर्वजों का महत्वपूर्ण योगदान होता है। इसलिए पितरों का स्मरण केवल धार्मिक परंपरा नहीं, बल्कि अपने अस्तित्व की जड़ों के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करने का अवसर भी है।

भारतीय संस्कृति में पितृ-स्मरण की परंपरा अत्यंत प्राचीन है। श्राद्ध, तर्पण और पिंडदान जैसे धार्मिक कर्मों के माध्यम से पूर्वजों के प्रति श्रद्धा व्यक्त की जाती है। इन परंपराओं का बाहरी स्वरूप चाहे धार्मिक हो, लेकिन उनका मूल भाव स्मरण, कृतज्ञता, श्रद्धा और अपने पूर्वजों के प्रति ऋण स्वीकार करने में निहित है। यह भाव मनुष्य को अहंकार से दूर करता है और उसे यह याद दिलाता है कि जीवन की यात्रा में वह अकेला नहीं है।

हमारे पूर्वजों ने अपने समय की परिस्थितियों में संघर्ष किया, परिवार को संभाला, अभावों से जूझे और आने वाली पीढ़ियों के लिए बेहतर जीवन की नींव रखी। उनकी सबसे बड़ी विरासत केवल जमीन-जायदाद या भौतिक संपत्ति नहीं थी। उनका वास्तविक धन था– ईमानदारी, परिश्रम, त्याग, अनुशासन, सहनशीलता, करुणा और परिवार के प्रति जिम्मेदारी।

इसीलिए पितरों के प्रति कर्तव्य को केवल कर्मकांड तक सीमित करना उचित नहीं होगा। यदि हम श्रद्धा से उनका स्मरण करते हैं, तो उनके श्रेष्ठ मूल्यों को अपने जीवन में अपनाना भी हमारी जिम्मेदारी है।

जीवित माता-पिता की सेवा सबसे बड़ी श्रद्धांजलि

पितृ-स्मरण का सबसे महत्वपूर्ण पक्ष यह है कि हम अपने जीवित माता-पिता और बुजुर्गों के प्रति कितने संवेदनशील हैं। किसी दिवंगत पूर्वज के लिए श्रद्धा व्यक्त करना महत्वपूर्ण हो सकता है, लेकिन उसी परिवार में जीवित माता-पिता अकेलेपन, उपेक्षा या भावनात्मक दूरी का अनुभव करें, तो हमें अपने व्यवहार पर भी विचार करना चाहिए।

आज संयुक्त परिवारों का स्वरूप तेजी से बदल रहा है। रोजगार, शिक्षा और बेहतर अवसरों की तलाश में परिवार अलग-अलग शहरों और देशों में बस रहे हैं। इसका एक सकारात्मक पक्ष है कि लोगों को नए अवसर मिलते हैं, लेकिन दूसरी ओर बुजुर्गों के अकेलेपन की समस्या भी सामने आती है। कई बार उनके पास आर्थिक सुविधाएँ होती हैं, परंतु भावनात्मक साथ नहीं होता।

बुजुर्गों को सबसे अधिक आवश्यकता सम्मान, संवाद और अपनत्व की होती है। उनके साथ कुछ समय बैठना, उनकी बात ध्यान से सुनना, उनके अनुभवों का सम्मान करना और आवश्यकता पड़ने पर उनका सहारा बनना किसी भी धार्मिक अनुष्ठान से कम महत्वपूर्ण नहीं है। जिस घर में जीवित माता-पिता सम्मानित होते हैं, वही घर वास्तव में पितृ-संस्कारों का सम्मान करता है।

पितृ-ऋण चुकाने का अर्थ क्या है?

पितृ-ऋण कोई ऐसा ऋण नहीं जिसे धन से चुकाया जा सके। यह एक भावनात्मक और नैतिक जिम्मेदारी है। इसे चुकाने का अर्थ है–पूर्वजों से मिले अच्छे संस्कारों को आगे बढ़ाना और परिवार तथा समाज के प्रति अपने दायित्वों का ईमानदारी से निर्वहन करना।

यदि हमारे पूर्वजों ने कठिन परिस्थितियों में शिक्षा को महत्व दिया, तो हमें अगली पीढ़ी की शिक्षा के लिए गंभीर होना चाहिए। यदि उन्होंने जरूरतमंदों की मदद की, तो हमें भी अपनी क्षमता के अनुसार किसी जरूरतमंद का सहारा बनना चाहिए। यदि उन्होंने ईमानदारी से जीवन जिया, तो हमें भी कठिन परिस्थितियों में ईमानदारी का रास्ता नहीं छोड़ना चाहिए।

हड़ताल — सुविधा मांगने का असुविधाजनक तरीका

प्रो. आरके जैन अरिजीत

मांग किसी की हो, कीमत अक्सर किसी और को चुकानी पड़ती है। बैंक कर्मचारियों की मांग हो तो बैंक बंद, बस मालिकों की हो तो परिवहन व्यवस्था ठप, ट्रक ऑपरेटरों की हो तो माल ढुलाई ठप, डॉक्टरों की हो तो अस्पतालों की रफ्तार धीमी और शिक्षकों की हो तो पढ़ाई प्रभावित। क्षेत्र अलग, समस्याएं अलग और संगठन अलग, लेकिन हड़ताल की पटकथा लगभग एक–चेतावनी, बंद, वार्ता, आश्वासन और फिर कुछ दिनों की शांति। फिर नया मुद्दा, नई चेतावनी और वही पुराना चक्र। इस सिलसिले में सबसे स्थायी किरदार वही है, जो न कर्मचारी है, न प्रबंधन और न नीति-निर्माता–आम आदमी, जो हर बार बिना मांग किए इसकी कीमत चुकाता है।

आठ लाख बैंक कर्मचारी पांच दिवसीय बैंकिंग सप्ताह, पीएलआई योजना की वापसी/संशोधन और पेंशन अपडेशन समेत अन्य लंबित मुद्दों की मांग को लेकर हड़ताल की चेतावनी दे रहे हैं। सवाल इन मांगों से ज्यादा उस व्यवस्था पर है, जो समाधान तक पहुंचने से पहले हड़ताल की स्थिति बना देती है। काम के घंटे, पारिश्रमिक, पेंशन और सेवा-शर्तें कर्मचारियों के महत्वपूर्ण मुद्दे हैं; इन पर बातचीत होना स्वाभाविक है। फिर समाधान हड़ताल तक क्यों पहुंचे? जब यूनियन और प्रबंधन के बीच संस्थागत संवाद का रास्ता मौजूद है, तो बैंक बंद करने की नौबत क्यों आए? और यदि मार्च 2024 में समझौता हो चुका था, तो उसकी अधिसूचना अब तक क्यों नहीं हुई? हर बार हड़ताल की तारीख नजदीक आने पर ही व्यवस्था क्यों जागती है?

हड़ताल की घोषणा कर्मचारी करते हैं, लेकिन उसकी तैयारी आम आदमी को करनी पड़ती है। खबर आते ही सलाह–जरूरी लेनदेन निपटा लें, नकदी निकाल लें, चेक जमा कर दें, पेंशन का काम करा लें। यानी व्यवस्था ठप होने का इंतजाम भी नागरिक करे! डिजिटल बैंकिंग बढ़ी है, पर भारत सिर्फ महानगरों की मोबाइल स्क्रीन नहीं। छोटे शहरों, कस्बों और गांवों में बैंक शाखा आज भी जरूरी है। पेंशनर को काउंटर चाहिए, छोटे व्यापारी को बैंकिंग व्यवस्था और लाखों लोगों के लिए हर काम ऐप से संभव नहीं। तीन दिन बैंक बंद रहना बड़े कारोबारी के लिए असुविधा हो सकता है, लेकिन बुजुर्ग की दवा, दुकानदार का भुगतान या परिवार की जरूरी रकम अटक जाए तो उसकी कीमत बड़ी होती है।

हड़ताल जहां काम रोकती है, वहीं उसका असर आम आदमी की जिंदगी रोक देता है। बस मालिक किराया बढ़ाने की मांग पर हड़ताल करें तो यात्री की राह और जेब, दोनों प्रभावित होते हैं। ट्रक ऑपरेटर लागत और टोल का मुद्दा उठाएं तो माल की आवाजाही रुकती है और कीमतें बढ़ती हैं। डॉक्टरों की हड़ताल में मरीज इंतजार करता है, बिजली कर्मचारियों के आंदोलन में घर-कारोबार प्रभावित होते हैं और शिक्षकों के आंदोलन में विद्यार्थियों का समय जाता है। हड़ताल खत्म होने पर वार्ता में मांगों का हिसाब होता है, लेकिन मरीज का इंतजार, मजदूरी का नुकसान, रुका कारोबार और बढ़ी कीमतों का हिसाब कहीं नहीं होता।

हड़ताल खत्म होते ही व्यवस्था ऐसे चल पड़ती है, मानो जनता की जिंदगी में कुछ रुका ही नहीं था। कुछ मांगें मान ली जाती हैं, कुछ समितियों के हवाले, कुछ आश्वासनों में और कुछ अगली बैठक की फाइल में चली जाती हैं। बैठकें होती हैं, बयान आते हैं और मामला शांत। लेकिन उन तीन दिनों का क्या, जब बैंक के चक्कर काटता नागरिक अपना काम नहीं करा सका? छोटे व्यापारी का अटका भुगतान, पेंशनर का टला काम, कर्मचारी की गई मजदूरी और मरीज का बिगड़ा इलाज–इनका हिसाब कौन देगा? न कोई मुआवजा, न जवाबदेही, न प्रतिपूरक व्यवस्था। जैसे आम आदमी की परेशानी कोई लागत ही नहीं, जिसे हर आंदोलन बेझिझक जनता के खाते में डाल दे।

दुनिया की सबसे तेज बढ़ती अर्थव्यवस्था बनने की ओर भारत

महेन्द्र तिवारी

भारत की अर्थव्यवस्था को लेकर वैश्विक संस्थाओं का दृष्टिकोण तेजी से बदल रहा है। कुछ महीने पहले जिन अंतरराष्ट्रीय एजेंसियों ने ऊँची ऊर्जा कीमतों, वैश्विक अनिश्चितता और भू राजनीतिक तनाव के कारण भारत की विकास दर का अनुमान घटा दिया था, वही एजेंसियां अब वित्त वर्ष 2027 के लिए अपने अनुमान बढ़ा रही हैं। प्रमुख रेटिंग एजेंसी मूडीज ने भारत की सकल घरेलू उत्पाद वृद्धि दर का अनुमान 6 प्रतिशत से बढ़ाकर 7 प्रतिशत कर दिया है। अन्य वैश्विक संस्थानों ने भी निवेश, घरेलू खपत और विनिर्माण क्षेत्र की मजबूती के आधार पर अपने आर्थिक आकलनों में सुधार किया है।

यह बदलाव केवल आंकड़ों का संशोधन नहीं है, बल्कि भारतीय अर्थव्यवस्था की उस संरचनात्मक क्षमता का संकेत है जिसने अनेक वैश्विक चुनौतियों के बावजूद विकास की गति बनाए रखी है। जब दुनिया की कई बड़ी अर्थव्यवस्थाएं धीमी वृद्धि, महंगाई और व्यापारिक अनिश्चितता से जूझ रही हैं, तब भारत का लगातार तेज गति से आगे बढ़ना उसे वैश्विक अर्थव्यवस्था का प्रमुख विकास इंजन बना रहा है।

सकल घरेलू उत्पाद किसी देश की आर्थिक गतिविधियों का सबसे व्यापक मापदंड माना जाता है। इसमें कृषि, उद्योग, सेवा, निर्माण, परिवहन, व्यापार और विभिन्न आर्थिक क्षेत्रों में एक वर्ष के दौरान उत्पन्न कुल मूल्य को शामिल किया जाता है। विकास दर बढ़ने का अर्थ यह नहीं कि हर नागरिक तुरंत समृद्ध हो जाएगा, बल्कि इसका संकेत यह है कि उत्पादन, निवेश, रोजगार और आय सृजन की क्षमता मजबूत हो रही है। यही कारण है कि वैश्विक निवेशक और रेटिंग एजेंसियां विकास दर को किसी भी अर्थव्यवस्था की सेहत का महत्वपूर्ण संकेतक मानती हैं।

भारत के पक्ष में सबसे बड़ा कारण उसकी मजबूत घरेलू मांग है। लगभग 140 करोड़ की आबादी वाला देश एक विशाल उपभोक्ता बाजार प्रदान करता है। जब वैश्विक निर्यात में उतार चढ़ाव आता है, तब भी घरेलू खपत भारतीय अर्थव्यवस्था को स्थिर बनाए रखती है। हाल के महीनों में शहरी उपभोग, खुदरा बिक्री, आवास क्षेत्र और सेवा गतिविधियों में सुधार देखने को मिला है। कम आधारभूत महंगाई और परिवारों की बढ़ती आय ने उपभोग को सहारा दिया है। यही कारण है कि कई अर्थशास्त्री भारत को बाहरी झटकों के मुकाबले अपेक्षाकृत अधिक लचीली अर्थव्यवस्था मान रहे हैं।

विनिर्माण क्षेत्र भी इस सकारात्मक बदलाव का प्रमुख आधार बनकर उभरा है। पिछले कुछ वर्षों में उत्पादन आधारित प्रोत्साहन योजनाओं, रक्षा उत्पादन, इलेक्ट्रॉनिक्स निर्माण, सेमीकंडक्टर परियोजनाओं और औद्योगिक गलियारों पर विशेष बल दिया गया है। इसका परिणाम यह हुआ कि अनेक वैश्विक कंपनियों ने भारत को केवल बाजार नहीं, बल्कि उत्पादन केंद्र के रूप में देखना शुरू किया है। मोबाइल, इलेक्ट्रॉनिक उपकरण, ऑटोमोबाइल पुर्जे और रक्षा सामग्री के निर्माण में उल्लेखनीय विस्तार दर्ज किया गया है। इससे रोजगार और निर्यात दोनों को नई गति मिलने की संभावना बढ़ी है।

पहली तिमाही में भारत की आर्थिक वृद्धि लगभग 7.8 प्रतिशत रही, जिसने अधिकांश विशेषज्ञों के अनुमान को पीछे छोड़ दिया। निवेश मांग, निर्माण गतिविधियों और सेवा क्षेत्र की मजबूती ने इस प्रदर्शन में महत्वपूर्ण योगदान दिया। यही आंकड़ा वैश्विक एजेंसियों के लिए सबसे बड़ा संकेत बना कि भारत की आर्थिक गति अनुमान से कहीं अधिक मजबूत है। परिणामस्वरूप मूडीज सहित कई संस्थानों ने वित्त वर्ष 2027 के लिए अपने अनुमान संशोधित किए।

सार्वजनिक पूंजीगत व्यय भी इस कहानी का एक महत्वपूर्ण अध्याय है। केंद्र सरकार ने सड़क, रेल, बंदरगाह, हवाई अड्डे, जलमार्गों और डिजिटल अवसंरचना पर बड़े पैमाने पर निवेश जारी रखा है। वित्त वर्ष 2027 के बजट में भी पूंजीगत व्यय को उच्च प्राथमिकता दी गई है तथा राजकोषीय घाटे को नियंत्रित रखने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। इसका उद्देश्य केवल तत्काल रोजगार पैदा करना नहीं, बल्कि दीर्घकाल में उत्पादकता और निजी निवेश के लिए आधार तैयार करना है।

सेवा क्षेत्र भारत की सबसे बड़ी आर्थिक शक्ति बना हुआ है। सूचना प्रौद्योगिकी, वित्तीय सेवाएं, पर्यटन, स्वास्थ्य, शिक्षा और डिजिटल सेवाओं ने लगातार वृद्धि दर्ज की है। कृत्रिम बुद्धिमत्ता, डिजिटल भुगतान और ऑनलाइन सेवाओं के विस्तार ने नई आर्थिक गतिविधियों को जन्म दिया है। भारतीय कंपनियां वैश्विक डिजिटल अर्थव्यवस्था में अपनी उपस्थिति मजबूत कर रही हैं, जिससे विदेशी निवेशकों का विश्वास भी बढ़ा है।

कृषि क्षेत्र को लेकर भी आशावाद और सावधानी दोनों मौजूद हैं। एक ओर कृषि उत्पादकता में सुधार, सिंचाई विस्तार और प्रौद्योगिकी आधारित खेती के प्रयास जारी हैं, वहीं दूसरी ओर कमजोर मानसून और अल नीनो जैसी मौसमी परिस्थितियां खाद्य उत्पादन को प्रभावित कर सकती हैं। यदि खाद्यान्न उत्पादन पर असर पड़ता है तो खाद्य महंगाई बढ़ सकती है, जिसका प्रभाव ग्रामीण आय और उपभोग दोनों पर पड़ेगा। इसलिए विकास दर के साथ कृषि स्थिरता भी समान रूप से महत्वपूर्ण बनी हुई है।

वैश्विक एजेंसियों ने भारत की प्रशंसा करते हुए यह भी स्पष्ट किया है कि जोखिम पूरी तरह समाप्त नहीं हुए हैं। पश्चिम एशिया में जारी तनाव के कारण कच्चे तेल की कीमतें बढ़ सकती हैं। भारत अपनी ऊर्जा आवश्यकताओं का बड़ा हिस्सा आयात करता है, इसलिए तेल महंगा होने पर परिवहन, उर्वरक और उत्पादन लागत पर दबाव बढ़ सकता है। हालांकि भारत ने पिछले वर्षों में अपने कच्चे तेल के आयात स्रोतों में विविधता लाई है और उसके पास पर्याप्त विदेशी मुद्रा भंडार भी मौजूद है, जो ऐसे झटकों से आंशिक सुरक्षा प्रदान करता है।

राजकोषीय अनुशासन भी भारत की आर्थिक विश्वसनीयता का महत्वपूर्ण आधार है। अंतरराष्ट्रीय रेटिंग एजेंसियां केवल विकास दर नहीं देखतीं, बल्कि यह भी मूल्यांकन करती हैं कि सरकार कितना कर्ज ले रही है, घाटा कितना है और भविष्य में ऋण चुकाने की क्षमता कैसी रहेगी। मूडीज ने भारत की स्थिर रेटिंग बनाए रखते हुए यह माना है कि सरकार धीरे धीरे राजकोषीय घाटा कम करने की दिशा में आगे बढ़ रही है। इससे निवेशकों का भरोसा मजबूत होता है क्योंकि स्थिर सार्वजनिक वित्त दीर्घकालिक आर्थिक विकास के लिए आवश्यक माना जाता है।

निजी निवेश में बढ़ती सक्रियता भी उत्साहजनक संकेत है। बैंकिंग प्रणाली की मजबूत बैलेंस शीट, घटते फंसे ऋण, बेहतर ऋण उपलब्धता और औद्योगिक क्षमता विस्तार ने उद्योग जगत को नए निवेश के लिए प्रोत्साहित किया है। यदि निजी पूंजी निवेश लगातार बढ़ता है तो रोजगार, आय और उत्पादन की एक सकारात्मक श्रृंखला विकसित होती है, जिससे विकास दर टिकाऊ बनती है।

रोजगार का प्रश्न इस पूरी बहस का सबसे संवेदनशील पक्ष है। उच्च विकास दर तभी सार्थक होगी जब उसके लाभ व्यापक समाज तक पहुंचें। विनिर्माण, निर्माण, पर्यटन और सेवा क्षेत्रों में रोजगार सृजन की संभावना अवश्य बढ़ी है, लेकिन कौशल विकास, श्रम उत्पादकता और छोटे उद्योगों की प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता को मजबूत करना भी उतना ही आवश्यक है। भारत की युवा आबादी एक बड़ा अवसर है, बशर्ते उसे गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और रोजगार के अवसर मिलें।

सूखा नशा, वेब सीरीज और अश्लील रील संस्कृति से भी बढ़ रही महिला असुरक्षा की घटनाएँ

विनोद कुमार विक्की

बिहार के जमुई में कोचिंग से लौट रही दसवीं कक्षा की छात्रा के साथ युवकों द्वारा सरेआम छेड़छाड़ और उसका वीडियो वायरल होने की घटना ने सभ्य समाज और मानवीयता को एक बार फिर शर्मसार कर दिया है। हालांकि इस प्रकरण में बिहार पुलिस की त्वरित कार्रवाई और आरोपियों की गिरफ्तारी सराहनीय है। किंतु घटनाक्रम के कुछ दिन बाद बिहार के समस्तीपुर और देश की राजधानी दिल्ली से भी छेड़छाड़ की अन्य विडियो एवं तस्वीरें वायरल हुई है।

इस वर्ष जून में राजस्थान के श्रीगंगानगर में नाबालिग लड़की के साथ 30 से अधिक लोगों द्वारा सामूहिक दुष्कर्म, अगस्त में दिल्ली की चलती बस में दुष्कर्म तथा सितंबर में संत स्वरूप नगर में दुष्कर्म एवं हत्या की घटनाओं के साथ-साथ पश्चिम बंगाल के बारुईपुर दुष्कर्म-हत्याकांड, सारण और बेगूसराय के सामूहिक दुष्कर्म जैसे मामलों को देश अभी भूल भी नहीं पाया था कि बक्सर में कथित शिक्षकों द्वारा दर्जनों छात्राओं के साथ कथित यौन उत्पीड़न का मामला सामने आया। इसी बीच जमुई की घटना ने एक बार फिर महिला सुरक्षा और नारी अस्मिता को लेकर गंभीर सवाल खड़े कर दिए।

छेड़छाड़ और दुष्कर्म जैसे महिला उत्पीड़न के अनेक मामले लोक-लज्जा, सामाजिक दबाव और भय के कारण थानों तक पहुँच ही नहीं पाते। जो मामले दर्ज होते हैं, वे समस्या की पूरी तस्वीर नहीं दिखाते। यौन हिंसा का सबसे भयावह रूप तब सामने आता है, जब दुष्कर्म के साथ हत्या या सामूहिक दुष्कर्म जैसी घटनाएँ जुड़ जाती हैं और यौन अपराध सीधे जीवन के अधिकार पर हमला बन जाता है।

वर्ष 2024 के आंकड़ों पर आधारित, वर्ष 2026 में जारी एनसीआरबी की हालिया रिपोर्टके अनुसार देश में महिलाओं के खिलाफ अपराध के कुल 4.41 लाख से अधिक मामले दर्ज किए गए थे, जिसमें घरेलू हिंसा, अपहरण और अन्य अपराध शामिल हैं। आंकड़ों के अनुसार, अपराध दर (प्रति लाख आबादी) 66.2 से घटकर 64.6 होने के बावजूद रेप के पंद्रह हजार से अधिक मामले दर्ज हुए। इस हिंसा का सबसे क्रूर चेहरा तब दिखता है जब मर्डर विद रेप/गैंगरेप के सैकड़ों मामले सामने आते हैं। जहां यौन अपराध सीधे हत्या में बदल जाते हैं।

हाल ही में चर्चित निठारी कांड के दोषी और मृत शरीर से यौनिक सुख प्राप्त करने के बाद उसे पकाकर खाने वाले दरिंदे सुरेंद्र कोली की मौत की खबर ने इस ओर फिर से ध्यानाकर्षित किया है। ऐसे दरिंदे हमारे तथाकथित सभ्य समाज में हमारे बीच ही रहते हैं। कानून सशक्त होने के बावजूद आए दिन शर्मसार करने वाली घटनाएं परिलक्षित होती है।

दो वर्षीया कन्या से साठ साल की वृद्धा तक ऐसे यौनिक कुंठा से ग्रस्त मानसिक रोगियों का शिकार हो रहे हैं। गौरतलब है कि अधिकांश मामलों में बलात्कारियों का कोई आपराधिक इतिहास नहीं होता। कई मामलों में आरोपी पड़ोसी, रिश्तेदार, परिचित, मित्र या सहकर्मी के रूप में पीड़िता के आसपास ही मौजूद होते हैं। इसलिए केवल किसी अजनबी को खतरे के रूप में देखना पर्याप्त नहीं है। सामाजिक संबंधों के भीतर मौजूद जोखिमों के प्रति भी सजग रहना आवश्यक है।

गैंगरेप के मामलों में एक सवाल विशेष रूप से विचारणीय है,जब कई लोग किसी अपराध में शामिल होते हैं। तब क्या समूह में एक भी ऐसा व्यक्ति नहीं होता जिसकी चेतना और विवेक उसे उस अपने साथियों को उस कुकृत्य से रोक सके? भीड़ में शामिल होकर व्यक्ति का विवेक समाप्त हो जाना समाज के लिए बेहद गंभीर चिंता का विषय है।

यौन हिंसा को केवल व्यक्ति विशेष की मानसिकता अथवा चारित्रिक पतन का परिणाम मानकर समस्या का समाधान नहीं किया जा सकता। इसके पीछे अनेक सामाजिक, पारिवारिक, मनोवैज्ञानिक और सांस्कृतिक कारण हो सकते हैं। मोबाइल तकनीक और इंटरनेट की आसान उपलब्धता ने जहाँ सूचना और मनोरंजन को हमारी मुट्ठी में ला दिया है, वहीं अश्लील सामग्री, आपत्तिजनक रीलों, पोर्नोग्राफिक वेबसाइटों तथा बिना पर्याप्त अभिभावकीय निगरानी के डिजिटल सामग्री तक पहुँच ने नई चुनौतियाँ भी पैदा की हैं। वेब सीरीज या किसी एक माध्यम को सीधे दुष्कर्म का कारण मानना उचित नहीं होगा, लेकिन यौनिक सामग्री के अनियंत्रित और कम उम्र में संपर्क के प्रभाव पर गंभीर सामाजिक विमर्श और शोध की आवश्यकता अवश्य है।

इसी तरह शराब और अन्य नशीले पदार्थों के दुरुपयोग को भी नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। नशा अपराध का स्वतः कारण नहीं है, लेकिन कई हिंसक घटनाओं में नशे की भूमिका जोखिम को बढ़ाने वाले कारक के रूप में सामने आ सकती है।

कानून का सशक्त होना आवश्यक है, लेकिन केवल कानून बना देने से समाज सुरक्षित नहीं हो जाता। कानून के प्रभावी क्रियान्वयन के साथ बच्चों और युवाओं में लैंगिक संवेदनशीलता, सहमति की समझ, पारिवारिक संवाद, डिजिटल साक्षरता और नैतिक शिक्षा को भी मजबूत करना होगा। परिवार, विद्यालय, समाज, प्रशासन और डिजिटल मंचों,सभी को अपनी-अपनी जिम्मेदारी समझनी होगी।

नारी को केवल भोग की वस्तु नहीं, बल्कि समान अधिकार और गरिमा रखने वाले मनुष्य के रूप में देखने की सामाजिक दृष्टि विकसित करनी होगी। जब तक स्त्री की इच्छा, सहमति और सम्मान को व्यवहार का अनिवार्य हिस्सा नहीं बनाया जाएगा, तब तक कानून और तकनीक दोनों अकेले इस समस्या का स्थायी समाधान नहीं दे सकते।

बेरोजगारी और विकास : भारत 2014-2026

लेखक : सी. ए. डॉ. शंकर घनश्याम दास अंधानी

भारत में 2014 से 2026 के बीच आर्थिक विकास के साथ रोजगार का प्रश्न लगातार महत्वपूर्ण बना रहा है। इस अवधि में बुनियादी ढांचा, डिजिटल अर्थव्यवस्था, विनिर्माण, सेवा क्षेत्र, स्टार्टअप और स्वरोजगार में विस्तार हुआ, लेकिन रोजगार की संख्या के साथ उसकी गुणवत्ता और नियमितता भी महत्वपूर्ण चुनौती रही है। रोजगार की स्थिति समझने के लिए सरकार का प्रमुख आधिकारिक स्रोत आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण (पीएलएफएस) है, जिसकी शुरुआत 2017 में हुई।

बेरोजगारी की स्थिति

सरकारी आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण के अनुसार 2017-18 से 2019-20 के बीच रोजगार में उल्लेखनीय वृद्धि हुई। 2018-19 से 2019-20 के दौरान लगभग 4.75 करोड़ अतिरिक्त लोग रोजगार से जुड़े। इनमें लगभग 2.99 करोड़ महिलाएं थीं। हालांकि, इनमें लगभग 65 प्रतिशत नए रोजगार स्वरोजगार की श्रेणी में थे और महिला स्वरोजगार का बड़ा हिस्सा अवैतनिक पारिवारिक काम से संबंधित था। इससे स्पष्ट होता है कि केवल रोजगार की संख्या बढ़ना पर्याप्त नहीं है; आय, सामाजिक सुरक्षा और रोजगार की गुणवत्ता भी महत्वपूर्ण हैं।

2025 के आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण की वार्षिक रिपोर्ट में 15 वर्ष और उससे अधिक आयु के लोगों की श्रम बल भागीदारी दर 59.3 प्रतिशत रही। पुरुषों के लिए यह 79.1 प्रतिशत और महिलाओं के लिए 40.0 प्रतिशत थी। शिक्षित व्यक्तियों की बेरोजगारी दर 2024 के 7.0 प्रतिशत से घटकर 2025 में 6.5 प्रतिशत हुई। नियमित वेतनभोगी रोजगार की हिस्सेदारी भी 22.4 प्रतिशत से बढ़कर 23.6 प्रतिशत हुई।

2026 की स्थिति

आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण के नए मासिक आंकड़े रोजगार बाजार की अधिक नियमित निगरानी उपलब्ध कराते हैं। जुलाई 2026 में 15 वर्ष और उससे अधिक आयु के लोगों के लिए वर्तमान साप्ताहिक स्थिति के आधार पर बेरोजगारी दर 5.1 प्रतिशत, श्रम बल भागीदारी दर 55.4 प्रतिशत और श्रमिक जनसंख्या अनुपात 52.5 प्रतिशत दर्ज किया गया।

विकास और रोजगार की चुनौती

आर्थिक विकास में निवेश और बुनियादी ढांचे की भूमिका महत्वपूर्ण रही है। आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 में रोजगार एवं कौशल विकास को स्वतंत्र प्रमुख विषय के रूप में शामिल किया गया है। साथ ही उद्योग, सेवा, बुनियादी ढांचा, शिक्षा और कौशल के बीच बेहतर तालमेल पर जोर दिया गया है।

निष्कर्ष

2014-2026 के दौरान भारत की विकास यात्रा में रोजगार के कई सकारात्मक संकेत दिखाई देते हैं, लेकिन युवाओं, महिलाओं और शिक्षित वर्ग के लिए पर्याप्त, नियमित और बेहतर वेतन वाले रोजगार का विस्तार अभी भी महत्वपूर्ण चुनौती है। आगे भारत को केवल सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि नहीं, बल्कि रोजगार-सृजन वाली विकास रणनीति पर अधिक जोर देना होगा–विशेषकर विनिर्माण, सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम, आधुनिक कृषि, कौशल प्रशिक्षण, डिजिटल सेवाओं और महिला रोजगार के क्षेत्र में।

चुनाव आयोग की आड़ में फिर विपक्ष का मोदी सरकार पर हमला

अजय कुमार

एक अंग्रेजी अखबार की रिपोर्ट के आधार पर विपक्षी दलों ने एक बार फिर मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार को घेरकर निर्वाचन आयोग की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल खड़े करके मोदी सरकार को कटघरे में खड़ा करने की सियासी कोशिश शुरू कर दी है। अखबार की रिपोर्ट में दावा किया गया कि तीन सदस्यीय चुनाव आयोग में दो चुनाव आयुक्तों, सुखबीर सिंह संधू और विवेक जोशी ने पिछले 10 महीनों में कम से कम 14 बार आयोग के उन फैसलों और आदेशों पर आपत्ति दर्ज कराई, जो उनकी जानकारी के बिना लिए गए थे। ये आपत्तियां विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) प्रक्रिया से जुड़ी थीं, लेकिन आयोग की तरफ से कहा गया है कि चुनाव आयोग ने सभी फैसले बहुमत से बिना किसी विवाद के लिए हैं। आपत्ति या किसी मुद्दे पर मतभेद आम बात है। इसका फैसले पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है।

लेकिन एक पक्ष को सही मानकर अखबार के इस खुलासे के बाद कांग्रेस, सीपीआई(एम), टीएमसी, डीएमके, आप और शिवसेना (यूबीटी) जैसे दलों ने आयोग की साख पर तो सवाल उठाए ही, साथ ही आयोग की ओर से अभिषेक सिंघवी ने आरोप लगाया कि सीईसी ने चुनाव आयोग की साख और निष्ठा को नष्ट कर दिया है। कांग्रेस नेता कपिल सिब्बल ने दावा किया कि अब तक एसआईआर प्रक्रिया के तहत करीब 13 करोड़ नाम मतदाता सूची से हटाए जा चुके हैं और इस मुद्दे को रोज सुप्रीम कोर्ट में उठाया जा रहा है, लेकिन सुनवाई नहीं हो रही।विपक्ष ने आयोग की स्वतंत्रता और निष्पक्षता को लेकर व्यापक जांच की मांग दोहराई है। बहरहाल, विपक्ष के तीर भले ही मुख्य चुनाव आयुक्त की तरफ ताने जा रहे हों, लेकिन निशाने पर मोदी सरकार की विश्वसनीयता को दागदार करना ज्यादा है। वैसे यह पहला मौका नहीं है, जब मोदी सरकार विपक्ष और खासकर राहुल गांधी के निशाने पर आई हो, इसका काफी लम्बा सिलसिला है। नया दौर यह देखने में आ रहा है कि राहुल जो आरोप लगाते हैं, उसको देर-सवेर विपक्ष के अन्य नेता भी धार देने लगते हैं।

इससे पूर्व भी राहुल गांधी और अन्य विपक्षी नेताओं ने मोदी सरकार को घेरने के लिए जिन आरोपों को राजनीतिक अभियान का हिस्सा बनाया, उनकी सूची लंबी है। 2014 के बाद ह्यसूट-बूट की सरकारह, मोदी सरकार ने देश को बेच दिया वाला नैरेटिव, उद्योगपतियों के पक्ष में नीतियां बनाए जाने का आरोप, भूमि अधिग्रहण, बेरोजगारी और नोटबंदी जैसे मुद्दे कांग्रेस के प्रमुख हमलों में रहे।

नोटबंदी के समय राहुल गांधी ने इसे आर्थिक तबाही और गलत नीति बताते हुए सरकार को कठघरे में खड़ा किया। राहुल गांधी के राजनीतिक अभियान का सबसे चर्चित अध्याय राफेल सौदे से जुड़ा रहा। 2018-19 में उन्होंने आरोप लगाया कि 36 राफेल विमानों की खरीद में कीमत बढ़ाई गई, हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड को दरकिनार किया गया और अनिल अंबानी से जुड़ी कंपनी को फायदा पहुंचाया गया। उन्होंने 526 करोड़ रुपये बनाम करीब 1600 करोड़ रुपये की कीमत का तर्क भी सार्वजनिक मंचों पर रखा। इसी अभियान से ह्यचौकीदार चोर हैह नारा राष्ट्रीय राजनीति का हिस्सा बना। लेकिन दिसंबर 2018 में सुप्रीम कोर्ट ने राफेल सौदे में अदालत की निगरानी में जांच की मांग वाली याचिकाएं खारिज करते हुए कहा कि उसे खरीद प्रक्रिया, कीमत या ऑफसेट पार्टनर के चयन में हस्तक्षेप का आधार नहीं मिला।इसके बाद बेरोजगारी का मुद्दा विपक्ष के प्रमुख हथियारों में शामिल हुआ।

जिला जेल का डीजे, डीएम, एसपी ने किया निरीक्षण

स्वाती मिश्रा
कौशांबी । सोमवार को जिला जज, एसीजेएम , जिलाधिकारी कौशाम्बी अमित पाल एवं पुलिस अधीक्षक कौशाम्बी द्वारा जिला जेल का निरीक्षण किया गया।
निरीक्षण के दौरान जेल की सुरक्षा-व्यवस्था, बंदियों की व्यवस्थाओं, बैरकों, भोजन एवं अन्य आवश्यक सुविधाओं का जायजा लिया गया तथा संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए गए।
इस दौरान बंदियों से उनकी समस्याओं एवं सुविधाओं के संबंध में जानकारी प्राप्त करते हुए संबंधित अधिकारियों को नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही हेतु निर्देशित किया गया।

भारत विकास परिषद, प्रान्त स्तरीय राष्ट्रीय समूहगान प्रतियोगिता का भव्य आयोजन संपन्न

नोएडा। भारत विकास परिषद, स्वर्णिम शाखा, नोएडा के आतिथ्य में रविवार को भावराव देवरस सरस्वती विद्या मंदिर, सेक्टर-12, नोएडा में प्रान्त स्तरीय राष्ट्रीय समूहगान प्रतियोगिता का भव्य एवं सफल आयोजन किया गया।
कार्यक्रम में प्रान्त की विभिन्न शाखाओं से 26 टीमों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। सभी टीमों ने देशभक्ति एवं राष्ट्रभावना से ओत-प्रोत सुंदर एवं मनमोहक प्रस्तुतियाँ दीं, जिन्हें उपस्थित अतिथियों एवं दर्शकों ने खूब सराहा।
प्रतियोगिता में गाजियाबाद मुख्य शाखा की टीम प्रथम, दादरी शाखा की टीम द्वितीय तथा प्रेरणा शाखा, इन्द्रापुरम की टीम तृतीय स्थान पर रही। इस अवसर पर भारत विकास परिषद, स्वर्णिम शाखा के अध्यक्ष प्रमोद शर्मा ने कहा कि समूहगान प्रतियोगिता का उद्देश्य विद्यार्थियों में राष्ट्रभक्ति, संस्कार, अनुशासन एवं भारतीय संस्कृति के प्रति जागरूकता उत्पन्न करना है। उन्होंने सभी प्रतिभागी टीमों की शानदार प्रस्तुतियों की सराहना की।
शाखा सचिव महेंद्र शाह ने कार्यक्रम में उपस्थित सभी अतिथियों एवं प्रतिभागियों का स्वागत किया तथा कार्यक्रम को सफल बनाने में सहयोग देने वाले सभी सदस्यों एवं सहयोगियों के प्रति आभार व्यक्त किया। शाखा संस्कार संयोजक ओम प्रकाश बंसल ने प्रतियोगिता में भाग लेने वाली सभी शाखाओं एवं टीमों का धन्यवाद करते हुए कहा कि सभी टीमों ने अत्यंत सुंदर प्रस्तुतियाँ देकर कार्यक्रम की गरिमा बढ़ाई। कार्यक्रम में राष्ट्रीय टीम से श्री महेश बाबू गुप्ता, पवन गौतम एवं राजीव अजमानी, क्षेत्रीय टीम से राजीव गोयल एवं अमित सिंघल तथा प्रान्तीय टीम से कवित बंसल, श्रीमती मुक्ता अग्रवाल, पी. सी. गुप्ता, अंकुर अग्रवाल, राकेश मित्तल, विमल अग्रवाल, श्रीमती तरुण शर्मा, एवं एन के शर्मा सहित अनेक गणमान्य अतिथि उपस्थित रहे।

धोखाधड़ी में वांछित 50 हजार के इनामिया अभियुक्त गिरफ्तार

सबसे तेज प्रयागराज
फतेहपुर। पुलिस अधीक्षक अभिमन्यु मांगलिक के निर्देशन में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में, अपर पुलिस अधीक्षक के मार्गदर्शन तथा क्षेत्राधिकारी बिंदकी के निकट पर्यवेक्षण में जनपदीय सर्विलांस सेल फतेहपुर एवं थाना बिन्दकी पुलिस की संयुक्त टीम द्वारा अथक प्रयास एवं सतत सुरागरसी-पतारसी के फलस्वरूप ?50,000/- के इनामिया वांछित अभियुक्त निखिल विश्वकर्मा उर्फ गोलू पुत्र रामकिशोर विश्वकर्मा, उम्र करीब 29 वर्ष को गिरफ्तार किया गया।
याद दिला दे कि थाना बिन्दकी पर वादिनी श्रीमती सपना देवी पत्नी कृष्ण प्रताप सिंह निवासी ग्राम कुशारा, थाना बिन्दकी, जनपद फतेहपुर आदि की तहरीर एवं जांच आख्या के आधार पर दिनांक 22.02.2026 को मुकदमा पंजीकृत किया गया था। अभियोग में वांछित अभियुक्त निखिल विश्वकर्मा द्वारा सरकारी राशन कोटा एवं सरकारी कालोनी आवंटित कराने का प्रलोभन देकर वादिनी एवं अन्य महिलाओं से धनराशि प्राप्त करने तथा फर्जी/कूटरचित दस्तावेज उपलब्ध कराने का आरोप है। जांच के दौरान आवेदिकागण द्वारा उपलब्ध कराये गये लेन-देन संबंधी साक्ष्यों एवं जिला पूर्ति निरीक्षक की आख्या से आरोपों की प्रथम दृष्टया पुष्टि होने पर अभियोग पंजीकृत किया गया। अभियुक्त निखिल विश्वकर्मा लगातार वांछित चल रहा था। अभियुक्त की गिरफ्तारी हेतु पूर्व में पुलिस अधीक्षक अभिमन्यु मांगलिक द्वारा ?25,000/- का पुरस्कार घोषित किया गया था, जिसे बाद में पुलिस महानिरीक्षक, प्रयागराज परिक्षेत्र, प्रयागराज द्वारा बढ़ाकर ?50,000/- कर दिया गया।

मुकदमों और लेन-देन की निष्पक्ष जांच की मांग : धीरज चड्ढा

कानपुर।
कथित वसूली के लिए दबाव बनाने और अलग-अलग लोगों से जुड़े मुकदमों की निष्पक्ष जांच की मांग करते हुए रविवार को सनातन मठ मंदिर रक्षा समिति के समाजसेवी धीरज चड्ढा ने प्रेस वार्ता की। इस दौरान उन्होंने तमाम प्रकार के आरोप लगाएं।
उन्होंने बताया कि पुलिस आयुक्त से शिकायत में अधिवक्ता अमित कुमार गुप्ता, आशीष शुक्ला उर्फ बिल्लू एडवोकेट, विनोद गुप्ता उर्फ बिन्नू, जितेंद्र वाजपेई उर्फ जीतू पार्षद परमट और नवनीत मिश्रा के नाम का उल्लेख किया गया है। धीरज चड्ढा ने आरोप लगाया कि उनके खिलाफ करीब चार लाख रुपये को लेकर दबाव बनाया गया। उन्होंने शिकायत के साथ पुलिस को कुछ दस्तावेज भी उपलब्ध कराए हैं।
धीरज ने शिकायत में धारा 138 एनआई एक्ट के तहत दाखिल किए गए कुछ परिवादों का भी उल्लेख किया है। उनके अनुसार, एम. शौएब आलम से जुड़े वर्ष 2023 के मामले में करीब दो लाख रुपये और दो लाख रुपये के चेक से संबंधित विवाद का जिक्र है। वहीं, एम. फैसल से जुड़े वर्ष 2025 के मामले में आठ लाख रुपये के चेक के आधार पर परिवाद दाखिल किए जाने की बात कही गई है।
इसके अलावा कुंदन मिश्रा से जुड़े वर्ष 2024 के मामले में दो लाख रुपये की रकम और चेक से संबंधित विवाद का भी शिकायती पत्र में उल्लेख है। धीरज चड्ढा ने आरोप लगाया कि इन मामलों में आशीष शुक्ला उर्फ बिल्लू और विनोद गुप्ता उर्फ बिन्नू की भूमिका की भी जांच की जानी चाहिए। उन्होंने संबंधित लोगों पर गंभीर आरोप लगाते हुए पुलिस से पूरे मामले की जांच की मांग की है।
धीरज चड्ढा ने पुलिस आयुक्त से संबंधित परिवादों, बयानों और दस्तावेजों की निष्पक्ष जांच कराने का अनुरोध किया है। उन्होंने कहा कि जांच के जरिए वास्तविक लेन-देन और मुकदमे दाखिल किए जाने के आधार की स्थिति स्पष्ट की जानी चाहिए। शिकायतकर्ता ने मामले में तथ्यों के आधार पर कार्रवाई की मांग की है।

काशी में एयर शो की तैयारियां तेज, बाबतपुर एयरपोर्ट पर खड़े होंगे 20 फाइटर प्लेन; गंगा घाट पर बनेगा ATC टावर

वाराणसी।
काशी का आसमान 22, 23 व 25 अक्टूबर को भारतीय वायुसेना के लड़ाकू विमानों की गर्जना से गूंजने वाला है। भव्य एयर शो को लेकर तैयारियां जोर-शोर से चल रही हैं। इस आयोजन के दौरान वायुसेना के 20 फाइटर प्लेन वाराणसी एयरपोर्ट पर पार्क किए जाएंगे। इसके लिए एयरपोर्ट पर नया वे (एप्रन) बन रहा है।
वर्तमान में एयरपोर्ट पर 10 पार्किंग वे मौजूद हैं। साथ ही तेजी से चल रहे निर्माण कार्य के तहत अगले

सप्ताह तक 17 नए पार्किंग बे बनकर तैयार हो जाएंगे। इसके बाद कुल पार्किंग वे की संख्या बढ़कर 27 हो जाएगी।

डमी ट्रस्टी खोलेंगे जौहर ट्रस्ट की करतूतों की पोल; आजम खां और परिवार पर होंगे खुलासे

लखनऊ
जौहर ट्रस्ट के पदाधिकारियों को ईडी ने इस हफ्ते तलब किया है, डमी ट्रस्टी जौहर ट्रस्ट की करतूतों की पोल खोलेंगे। पदाधिकारियों में शहरयार खान भी शामिल हैं। शहरयार खान ने बयान दिया था कि ट्रस्ट में वह महज डमी था।
पूर्व मंत्री आजम खां और उनके परिजनों की जौहर ट्रस्ट की प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) जांच में जल्द कुछ अहम खुलासे होंगे। ईडी ने इस सप्ताह ट्रस्ट के पदाधिकारियों को तलब किया है, जिनमें शहरयार खान समेत कई डमी ट्रस्टी भी शामिल हैं।
अब इनसे पूछताछ में जौहर ट्रस्ट की करतूतों का पता लगाया जाएगा। बता दें कि चौधरी शहरयार सलीम ने इससे पहले आयकर विभाग को दिए बयान में ट्रस्ट की गतिविधियों के बारे में कई खुलासे किए थे।
दरअसल, शहरयार खान ने बयान दिया था कि ट्रस्ट में वह महज डमी था। जौहर विश्वविद्यालय के कुलपति के चयन के लिए आयोजित बैठक में उनसे केवल दस्तखत लेकर जाने दिया गया था। ट्रस्ट के फैसलों में उनकी कोई भूमिका नहीं रहती थी।

ट्रस्ट को आजम खान और उनके परिवार के सदस्य ही कंट्रोल और मैनेज करते थे। जांच में यह भी सामने आया है कि रामपुर की कई निजी कंस्ट्रक्शन फर्मों को सरकारी ठेके दिलाए गए और बाद में सरकारी बजट का इस्तेमाल ट्रस्ट की संपत्तियां बनाने में हुआ।

आजम के परिजनों की भूमिका पर होगी पूछताछ
जौहर एसोसिएट्स और सीके एसोसिएट्स ने सरकारी अनुबंध से मिली करीब 86 करोड़ रुपये के सरकारी बजट का दुरुपयोग किया। अब ट्रस्ट के पदाधिकारियों से सरकारी विभागों के बजट का दुरुपयोग, सरकारी भूमि पर कब्जे, मस्जिद और सपा कार्यालय का निर्माण, फर्जी दानदाताओं के साथ खाते में जमा की गई करोड़ों रुपये की नगदी के बारे में गहनता से पूछताछ की जाएगी। साथ ही ट्रस्ट में शामिल आजम के परिजनों की भूमिका की गहनता से पूछताछ की जाएगी।

कई फर्मों की मिली जानकारी
वहीं दूसरी ओर आजम खां के मंत्री रहने के दौरान जल निगम के अधिकतर सरकारी ठेके पाने वाली एक दर्जन से अधिक फर्मों की जानकारी ईडी को मिल गई है। अब इन फर्मों के संचालकों को तलब किया जाना है, जिनमें एक मुख्य नाम आफताब का है।
आरोप है कि आफताब की कई फर्मों को ही प्रचार-प्रसार का अधिकांश कार्य दिया गया। अब ईडी यह पता लगाएगा कि इसके बदले में जौहर ट्रस्ट को कितना दान दिया गया था।

कजरी महोत्सव में लोक संस्कृति के रंगों से सराबोर हुई पीतलनगरी

सेवा संकल्प अभियान एवं विश्व पर्यटन दिवस के अवसर पर पंचायत भवन मुरादाबाद में हुआ भव्य लोक सांस्कृतिक कार्यक्रम

मुरादाबाद।
सेवा संकल्प अभियान एवं विश्व पर्यटन दिवस के अवसर पर रविवार को पंचायत भवन, मुरादाबाद में संस्कृति विभाग, उत्तर प्रदेश, जिला प्रशासन तथा वृंदावन शोध संस्थान, वृंदावन के संयुक्त तत्वावधान में भव्य कजरी महोत्सव का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में लोकगीत एवं लोकनृत्य की मनमोहक प्रस्तुतियों ने दर्शकों को भारतीय लोक संस्कृति और संगीत की समृद्ध

परंपरा से रूबरू कराया।
कार्यक्रम का शुभारंभ मुख्य अतिथि सदस्य विधान परिषद डॉ. जयपाल सिंह ह्यव्यस्तह्न, महापौर विनोद अग्रवाल, लखनऊ से पधारीं लोकगायिका संजोली पांडेय तथा मथुरा की सुप्रसिद्ध लोकगायिका माधुरी शर्मा ने दीप प्रज्ज्वलित कर किया।
कार्यक्रम के प्रारंभ में वृंदावन शोध संस्थान, मथुरा के प्रशासनिक अधिकारी श्री रजत शुक्ला ने स्वागत भाषण प्रस्तुत किया। पर्यटन अधिकारी प्रदीप टम्टा ने अतिथियों का परिचय कराते हुए विश्व पर्यटन दिवस-2026 की थीम की जानकारी दी तथा मुरादाबाद के प्रमुख पर्यटन स्थलों एवं उनकी विशेषताओं से दर्शकों को अवगत कराया।
सांस्कृतिक प्रस्तुतियों का शुभारंभ नमिता अग्रवाल के कजरी गायन से हुआ। इसके पश्चात प्रतिमा वर्मा, निधि एवं रुचि की टीम ने कजरी गायन एवं नृत्य की मनमोहक प्रस्तुति दी।

चुनाव आयोग की कथित अनियमितताओं और ज्ञानेश के इस्तीफे की मांग को लेकर कांग्रेसियों का विशाल प्रदर्शन,फूंका पुतला..

ब्यूरो चीफ
सबसे तेज प्रयागराज
कौशाम्बी। सोमवार कांग्रेसियों ने जिलाध्यक्ष गौरव पाण्डेय के नेतृत्व में एक विशाल विरोध प्रदर्शन के माध्यम से चुनाव आयोग व ज्ञानेश कुमार की इस्तीफे की मांग को लेकर विशाल प्रदर्शन किया और जिलाधिकारी के माध्यम से महामहिम राष्ट्रपति को सम्बोधित ज्ञापन सौंपा और मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार का पुतला फूंका इस दौरान जिलाध्यक्ष गौरव पाण्डेय ने कहा कि चुनाव आयोग में मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के सहयोगियों ने खुद कई बार शिकायत

की ज्ञानेश कुमार अपने मन का कार्य कर रहें है बिना हमारे राय के हमारे नेता राहुल गांधी ने कई बार चुनाव आयोग में धांधली के बारे में जनता को चेताया लेकिन भाजपा संरक्षित ज्ञानेश कुमार ने वही किया जो भाजपा ने चाहा । चुनाव आयोग के भीतर ही वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा बार-बार गलत फैसलों पर नोट लिखना संविधान और लोकतंत्र के लिए बड़ा खतरा है। उन्होंने आरोप लगाया कि मतदाताओं के नाम काटने का "यूपी मॉडल" बिहार और पश्चिम बंगाल में भी लागू किया गया है। उन्होंने मांग की कि भविष्य के कोई भी चुनाव ज्ञानेश कुमार की देखरेख में नहीं होने चाहिए। और इनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए।
आज हमने प्रदर्शन के माध्यम से सरकार और चुनाव आयोग को चेताया कि अगर इन अनियमितताओं में सुधार और ज्ञानेश कुमार का इस्तीफा नहीं होता तो हम सब इससे भी बड़ा प्रदर्शन करने को बाध्य होंगे।....
प्रदर्शन में मुख्य रूप से प्रभारी राजेश साहनी ,पूर्व प्रदेश सचिव रामबहादुर त्रिपाठी,वरिष्ठ जिला उपाध्यक्ष श्याम मूर्ति तिवारी,राजेंद्र त्रिपाठी,जिला उपाध्यक्ष राम सूरत रैदास, ब्लाक अध्यक्ष नेवादा रावेंद्र यादव, रजनीश पाण्डेय,रमेश यादव,ब्लाक अध्यक्ष मंझनपुर प्रदीप सिंह पटेल,नगर अध्यक्ष मंझनपुर संगीता कोरी,मूरतगंज ब्लॉक अध्यक्ष राज बहादुर,जिला सचिव मोहम्मद नोमान,जिला उपाध्यक्ष उदय यादव,नैय्यर रिजवी,कौशलेश द्विवेदी,आशीष मिश्रा पप्पू,जिला महासचिव श्याम सिंह भदौरिया,प्रियांशु त्रिपाठी,मोहम्मद फरमान,कालका सिंह, आयूष यादव प्रभारी कार्यालय हेमन्त रावत,सोसल मीडिया जिलाध्यक्ष सचिन पाण्डेय,नगर अध्यक्ष चरवा निक्की पाण्डेय,आबिदा बेगम,विकास पासी,ब्लाक अध्यक्ष कड़ा रफीक अहमद,विवेक मिश्रा,नगर अध्यक्ष अझुवा विजय यादव,दुर्गेश यादव, मण्डल अध्यक्ष शिवलेश मिश्रा, कैलाश केसरवानी,महेंद्र मिश्रा,मीना देवी,जलसा देवी,तेजा देवी,लालती देवी,महारानी देवी,देवकली देवी,शाहनवाज अहमद,राममिलन कोरी,सुनील गौतम, फहीमुद्दीन,शिवबाबू पाल, कौशल्या देवी, सुशीला देवी,तारा देवी,कमलेश कुमार,अंकुर सिंह, ओम प्रकाश पंडा,चंद्र कुमार, करन कुशवाहा,नीलम देवी,राजुलयादव, इंद्रपाल रैदास, बिफई लाल,अमृत लाल,नुरैन खान, झुन्नू लाल,तिलक राज, रामकिशन,संदीप कुमार,अवधेश कुमार,महेश मिश्रा, मानसिंह पासी, प्रकाश मिश्रा ,सुखलाल यादव,राजकुमार,अनुज पासी, मनोज पासी,अनिल पासी,बबलू सिंह,गोकुल प्रसाद,रामू प्रजापति,रवि यादव, राधे श्याम यादव,सहित हजारों की संख्या में कार्यकर्ता मौजूद रहे।

यूपी: चार दिन के बाद प्रदेश में थमी बारिश, रविवार को मकान-पेड़ गिरने से 33 मौतें; यहां आज भी स्कूल रहेंगे बंद

लखनऊ
यूपी में चार दिन बाद रविवार दोपहर से बारिश बंद हुई। बारिश की वजह से प्रदेश में 33 मौतें हुईं। यूपी में पारा सामान्य से नीचे गिर गया है।
प्रदेश में बृहस्पतिवार शाम से जारी भारी बारिश से रविवार को भी कई जगह मकान-दीवार, पेड़ गिरने से 33 लोगों की मौत हो गई। शनिवार को बारिश के बीच हुए हादसों में प्रदेश में 58 लोगों की मौत हुई थी। रविवार को भी बारिश से जनजीवन बुरी तरह प्रभावित रहा। जलभराव व ठप हुई बिजली आपूर्ति ने लोगों के लिए संकट खड़ा कर दिया। नदियों का जलस्तर तेजी से बढ़ने से तटवर्ती इलाकों पर बाढ़ का खतरा गहरा गया। रविवार को बारिश थमने

के साथ मौसम विभाग ने सोमवार के लिए कहीं भी भारी बारिश की चेतावनी जारी नहीं की है।

फरुर्खाबाद में सर्वाधिक बारिश और तापमान में गिरावट
प्रदेश में रविवार को फरुर्खाबाद में सर्वाधिक 320 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई। लगातार बारिश के कारण दिन का तापमान सामान्य से काफी नीचे रहा। उरई 18.4 डिग्री सेल्सियस के साथ प्रदेश का सबसे ठंडा रहा। बरेली, मुजफ्फरनगर और मुरादाबाद में अधिकतम तापमान सामान्य से नौ से 10 डिग्री सेल्सियस तक नीचे रहा। एटा में 36 घंटे लगातार बारिश से छह मकान भरभराकर ढह गए।

विभिन्न जिलों में हुए हादसे
रविवार को अवध के अलग-अलग जिलों में हुए हादसों में 11 लोगों की मौत हो गई। सीतापुर में तीन, बलरामपुर में तीन तथा श्रावस्ती, बहराइच, अमेठी, बाराबंकी और गोंडा में एक-एक व्यक्ति की जान गई।
मकान गिरने से रामपुर में दो और संभल में एक की मौत हुई है। रामपुर में बारिश का पानी निकालते समय करंट लगने से एक महिला की जान चली गई।

केन नदी पुल पर महिला ने चार बच्चों के साथ उठाया खतरनाक कदम

बांदा।
उत्तर प्रदेश के जनपद बांदा में केन नदी पुल पर एक महिला अपने चार बच्चों के साथ नदी की ओर आत्महत्या करने के लिए जाने लगी। स्थिति पर नजर पड़ते ही यातायात पुलिसकर्मियों ने तत्काल सक्रियता दिखाते हुए महिला और उसके चारों बच्चों को सुरक्षित बचा लिया। पुलिसकर्मियों की तत्परता और संवेदनशीलता से पांच जिंदगियां सुरक्षित बच गईं। इसके बाद महिला और बच्चों को समझाकर सुरक्षित रूप से कोतवाली नगर पुलिस के सुपुर्द कर दिया गया।
प्रभारी निरीक्षक यातायात महेन्द्र प्रताप सिंह के मुताबिक वह रविवार को अपनी टीम के साथ शहर में यातायात व्यवस्था का निरीक्षण कर रहे थे। इसी दौरान केन नदी पुल पर महिला और उसके चार बच्चों को

देखकर पुलिसकर्मियों ने तत्काल हस्तक्षेप किया। स्थिति की गंभीरता को समझते हुए प्रभारी यातायात ने अपने हमराह, चालक तथा मौके पर मौजूद आरक्षी पवन कुशवाहा के साथ मिलकर महिला और बच्चों को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया।
पुलिसकर्मियों ने महिला को धैर्यपूर्वक समझाया और मामले की जानकारी उच्चाधिकारियों को दी। बाद में महिला और उसके चारों बच्चों को सुरक्षित रूप से कोतवाली नगर पुलिस के सुपुर्द कर दिया गया। इस सराहनीय कार्य में प्रभारी निरीक्षक यातायात महेन्द्र प्रताप सिंह, मुख्य आरक्षी यातायात कृष्ण प्रताप, आरक्षी यातायात सरवर आलम, आरक्षी यातायात आशुतोष राजपूत तथा आरक्षी पवन कुशवाहा की महत्वपूर्ण भूमिका रही।

भगवान की शरणागति ही जीव का वास्तविक घर, गोसेवा से श्रीकृष्ण की प्राप्ति संभव : स्वामी राजेंद्रदास

गोरखपुर।
युगपुरुष ब्रह्मलीन महंत दिग्विजयनाथ की 57वीं तथा राष्ट्रसंत ब्रह्मलीन महंत अवेद्यनाथ की 12वीं पुण्यतिथि के अवसर पर आयोजित साप्ताहिक श्रीमद्भागवत कथा के पांचवें दिन कथा व्यास वृंदावन से पधारे मलूक पीठाधीश्वर जगद्गुरु स्वामी राजेंद्रदास देवाचार्य ने प्रतिदिन के नियम के अनुसार गोस्वामी तुलसीदास कृत गीतावली के पद का गान किया। इसके बाद उन्होंने लव-कुश के नामकरण संस्कार और गुरुकुल शिक्षा का वर्णन किया।

कथा व्यास ने कहा कि कुलीनता जीवन का सद्गुण है। अच्छे माता-पिता और कुलीन वंश में ही महापुरुष पैदा होते हैं। उन्होंने कहा कि सनातन धर्म की रक्षा के लिए विवाह और पारिवारिक संस्कारों की परंपराओं को महत्व देना चाहिए। उन्होंने कहा कि पिंडदान आदि श्रद्धा की प्रक्रियाओं का भी अपना धार्मिक महत्व है।

उन्होंने कहा कि गुलामी के समय क्रांति का बीज गोरक्षा था, लेकिन आजादी के 80 वर्ष बाद भी भारत गोवध से पूरी तरह मुक्त नहीं हो पाया है। जीवन में गुरु-कृपा का विशेष महत्व है। सच्चे गुरु की पूर्ण कृपा मिलने पर शिष्य का कल्याण सुनिश्चित होता है।

उन्होंने कहा कि ब्रज मंडल में भगवान के आगमन के बाद वहां लक्ष्मी का नित्य निवास होने लगा। गोपियां कहती हैं कि ब्रज बैकुंठ से भी अधिक सुंदर हो गया। भगवान की लीला में भक्तों को विस्मित या शंकित होने के बजाय पूर्ण विश्वास रखना चाहिए, क्योंकि ईश्वर सर्वशक्तिमान हैं। धर्मनिष्ठ और सदाचारी संतों का दर्शन मात्र भी जीव के कल्याण का कारण बनता है।

कथा व्यास ने कहा कि जीवन में विपरीत परिस्थितियां आने पर व्याकुल होने के बजाय धैर्य रखना चाहिए। भगवान के प्रति विश्वास की कमी के कारण मनुष्य परेशान रहता है। उन्होंने कहा कि भगवान की शरणागति ही हमारा लक्ष्य है। सभी जीवों का वास्तविक घर भगवान की शरणागति है। जब तक यह प्राप्त नहीं होती, तब तक जीवन का प्रवास जारी रहता है।

गोसेवा से श्रीकृष्ण की प्राप्ति

स्वामी राजेंद्रदास ने कहा कि गोविंदा की शरणागति करने का सामर्थ्य गौ माता में है। गोसेवा करने पर उनकी कृपा से भगवान का साक्षात दर्शन हो जाता है। भगवान श्रीकृष्ण भी गोसेवा की कामना से ब्रज में आए और प्रत्यक्ष गोसेवा का सौभाग्य प्राप्त किया। उन्होंने कहा कि हम श्रीकृष्ण को पाना चाहते हैं और श्रीकृष्ण गाय को पाना चाहते हैं। इसलिए गाय की सेवा करने से श्रीकृष्ण की प्राप्ति संभव है। गाय को पशु नहीं मानना चाहिए। उन्होंने कहा कि गोमाता का गोबर भी सामान्य पदार्थ नहीं, बल्कि कल्याणकारी और पवित्र है।

रासलीला का वर्णन करते हुए उन्होंने कहा कि भगवान अपनी योगमाया के प्रभाव से अनंत गोपियों के साथ रासलीला करते हैं। जितनी गोपियां हैं, उतने ही कृष्ण हैं।

उन्होंने कहा कि जिन गोरक्षनाथ की तपस्थली में कथा हो रही है, वहां भगवान गोरखनाथ भी गोमाता के गोबर से प्रकट होने की मान्यता है। गोबर को उन्होंने अत्यंत पवित्र बताते हुए कहा कि गाय कभी किसी का उधार नहीं रखती और गोसेवा का फल प्रत्यक्ष मिलता है।

भगवान ही हमारे रक्षक और शरण

कथा व्यास ने कहा कि भगवान ही हमारे रक्षक हैं और भगवान ही हमारी शरण हैं। उनके भजन और कथा-श्रवण से जीवन भयमुक्त और सुखमय होता है। वह जिसे अपना बना लेते हैं, उसका कल्याण किए बिना नहीं छोड़ते।

मशरूम उत्पादन से युवाओं और किसानों के लिए रोजगार के अवसर बढ़ेंगे : डॉ. खलील खान

कानपुर।
मशरूम उत्पादन की तकनीक और इससे जुड़े रोजगार के अवसरों की जानकारी प्रशिक्षणार्थियों को दी गई, ताकि वे इसका लाभ उठाकर स्वरोजगार की दिशा में आगे बढ़ सकें। यह बातें रविवार को चंद्रशेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिकी (सीएसए) विश्वविद्यालय के मीडिया प्रभारी डॉ. खलील खान ने छह दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम के समापन पर कही।

सीएसए के पादप रोग विज्ञान विभाग की ओर से आयोजित छह दिवसीय मशरूम उत्पादन प्रशिक्षण कार्यक्रम का समापन हो गया। प्रशिक्षण में प्रदेश के 92 प्रशिक्षणार्थियों ने हिस्सा लिया, जिसमें नौ महिलाएं भी शामिल रहीं।

छह दिनों तक चले प्रशिक्षण में विश्वविद्यालय के शिक्षकों ने मशरूम उत्पादन से जुड़ी विभिन्न तकनीकों की जानकारी दी। विभागाध्यक्ष डॉ. मुकेश श्रीवास्तव, खाद्य विज्ञान एवं पोषण विभाग की प्राध्यापक डॉ. विनीता सिंह, डॉ. सेंथिलकुमार एस., डॉ. शिवानी चौधरी और कीट विज्ञान विभाग की डॉ. नाहिदा ए. खान ने प्रशिक्षणार्थियों को मशरूम का इतिहास, श्वेत बटन मशरूम और ढिंगरी मशरूम के उत्पादन की तकनीक समझाई।

इसके साथ ही मशरूम से बनने वाले मूल्यवर्धित उत्पाद और व्यंजन तैयार करने, फसलों में होने वाली बीमारियों व कीटों से बचाव, मशरूम फार्म की संरचना और खेती के दौरान आने वाली समस्याओं के समाधान की जानकारी दी गई।

जिला उद्यान अधिकारी उमेश चंद्र, भारत एग्रीटेक के संस्थापक एवं निदेशक डॉ. धनंजय सिंह और एमएसएमई से जुड़े शिवम त्रिपाठी ने मशरूम उत्पादन के क्षेत्र में संचालित सरकारी योजनाओं, सब्सिडी और ऋण की जानकारी दी।

प्रशिक्षणार्थियों को प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यम औपचारिकीकरण योजना, स्पॉन उत्पादन और मशरूम फार्म तैयार करने के संबंध में भी बताया गया। प्रशिक्षण के अंतिम दिन प्रशिक्षणार्थियों की शंकाओं का समाधान किया गया।

लोगों का प्यार कलाकार की सबसे बड़ी ताकत : रोहिताश गौड़

कानपुर।
जब लोगों का प्यार और अपनापन मिलता है तो कलाकार के लिए इससे बड़ी खुशी कोई और नहीं होती। दर्शकों का स्नेह ही हमें लगातार बेहतर काम करने की प्रेरणा देता है। लोगों के बीच आकर उनसे मिलना हमेशा खास अनुभव रहता है। यह बातें रविवार को टीवी सीरियल भाभी जी घर पर हैं में तिवारी जी का किरदार निभाने वाले अभिनेता रोहिताश गौड़ ने रविवार को कानपुर में कहीं।

रोहिताश गौड़ के शहर पहुंचने पर प्रशंसकों में खासा उत्साह देखने को मिला। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में लोग उन्हें देखने और उनसे मिलने पहुंचे। उन्होंने लोगों से मुलाकात की और उनके साथ तस्वीरें भी खिंचवाईं। अभिनेता ने कहा कि कानपुर के लोगों का उत्साह और अपनापन हमेशा यादगार रहता है।

कार्यक्रम में उन्होंने लोगों के साथ प्रसाद भी ग्रहण किया और आयोजन में सहभागिता की।

केशवपुरम, कल्याणपुर स्थित मां शारदा मेडिकल स्टोर ने अपने सफर के 21 वर्ष पूरे किए हैं। इस अवसर पर स्टोर की ओर से विशेष प्रसाद वितरण समारोह आयोजित किया गया। इस दौरान स्टोर के संचालक सुशील पाल और अजीत पाल ने बताया कि इन वर्षों में दवाओं की उपलब्धता के साथ मरीजों और आम नागरिकों को जरूरत के समय उचित मार्गदर्शन और सेवा देने का प्रयास किया गया। समारोह में क्षेत्रीय नागरिकों, ग्राहकों और शुभचिंतकों ने बड़ी संख्या में सहभागिता की।

कानपुर नगर सांसद रमेश अवस्थी ने कहा कि 21 वर्षों तक लगातार लोगों से जुड़े रहना और अपनी सेवाएं देना सराहनीय है। उन्होंने वर्षगांठ की शुभकामनाएं देते हुए कहा कि संस्थानों का लोगों के साथ बना विश्वास ही उनकी सबसे बड़ी पूंजी होता है। उन्होंने भविष्य में भी इसी तरह सेवा कार्य जारी रखने की शुभकामनाएं दीं।

कार्यक्रम में कल्याणपुर विधायक नीलिमा कटियार समेत कई गणमान्य लोग मौजूद रहे। सुशील पाल, अजीत पाल और सुरजीत पाल ने अतिथियों का स्वागत किया। क्षेत्रीय नागरिकों और ग्राहकों ने भी कार्यक्रम में हिस्सा लिया।

अशोक सिंघल ने हिंदू समाज के संगठन और सांस्कृतिक पुनर्जागरण का अभियान चलाया : महंत यमुना पुरी

प्रयागराज।
अशोक सिंघल राम मंदिर आंदोलन और समाज निर्माण को हिंदू समाज के संगठन तथा सांस्कृतिक पुनर्जागरण का अभियान मानते थे। भगवान श्रीराम भारतीय सांस्कृतिक चेतना के प्रतीक हैं। अशोक सिंघल ने जाति, पंथ, संप्रदाय और क्षेत्र की सीमाओं से ऊपर उठकर हिंदू समाज को एकजुट करने का संकल्प लिया और अपने जीवनकाल में उसे पूरा करने के लिए निरंतर प्रयास किया। संत समाज के समन्वय में भी उनका महत्वपूर्ण योगदान रहा। उन्होंने विभिन्न अखाड़ों, मतों और संप्रदायों को एक मंच पर लाने का कार्य किया। यह बात महा निवार्णी अखाड़े के महंत यमुना पुरी महाराज ने रविवार को कही।

विश्व हिंदू परिषद (विहिप) काशी प्रांत की ओर से पूज्य स्वामी वासुदेवानंद सरस्वती के आश्रम में प्रांत मार्गदर्शक मंडल की बैठक आयोजित की गई। अशोक सिंघल की जयंती के 100 वर्ष पूर्ण होने के अवसर पर आयोजित बैठक में संतों ने उनके जीवन और कार्यों को याद किया।

महंत यमुना पुरी ने कहा कि 27 सितंबर को अशोक सिंघल की जयंती केवल स्मरण का अवसर नहीं, बल्कि भगवान श्रीराम के आदर्श, मयार्दा, कर्तव्य, सेवा, त्याग, समरसता और लोकमंगल को जीवन में उतारने की प्रेरणा लेने का दिन है।

नया उदासीन अखाड़े के जगतार मुनि ने कहा कि अशोक सिंघल जीवनभर हिंदू समाज की एकता के लिए संकल्पित रहे।

यूपी के हमीरपुर में 40 घंटे की बारिश से स्वामी ब्रह्मानंद बांध का जलस्तर बढ़ा

9 गेट खोलकर छोड़ा पानी, विरमा नदी उफनाई

हमीरपुर।
उत्तर प्रदेश के हमीरपुर जिले में लगातार 40 घंटे से हुई बारिश से स्वामी ब्रह्मानंद बांध का जलस्तर बढ़ गया है। रविवार को बांध के नौ गेट फिर से खोले गए हैं, जिससे विरमा नदी का जलस्तर बढ़ गया है।

विकास खंड मुस्करा के गुंदेला गांव से 5 किलोमीटर दूर विरमा नदी पर स्वामी ब्रह्मानंद बांध बना हुआ है। सफाई को लेकर बांध को जून माह में पूरी तरह खाली कर दिया गया था, लेकिन इस बार हुई अतिवृष्टि से विरमा नदी का जलस्तर पिछले एक माह से कम होने का नाम नहीं ले रहा है। इससे विरमा नदी पर बना स्वामी ब्रह्मानंद बांध का जलस्तर अपने उच्चतम स्तर को छू रहा है।

दो दिन पहले बांध के नौ गेटों से करीब 80 हजार क्यूसेक पानी छोड़ा गया था। बारिश के बाद फिर से जलस्तर बढ़ने पर 9 गेटों से करीब 40 हजार क्यूसेक पानी विरमा नदी में छोड़ा जा रहा है। अवर अभियंता सपना कटियार ने रविवार को बताया कि अभी बांध का जलस्तर बढ़ा हुआ है, इसलिए विरमा नदी में पानी छोड़ा जा रहा है। नदी में पानी बढ़ने से लोगों को विरमा नदी से दूर रहने को कहा गया है।

अमेठी : तमंचा सटाकर बीसी संचालक से लूट का प्रयास, एक आरोपी गिरफ्तार

अमेठी।
शिवरतनगंज थाना क्षेत्र अंतर्गत कस्बे में रविवार की देर शाम बैंक ऑफ बड़ौदा के बीसी फ्रेंचाइजी संचालक से तमंचे के बल पर लूट के प्रयास किया गया। शोर सुनकर जुटे ग्रामीणों ने एक आरोपित को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया, जबकि उसके दो साथी फरार हो गए।

शिवरतनगंज निवासी बीसी फ्रेंचाइजी संचालक व पूर्व जिला पंचायत सदस्य अनीता साहू के पति डॉ. सत्य प्रकाश साहू के घर में ही फ्रेंचाइजी संचालित होती है। रविवार शाम करीब 7:30 बजे तीन युवक पहुंचे और तमंचा सटाकर लूट का प्रयास किया। शोर मचने पर आसपास के दुकानदार और ग्रामीण पहुंच गए। भीड़ जुटती देख दो आरोपित भाग निकले, जबकि एक आरोपित को ग्रामीणों ने घेरकर पकड़ लिया।

पुलिस आरोपित को हिरासत में लेकर थाने ले जाने लगी तो ग्रामीणों ने आक्रोश जताते हुए पुलिस वाहन रोकने का प्रयास किया। कुछ ग्रामीण वाहन के आगे लेट गए और पकड़े गए आरोपित को पुलिस के कब्जे से छुड़ाकर पीटने की कोशिश की। इस दौरान पुलिस और ग्रामीणों के बीच धक्का-मुक्की भी हुई। ग्रामीण फरार दोनों आरोपितों की तत्काल गिरफ्तारी की मांग पर अड़े रहे। सूचना पर सीओ तिलोई दिनेश मिश्रा मौके पर पहुंचे। उनके सामने भी ग्रामीणों ने पुलिस कार्रवाई पर नाराजगी जताई। काफी देर तक मौके पर तनाव की स्थिति बनी रही।

वाराणसी में इस बार अंगकोर वाट की अनुकृति में सजेगा हथुआ मार्केट का दुगार्पूजा पंडाल

वाराणसी।
उत्तर प्रदेश के वाराणसी में दुगार्पूजा की तैयारियां जोर-शोर से चल रही हैं। शहर के विभिन्न पूजा पंडालों को भव्य और आकर्षक रूप देने के लिए कारीगर दिन-रात जुटे हुए हैं। इसी क्रम में शहर के प्रसिद्ध हथुआ मार्केट स्थित प्रीमियर बॉयज क्लब की दुगार्पूजा इस बार विशेष आकर्षण का केंद्र बनने जा रही है। क्लब के 51वें वर्ष में पंडाल को कंबोडिया के विश्वप्रसिद्ध प्राचीन मंदिर अंगकोर वाट की स्थापत्य कला की अनुकृति के रूप में तैयार किया जा रहा है।

पंडाल में अंगकोर वाट के विशाल शिखरों, विशिष्ट प्रवेश संरचना और बारीक शिल्पकारी की झलक देखने को मिलेगी। आयोजकों के अनुसार, वाराणसी में पहली बार किसी विदेशी मंदिर की स्थापत्य शैली को दुगार्पूजा पंडाल की थीम बनाया जा रहा है। भव्य प्रकाश-सज्जा के बीच पंडाल श्रद्धालुओं के लिए खास आकर्षण का केंद्र होगा। पंडाल की ऊंचाई करीब 60 फीट और चौड़ाई 55 फीट होगी। इसमें तीन शिखर बनाए जा रहे हैं। प्रवेश द्वार पर छह-छह फीट ऊंचे दो आकर्षक शेर भी तैयार किए जा रहे हैं। पंडाल में अंगकोर वाट की स्थापत्य कला के साथ उसकी विशिष्ट शिल्प शैली और आभा को उकेरने का प्रयास किया जा रहा है।

मुरादाबाद में कक्षा 12 तक के सभी शैक्षिक संस्थानों में कल रहेगा अवकाश

मुरादाबाद।
अत्यधिक बारिश के दृष्टिगत जिला अधिकारी के निदेर्शानुसार जनपद में संचालित राजकीय, परिषदीय, शासकीय, वित्तविहीन बोर्ड के कक्षा प्री प्राइमरी से कक्षा 12 तक के सभी शैक्षिक संस्थानों में 28 सितंबर (सोमवार) को अवकाश घोषित किया गया है।

जिला विद्यालय निरीक्षक रितु तोमर ने रविवार को इस संबंध में जानकारी देते हुए बताया कि, किसी विद्यालय में पूर्व से आयोग द्वारा निर्धारित परीक्षा है, तो वह यथावत रहेगी।

एआई और सेमीकंडक्टर के क्षेत्र में नई छलांग लगा रहा उत्तर प्रदेश: सुनील कुमार शर्मा

नोएडा।
यूपीज जर्नी फ्रॉम इलेक्ट्रॉनिक्स लीडर टू एआई एंड सेमीकंडक्टर पावरहाउस सत्र को संबोधित करते हुए उत्तर प्रदेश के आईटी एवं इलेक्ट्रॉनिक्स विभाग के मंत्री सुनील कुमार शर्मा ने कहा कि उत्तर प्रदेश अब केवल इलेक्ट्रॉनिक्स और मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग का बड़ा केंद्र नहीं, बल्कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई), सेमीकंडक्टर और डेटा सेंटर के क्षेत्र में भी तेजी से अपनी क्षमता विकसित कर रहा है। आने वाले समय में एआई और आईटी का कृषि तथा ग्रामीण अर्थव्यवस्था से जुड़ाव प्रदेश के विकास को नई दिशा देगा।

मंत्री ने बताया कि हाल में 52 स्टार्टअप के साथ हुई बैठक में सामने आया कि बड़ी संख्या में स्टार्टअप फूड सप्लाई से जुड़े हैं, जबकि कृषि क्षेत्र में एआई का इस्तेमाल करने वाले स्टार्टअप की संख्या अभी कम है। उन्होंने इसे एक बड़े अवसर के रूप में रेखांकित करते हुए कहा कि एआई और आईटी को कृषि आधारित उद्योगों से जोड़कर किसानों की आय और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत किया जा सकता है। प्रदेश में मक्का की खेती को इथेनॉल उत्पादन से जोड़ने के बाद किसानों को अपनी उपज का बेहतर मूल्य मिल रहा है। भविष्य में इसी तरह तकनीक आधारित समाधान कृषि क्षेत्र में व्यापक बदलाव ला सकते हैं।

उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार निवेशकों को अनुकूल वातावरण देने के लिए लगातार नीतियों में आवश्यक बदलाव कर रही है। उद्योगों की जरूरत के अनुरूप मुख्यमंत्री के स्तर से नीतिगत सुधार किए जाते हैं। निवेशकों को प्रोत्साहन राशि देने की प्रक्रिया में पारदर्शिता पर विशेष जोर है और विभाग में निवेश प्रोत्साहन से संबंधित कोई फाइल लंबित न रखने की व्यवस्था की गई है। पिछले एक वर्ष में करीब 500 से 600 करोड़ रुपये के प्रोत्साहन वितरित किए गए हैं।

सुनील कुमार शर्मा ने कहा कि उत्तर प्रदेश ने बीते वर्षों में औद्योगिक और बुनियादी ढांचे के क्षेत्र में बड़ा परिवर्तन देखा है। एक्सप्रेसवे, इलेक्ट्रॉनिक्स और मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग तथा एयर कनेक्टिविटी के क्षेत्र में यूपी देश के अग्रणी राज्यों में शामिल है। उन्होंने रक्षा उत्पादन में हुए बदलाव का उल्लेख करते हुए कहा कि जहां कभी अवैध हथियार निर्माण की चर्चा होती थी, वहीं आज प्रदेश में ब्रह्मोस मिसाइल और एके-203 जैसी आधुनिक रक्षा प्रणालियों के निर्माण की दिशा में काम हो रहा है।

मुरादाबाद जनपद के ठाकुरद्वारा के शेरपुर पट्टी में तेंदुआ पिंजरे में कैद

मुरादाबाद।
उत्तर प्रदेश के जनपद मुरादाबाद में ठाकुरद्वारा तहसील के ग्राम शेरपुर पट्टी में सोमवार की सुबह एक तेंदुआ ट्रैप केज के माध्यम से सफलतापूर्वक रेस्क्यू किया गया है। जनपद में पिंजरे के माध्यम से रेस्क्यू किया जाने वाला यह 20वां तेंदुआ है। बीते माह ठाकुरद्वारा क्षेत्र में तेंदुए ने तीन महिलाओं समेत चार लोगों को अपना निवाला बनाया था।

जिलाधिकारी डॉ. राजेंद्र पैंसिया ने बताया कि संवेदनशीलता के दृष्टिकोण से वन विभाग की देखरेख में रेस्क्यू टीम लगातार सक्रिय है। साथ ही प्रशासनिक स्तर से पूरे संवेदनशील क्षेत्र के अंतर्गत गांवों में सतर्कता एवं जागरूकता के लिए चौपालें आयोजित की जा रही हैं। पूरे संवेदनशील क्षेत्र से अब तक 20 तेंदुओं का रेस्क्यू किया जा चुका है। वन विभाग की रेस्क्यू टीम को मुरादाबाद के तहसील ठाकुरद्वारा के ग्राम शेरपुर पट्टी में सोमवार सुबह छह बजे एक तेंदुआ पिंजरे में कैद हो जाने की सूचना मिली।उसके बाद वन विभाग की टीम ने पहुंचकर उसे अपने कब्जे में लिया। तेंदुए के पिंजरे में कैद हो जाने के बाद ग्रामीणों ने राहत की सांस ली।

जौनपुर में दुकान के सामने सो रहे व्यक्ति की हत्या

जौनपुर।
उत्तर प्रदेश के जौनपुर जिले में सिकरारा थाना क्षेत्र स्थित गोदाम चौराहे के पास रविवार देर रात दुकान के सामने सो रहे एक व्यक्ति की अज्ञात लोगों ने वजनदार वस्तु से प्रहार करके हत्या कर दी। घटना की सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। फॉरेंसिक टीम ने मौके से साक्ष्य जुटाए।

मृतक की पहचान भभौरी गांव निवासी उदयराज यादव (50) के रूप में हुई है। वह प्रतिदिन की तरह गोदाम चौराहे के पास स्थित एक दुकान के सामने सोता था। मानसिक रूप से अस्वस्थ है। रविवार रात किसी समय अज्ञात व्यक्ति ने उसके सिर पर किसी भारी या ठोस वस्तु से वार कर दिया, जिससे उसकी मौत हो गई। घटना की जानकारी मिलने पर अपर पुलिस अधीक्षक (देहात) आतिश कुमार सिंह मौके पर पहुंचे और घटनास्थल का निरीक्षण किया। पुलिस ने आसपास के लोगों से पूछताछ करने के साथ ही घटना के कारणों और हमलावरों की पहचान के लिए जांच शुरू कर दी है।

परिजनों के संबंध में बताया कि मृतक चार भाइयों में से एक था। उसके एक भाई की पहले ही हत्या हो चुकी है, जबकि दूसरा भाई मुंबई में रहकर काम करता है। एक भाई काफी समय से लापता है। मृतक की मां भी कुछ दिन पहले ही कहीं से वापस लौटी हैं।

बुजुर्गों की सेवा और सम्मान से ही समाज में संवेदना मजबूत होगी : प्रो. विनय कुमार पाठक

कानपुर।
बुजुर्गों की सेवा, सम्मान और देखभाल समाज की जिम्मेदारी है और ऐसे प्रयासों से सेवा व मानवता की भावना मजबूत होती है। यह बातें रविवार को छत्रपति साहू जी महाराज विश्विद्यालय के कुलपति प्रो. विनय कुमार पाठक ने गांधी जयंती सेवा अभियान के तहत आयोजित कार्यक्रम को लेकर कही।

महात्मा गांधी की जयंती के अवसर पर 23 सितंबर से दो अक्टूबर तक चल रहे गांधी जयंती सेवा अभियान के तहत दामोदर नगर स्थित एक वृद्धाश्रम में सेवा कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस दौरान वृद्धाश्रम में रहने वाले बुजुर्गों को मिठाई, फल और बिस्कुट वितरित किए गए। कार्यक्रम का उद्देश्य बुजुर्गों के बीच अपनत्व और आत्मीयता का भाव बढ़ाने के साथ उनके प्रति सम्मान और संवेदना व्यक्त करना रहा।

कार्यक्रम में डॉ. विवेक सचान, मयंक मिश्रा और सोमिल सिंह मौजूद रहे। उन्होंने वृद्धाश्रम में रहने वाले बुजुर्गों से बातचीत कर उनका हालचाल जाना और उनके साथ समय बिताया। इस दौरान बुजुर्गों के प्रति स्नेह और सम्मान का भाव व्यक्त किया गया। आयोजकों ने बताया कि अभियान के माध्यम से महात्मा गांधी के सेवा, करुणा, मानवता और प्रत्येक व्यक्ति के सम्मान से जुड़े विचारों को समाज तक पहुंचाने का प्रयास किया जा रहा है।

वृद्धाश्रम में आयोजित कार्यक्रम को इसी कड़ी का हिस्सा बताया गया। कार्यक्रम के दौरान बुजुर्गों की जरूरतों और उनकी देखभाल के महत्व पर भी जोर दिया गया।

आयोजकों के अनुसार, इस तरह के सेवा कार्यक्रम समाज में संवेदना और सामाजिक जिम्मेदारी की भावना को मजबूत करने में सहायक होते हैं। गांधी जयंती सेवा अभियान के तहत आगे भी विभिन्न सेवा गतिविधियां आयोजित की जाएंगी।

रामलीला, दुर्गा पूजा और छठ की तैयारियों के लिए दिल्ली सरकार ने बनाई तीन समितियां मंत्रियों-विधायकों को मिली जिम्मेदारी

नई दिल्ली । राजधानी दिल्ली में आने वाले आस्था के बड़े पर्वों रामलीला, दुर्गा पूजा और छठ पूजा को भव्य और सुव्यवस्थित तरीके से मनाने के लिए मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कदम उठाया है। मुख्यमंत्री के निर्देश पर तीनों पर्वों के लिए तीन अलग-अलग विशेष समितियों का गठन किया गया है। इन समितियों की कमान मंत्रियों, विधायकों और समाजसेवियों को सौंपी गई है।

मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि इन समितियों का मुख्य उद्देश्य श्रद्धालुओं को बेहतर सुविधा, सुरक्षा और सुचारु व्यवस्था उपलब्ध कराना है। सरकार चाहती है कि दिल्ली में ये पर्व श्रद्धा, अपनत्व और सौहार्दपूर्ण वातावरण में मनाए जाएं और आयोजन समितियों को किसी प्रकार की परेशानी न हो। रामलीला समिति की कमान मंत्री रविंद्र इंद्राज सिंह कोरामलीला आयोजनों के लिए गठित समिति के अध्यक्ष समाज कल्याण, एससी/एसटी कल्याण, सहकारिता एवं निर्वाचन मंत्री रविंद्र इंद्राज सिंह बनाए गए हैं। इस समिति में विधायक अशोक गोयल, अनिल कुमार शर्मा, श्याम शर्मा, संजय गोयल और संदीप सहरावत सदस्य होंगे, जबकि सचिव, राजस्व-सह-मंडलायुक्त इसके सदस्य सचिव होंगे।

समिति की मुख्य जिम्मेदारी जिला मजिस्ट्रेट कार्यालय के माध्यम से सिंगल विंडो सिस्टम के तहत रामलीला के लिए जरूरी एनओसी जारी करवाना होगी। इसके अलावा रामलीला स्थलों पर पीने के पानी, चिकित्सा सहायता, एंबुलेंस, अग्निशमन सेवा, सुरक्षा, मोबाइल शौचालय, यातायात प्रबंधन, सफाई, फॉगिंग और निर्बाध बिजली आपूर्ति सुनिश्चित करना भी इसी समिति का काम होगा। समिति रामलीला के मंच से पर्यावरण संरक्षण, वोकल फॉर लोकल, स्वच्छता, जल संरक्षण, स्वदेशी और नशा मुक्त भारत अभियान जैसे जनहित के संदेशों को भी बढ़ावा देगी।

दुर्गा पूजा की तैयारियों के लिए गठित समिति की अध्यक्षता कानून एवं न्याय, श्रम, रोजगार, विकास, कला-संस्कृति भाषा तथा पर्यटन मंत्री कपिल मिश्रा करेंगे। समिति में विधायक शिखा रॉय और नीरज बसोया के साथ सामाजिक कार्यकर्ता अंजलि भट्टाचार्य, देवदत्त भारद्वाज और अरुण मुखर्जी सदस्य के रूप में शामिल हैं।

यह समिति भी पूजा स्थलों पर सभी नागरिक सुविधाएं, सुरक्षा और एनओसी की व्यवस्था देखेगी। इसके अलावा, दुर्गा पूजा के लिए विशेष रूप से मूर्तियों के विसर्जन हेतु कृत्रिम और अस्थायी तालाबों की व्यवस्था करना और विसर्जन के बाद अवशेषों की सफाई सुनिश्चित करना भी इसकी जिम्मेदारी होगी।

छठ पूजा के लिए भी मंत्री कपिल मिश्रा की अध्यक्षता में ही समिति बनाई गई है। इसमें विधायक अभय कुमार वर्मा, चंदन कुमार चौधरी, संदीप सहरावत, दीपक चौधरी और सामाजिक कार्यकर्ता संतोष ओझा सदस्य होंगे। सचिव, राजस्व-सह-मंडलायुक्त इसके सदस्य सचिव होंगे। छठ समिति घाटों और आयोजन स्थलों पर पानी, चिकित्सा, एंबुलेंस, सुरक्षा, सफाई और बिजली जैसी सभी व्यवस्थाओं की निगरानी करेगी और सिंगल विंडो सिस्टम से एनओसी दिलाने में मदद करेगी।

मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा, "रामलीला, दुर्गा पूजा और छठ पूजा केवल धार्मिक आयोजन नहीं, बल्कि दिल्ली की सामाजिक और सांस्कृतिक विविधता को जोड़ने वाले आस्था के पर्व हैं। इनसे लाखों लोगों की भावनाएं जुड़ी हैं।

सीएम के दौरे के बीच पुलिस महकमे में हड़कंप

उदयपुर में एसओजी एडिशनल एसपी मुकेश सोनी के नाम पर 2 करोड़ की घूस लेते दलाल गिरफ्तार

उदयपुर। भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (ACB) की टीम ने शनिवार को झीलों की नगरी उदयपुर में एक ऐसी सनसनीखेज और ऐतिहासिक कार्रवाई को अंजाम दिया, जिसने पूरे पुलिस महकमे और प्रशासनिक गलियारों की चूलें हिलाकर रख दी हैं। एसीबी ने स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप (SOG) के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ((Additional SP मुकेश सोनी के नाम पर दो करोड़ रुपये की भारी-भरकम रिश्वत राशि लेते हुए एक निजी दलाल सज्जन कुमार उर्फ टाटला को रंगे हाथों धर दबोचा। प्रदेश में किसी पुलिस अफसर के नाम पर इतनी बड़ी रकम के ट्रैप की यह संभवतः सबसे बड़ी कार्रवाइयों में से एक मानी जा रही है। खास बात यह रही कि एसीबी ने यह जोरदार सर्जिकल स्ट्राइक ठीक उसी वक्त की, जब सूबे के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा खुद उदयपुर प्रवास पर थे। उदयपुर संभाग में एक तरफ मुख्यमंत्री करोड़ों रुपये की विकास योजनाओं का लोकार्पण कर रहे थे और निकाय चुनावों में जीत दर्ज करने वाले पार्टी पार्षदों व जनप्रतिनिधियों से मुलाकात कर रहे थे, वहीं दूसरी तरफ शहर के दूसरे कोने में एसीबी रिश्वत के इस बड़े खेल का पदार्फाश कर रही थी। एसओजी के केस में राहत के बदले मांगी थी करोड़ों की 'डील' मिली जानकारी के अनुसार, परिवादी ने एसीबी मुख्यालय में उपस्थित होकर एक गोपनीय शिकायत दर्ज कराई थी। शिकायत में बताया गया था कि स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप (एसओजी) में उसके खिलाफ विचाराधीन एक मामले में कानूनी राहत देने, जांच को प्रभावित करने और पक्ष में फैसला कराने के एवज में

भारत का बॉन्ड बाजार मजबूत, आर्थिक बुनियाद के दम पर शेयर बाजार में फिर से लौटेगी तेजी: आरबीआई

नई दिल्ली । भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) की डिप्टी गवर्नर पूनम गुप्ता ने कहा है कि हाल के वर्षों में भारत के बॉन्ड बाजार का प्रदर्शन न केवल अपने पिछले रिकॉर्ड की तुलना में बेहतर रहा है, बल्कि दुनिया के अधिकांश देशों की तुलना में भी अधिक मजबूत रहा है। उनका कहना है कि भारतीय अर्थव्यवस्था की मजबूत बुनियाद अंततः शेयर बाजार में भी दिखाई देगी और भारतीय इक्विटी दोबारा निवेशकों के लिए आकर्षक बनेगी।

आरबीआई के सितंबर बुलेटिन में पूनम गुप्ता ने कहा कि अमेरिका में बॉन्ड यील्ड 22 वर्षों के उच्चतम स्तर पर पहुंचने के बावजूद भारतीय बॉन्ड बाजार ने मजबूती दिखाई है। उन्होंने इसके पीछे केंद्र सरकार की राजकोषीय अनुशासन के प्रति प्रतिबद्धता और आने वाले वर्षों में उच्च आर्थिक विकास दर की संभावनाओं को प्रमुख कारण बताया।

उन्होंने कहा कि सरकार की वित्तीय स्थिति में सुधार और भविष्य में बेहतर राजकोषीय परिणामों की उम्मीदों ने भारतीय बॉन्ड बाजार को मजबूती प्रदान की है। इसके अलावा मौद्रिक नीति की विश्वसनीयता और मुद्रास्फीति से जुड़े संरचनात्मक दबावों में आई कमी ने भी निवेशकों का भरोसा बढ़ाया है।

पूनम गुप्ता ने उल्लेख किया कि भारत के सुव्यवस्थित बॉन्ड बाजार को लेकर अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी सराहना हुई है। उन्होंने कहा कि प्रतिष्ठित पत्रिका द इकोनॉमिस्ट ने टिप्पणी की थी कि भारत का अनुभव यह दिखाता है कि सार्वजनिक वित्त को मजबूत रखना और केंद्रीय बैंकरों को स्वतंत्र रूप से महंगाई नियंत्रित करने देना कितना महत्वपूर्ण है।

हालांकि उन्होंने कहा कि भारतीय शेयर बाजार ने अभी तक उसी स्तर का आशावाद नहीं दिखाया है, जैसा बॉन्ड बाजार में देखने को मिला है।

उन्होंने बताया कि इसका एक कारण यह हो सकता है कि कुछ अन्य अर्थव्यवस्थाओं में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) आधारित विकास की कहानी फिलहाल अधिक आकर्षक दिखाई दे रही है।

उन्होंने कहा कि भारतीय शेयर बाजार ने जून 2022 से सितंबर 2024 के बीच असाधारण प्रदर्शन किया था, लेकिन वर्तमान में कुछ अन्य देशों के बाजार उस तरह की तेजी का अनुभव कर रहे हैं। इसके बावजूद उनका मानना है कि आखिरकार वास्तविक अर्थव्यवस्था की मजबूती अपना प्रभाव दिखाएगी और भारतीय शेयर फिर अपेक्षाकृत अधिक आकर्षक नजर आएंगे।

गुप्ता ने भारत के भुगतान संतुलन (बैलेंस ऑफ पेमेंट्स - बीओपी) और रुपए की दिशा पर भी चर्चा की। उन्होंने कहा कि अक्सर यह सवाल उठता है कि क्या भुगतान संतुलन और विनिमय दर देश की वास्तविक आर्थिक ताकत को सही ढंग से दर्शाते हैं।

चक्रवात अर्नब का तांडव : उत्तर प्रदेश में 48 घंटे से भारी बारिश और आंधी, 13 की मौत, 14 राज्यों में अलर्ट

बिहार के सुपौल में 50 गांव जलमग्न, राजस्थान-एमपी में भी बारिश का अलर्ट

नई दिल्ली/लखनऊ। बंगाल की खाड़ी से उठे चक्रवाती तूफान 'अर्नब' (Cyclone Arnab) के प्रभाव से उत्तर भारत सहित देश के 14 राज्यों में मौसम ने विकराल रूप धारण कर लिया है। दक्षिण छत्तीसगढ़ से उत्तर-पूर्व दिशा की ओर बढ़ रहे इस मौसमी सिस्टम के कारण उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान और मध्य प्रदेश सहित कई राज्यों में मूसलाधार बारिश और तेज आंधी का दौर जारी है, जिससे जनजीवन अस्त-व्यस्त हो गया है। उत्तर प्रदेशः 32 जिलों में बाढ़ का खतरा, हादसों में 13 की जान गई

उत्तर प्रदेश में पिछले 48 घंटों से लगातार 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रही तूफानी हवाओं और झमाझम बारिश ने भारी तबाही मचाई हैः

हादसे व जनहानिः प्रदेश के अलग-अलग जिलों में दीवार गिरने, पेड़ उखड़ने और बिजली गिरने जैसी घटनाओं में अब तक 13 लोगों की मौत हो चुकी है। कन्नौज के पास आगरा-लखनऊ एक्सप्रेसवे पर तेज आंधी-बारिश के कारण एक कार अनियंत्रित होकर पलट गई, जिसमें 5 लोग गंभीर रूप से फंस गए।

राजधानी में जलभरावः राजधानी लखनऊ के कई इलाकों में सड़कों पर तीन-तीन फीट तक पानी भर गया है और पानी लोगों के घरों में घुस गया है। बाढ़ की चेतावनीः लगातार हो रही बारिश को देखते हुए प्रशासन ने प्रदेश के 32 जिलों में बाढ़ का खतरा घोषित करते हुए अलर्ट जारी किया है।

उत्तराखंडः बद्रीनाथ में बर्फबारी, पिथौरागढ़ में लैंडस्लाइड से 300 से अधिक गाड़ियां फंसीपहाड़ी राज्यों में चक्रवात का असर बर्फबारी और भूस्खलन के रूप में देखने को मिल रहा हैः

मौसम का पहला हिमपातः चमोली जिले स्थित बद्रीनाथ धाम और प्रसिद्ध सिख तीर्थ स्थल हेमकुंड साहिब में मौसम की पहली बर्फबारी दर्ज की गई है, जिससे तापमान में भारी गिरावट आई है।

लैंडस्लाइड से मार्ग बाधितः पिथौरागढ़-घाट मुख्य मार्ग पर भीषण लैंडस्लाइड (भूस्खलन) के कारण पहाड़ियों से मलबा सड़क पर आ गिरा है, जिससे मार्ग पूरी तरह ठप हो गया है और 300 से अधिक वाहन जाम में फंसे हुए हैं।

बिहार, राजस्थान और मध्य प्रदेश में भी अलर्ट

बिहार में यलो अलर्टः बिहार के सुपौल जिले में कोसी नदी के जलस्तर में वृद्धि और बारिश के कारण 50 से अधिक गांव बाढ़ की चपेट में आ गए हैं। राज्य में बारिश और आकाशीय बिजली से जुड़ी घटनाओं में 3 लोगों की मौत हुई है। मौसम विभाग ने राज्य के 19 जिलों में 'यलो अलर्ट' जारी किया है।

राजस्थान व मध्य प्रदेशः चक्रवात के असर से राजस्थान और मध्य प्रदेश के पूर्वी व उत्तरी हिस्सों में बादलों की आवाजाही के साथ तेज हवाएं और मध्यम से भारी बारिश दर्ज की जा रही है।

पंजाब में पराली जलाने के 32 मामले सामने आए, 25 की हुई जांच

पटियाला। पंजाब में पराली जलाने के संबंध में इसरो (भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन) सैटेलाइट प्रोटोकॉल के तहत अब तक 32 घटनाएं रिपोर्ट हुई हैं। सीएक्यूएम (वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग) ने जानकारी दी कि 32 में से 25 मामलों का जमीनी स्तर पर निरीक्षण किया गया, जबकि 12 स्थानों पर मौके पर आग की पुष्टि हुई। सीएक्यूएम की रिपोर्ट के मुताबिक, 8 केसों में पर्यावरणीय मुआवजा लगाया गया, जिसकी कुल राशि 40,000 रुपए है।

इसमें से अब तक 10,000 रुपए की वसूली की जा चुकी है। वहीं, पराली जलाने के मामलों में 5 एफआईआर दर्ज की गई हैं और 4 मामलों में संबंधित नोडल/सुपरवाइजरी अधिकारियों को चेतावनी नोटिस जारी किए गए हैं। पटियाला जिले में रिपोर्ट के अनुसार, आग की एक घटना सामने आई। इसका निरीक्षण किया गया और मौके पर भी इसकी पुष्टि हुई। इस मामले में 5,000 रुपए का पर्यावरणीय मुआवजा लगाया गया। हालांकि, रिपोर्ट में अभी तक इसकी वसूली शून्य दर्ज है।

जिलावार आंकड़ों के अनुसार, सबसे अधिक मामले अमृतसर में दर्ज हुए हैं। यहां कुल 18 मामले आए और 11 मामलों में फील्ड निरीक्षण किया गया। आयोग ने 4 की मौके पर पुष्टि की। इसको लेकर कार्रवाई करते हुए 5,000 रुपए का पर्यावरणीय मुआवजा लगाया और वसूल भी किया गया। तरनतारन जिले में 5 मामले आए और 2 की मौके पर पुष्टि हुई। इन 2 मामलों में कुल 10,000 रुपए का मुआवजा वसूल किया गया है। साथ ही, इन घटनाओं को लेकर दो एफआईआर भी दर्ज हुई हैं। फिरोजपुर जिले में 4 मामले आए और सभी 4 का निरीक्षण व पुष्टि की गई। 3 मामलों में कुल 15,000 रुपए का पर्यावरणीय मुआवजा लगाया गया, जिनमें से 5,000 रुपए वसूल किए गए। फिरोजपुर में तीन एफआईआर दर्ज की गई हैं, जबकि चार चेतावनी नोटिस भी जारी किए गए हैं।

सैटेलाइट प्रोटोकॉल के तहत गुरदासपुर जिले में 2 मामले, जबकि होशियारपुर, पटियाला और एसबीएस नगर में एक-एक मामला दर्ज किया गया। होशियारपुर व पटियाला की घटना में पुष्टि के बाद 5-5 हजार रुपए का पर्यावरणीय मुआवजा लगाया गया है।

तीन दिन की बैंक हड़ताल से पहले जरूरी काम निपटा लें ग्राहक, 28 सितंबर से कई सेवाएं हो सकती हैं प्रभावित

नई दिल्ली । सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों और कुछ पुरानी पीढ़ी के निजी बैंकों के ग्राहकों को सलाह दी गई है कि वे अपने महत्वपूर्ण बैंकिंग लेनदेन पहले ही पूरा कर लें, क्योंकि बैंक कर्मचारी यूनियनें 28 सितंबर से तीन दिन की देशव्यापी हड़ताल पर जाने की तैयारी कर रही हैं। प्रस्तावित हड़ताल से कई बैंकों की शाखा सेवाएं प्रभावित हो सकती हैं और यह बैंकिंग क्षेत्र के महत्वपूर्ण अर्धवार्षिक समापन (हाफ-ईयर क्लोजिंग) के दौरान हो रही है।

यह हड़ताल यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियंस (यूएफबीयू) की ओर से बुलाई गई है, जो दावा करता है कि वह देश के लगभग 90 प्रतिशत बैंक कर्मचारियों का प्रतिनिधित्व करता है।

यूनियनें पांच दिन के बैंकिंग सप्ताह को लागू करने, पेंशन सुधारों और कर्मचारियों के कल्याण से जुड़े अन्य मुद्दों पर मांग कर रही हैं। ग्राहकों को होने वाली असुविधा कम करने के लिए केंद्र सरकार ने सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों को रविवार, 27 सितंबर को भी खुले रखने का निर्देश दिया है, ताकि लोग हड़ताल शुरू होने से पहले अपने जरूरी बैंकिंग कार्य पूरे कर सकें। भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) ने जारी एडवाइजरी में कहा है कि वह शाखाओं और कार्यालयों में आवश्यक सेवाएं जारी रखने का प्रयास करेगा, लेकिन हड़ताल के दौरान कुछ बैंकिंग सेवाएं प्रभावित हो सकती हैं।

बैंक ने ग्राहकों से कहा है कि वे अपने महत्वपूर्ण लेनदेन पहले ही निपटा लें और जहां संभव हो, योनो, इंटरनेट बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग, यूपीआई, एटीएम और कैश डिपॉजिट मशीनों जैसी डिजिटल सेवाओं का उपयोग करें।

बैंक ऑफ इंडिया ने भी ग्राहकों को संभावित हड़ताल के बारे में आगाह करते हुए सलाह दी है कि वे बैंकिंग जरूरतों के लिए इंटरनेट बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग, एटीएम, बिजनेस कॉरेस्पोंडेंट पॉइंट और यूपीआई जैसी चौबीसो घंटे उपलब्ध डिजिटल सेवाओं का इस्तेमाल करें।

रिपोर्ट के अनुसार, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक (आरआरबी) के कर्मचारी भी आंदोलन में शामिल हो सकते हैं, जिससे देशभर में बैंकिंग सेवाओं पर असर और व्यापक हो सकता है।

हालांकि, नई पीढ़ी के निजी क्षेत्र के बैंक जैसे आईसीआईसीआई बैंक, एचडीएफसी बैंक, एक्सिस बैंक और इंडसइंड बैंक के सामान्य रूप से काम जारी रखने की उम्मीद है। ऐसे में ग्राहकों के लिए नियमित बैंकिंग सेवाओं का एक वैकल्पिक विकल्प उपलब्ध रहेगा।

इस सप्ताह की शुरूआत में वित्त मंत्रालय ने बैंक कर्मचारी यूनियनों से हड़ताल टालने और लंबित मुद्दों को बातचीत के जरिए सुलझाने की अपील की थी। मंत्रालय का कहना है कि यूनियनों द्वारा उठाई गई अधिकांश चिंताओं पर पहले ही काफी हद तक कार्रवाई की जा चुकी है।

यूपी में भारी बारिश के बीच राहत-बचाव जारी, नेपाल सीमा से सटे जिलों में विशेष निगरानी

लखनऊ । उत्तर प्रदेश में पिछले 48 घंटों से जारी भारी बारिश और प्रतिकूल मौसम की स्थिति को देखते हुए योगी सरकार ने राहत एवं बचाव व्यवस्था को पूरी तरह सक्रिय रखा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देशों के क्रम में प्रशासन प्रभावित क्षेत्रों में लगातार निगरानी कर रहा है।

राहत आयुक्त डॉ. हृषिकेश भास्कर यशोद ने शनिवार को प्रभावित जनपदों के जिलाधिकारियों को अतिवृष्टि से प्रभावित परिवारों से व्यक्तिगत रूप से मिलकर उनकी समस्याओं का त्वरित निस्तारण सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने स्पष्ट किया कि हर परिस्थिति में आमजन की जान-माल की सुरक्षा जिलाधिकारियों की सर्वोच्च प्राथमिकता होनी चाहिए। राहत आयुक्त ने नेपाल में हो रही भारी बारिश के मद्देनजर सीमावर्ती जिलों, विशेषकर पूर्वी उत्तर प्रदेश में नदियों के जलस्तर बढ़ने की आशंका को देखते हुए प्रशासन को अतिरिक्त सतर्कता बरतने को कहा। संबंधित जिलाधिकारियों को नदियों के जलस्तर पर लगातार नजर रखने और बाढ़ राहत एवं बचाव दलों को अलर्ट मोड पर रखने के लिए कहा गया है। भारत मौसम विज्ञान विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार आगामी 36 घंटों के बाद प्रदेश में मौसम सामान्य होने की संभावना है। राहत आयुक्त ने आमजन से अपील की है कि अत्यंत आवश्यक होने पर ही घर से बाहर निकलें और सुरक्षित स्थानों पर रहें। उन्होंने लोगों से प्रशासन और मौसम विभाग की ओर से जारी दिशा-निर्देशों का पालन करने की अपील की। किसी भी आपदा की स्थिति में तत्काल सहायता के लिए राहत हेल्पलाइन 1070 पर संपर्क किया जा सकता है।

राहत आयुक्त ने बताया कि प्रदेश के 63 जनपदों में सामान्य से अधिक वर्षा दर्ज की गई है। पिछले 24 घंटों के दौरान पूरे प्रदेश में सामान्य से 19 गुना अधिक वर्षा हुई। फरुर्खाबाद में सामान्य से 200 गुना, कानपुर नगर में 160 गुना, कन्नौज, कानपुर देहात और हरदोई में सामान्य से 130 गुना अधिक वर्षा दर्ज की गई है। भदोही, देवरिया और अलीगढ़ में सामान्य वर्षा हुई, जबकि गाजीपुर में सबसे कम बारिश दर्ज की गई। वहीं बागपत, गाजियाबाद, मथुरा, मुजफ्फरनगर, सहारनपुर, शामली, गौतमबुद्धनगर और हापुड़ में वर्षा नहीं हुई। पिछले 48 घंटों में अतिवृष्टि और आंधी-तूफान के कारण प्रदेश में 117 मकानों के क्षतिग्रस्त होने की सूचना प्राप्त हुई है।

राहत आयुक्त ने संबंधित जिलाधिकारियों को प्रभावित परिवारों को पूरी संवेदनशीलता के साथ अनुमन्य सहायता राशि तत्काल उपलब्ध कराने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने भारी बारिश से हुई क्षति का तत्काल सर्वेक्षण एवं आकलन कराने और प्रभावित लोगों को नियमानुसार राहत सहायता शीघ्र उपलब्ध कराने को कहा है। साथ ही फील्ड अधिकारियों को बारिश से फसलों को हुए नुकसान का त्वरित आकलन कराने का निर्देश दिया गया है, ताकि प्रभावित किसानों को नियमानुसार सहायता उपलब्ध कराई जा सके।

राहत आयुक्त ने जिलाधिकारियों को निर्देश दिया है कि आवश्यकता के अनुसार फायर सर्विस, पीएसी, सिविल डिफेंस, होमगार्ड और आपदा मित्रों की सेवाएं ली जाएं। सभी राहत एवं बचाव दलों को सक्रिय रखते हुए प्रभावित क्षेत्रों में निरंतर भ्रमण और निगरानी सुनिश्चित करने को कहा गया है। जिलाधिकारियों को स्वयं फील्ड में रहकर स्थिति का लगातार आकलन करने और स्थानीय परिस्थितियों के अनुसार त्वरित निर्णय लेने के निर्देश दिए गए हैं।

योगी सरकार की ओर से प्रशासन को स्पष्ट किया गया है कि प्रतिकूल मौसम के दौरान आमजन की सुरक्षा में किसी भी स्तर पर लापरवाही नहीं होनी चाहिए।

लेखपालों और ग्राम विकास अधिकारियों के माध्यम से कच्चे मकानों के आस-पास जलभराव की स्थिति का तत्काल संज्ञान लेने के निर्देश दिए गए हैं। जल निकासी की समुचित व्यवस्था के साथ कच्चे मकानों में रहने वाले परिवारों की सुरक्षा के लिए आवश्यक सुरक्षात्मक कदम उठाने को कहा गया है।

पंजाब में कोई सुरक्षित नहीं, पुलिसकर्मी भी असुरक्षित महसूस कर रहे: सुनील जाखड़

चंडीगढ़ । पंजाब में कानून-व्यवस्था को लेकर भाजपा नेता सुनील जाखड़ ने राज्य सरकार पर तीखा हमला बोला। उन्होंने आरोप लगाया कि भगवंत मान की सरकार में कोई भी सुरक्षित नहीं है, यहां तक कि रक्षक भी अपनी सुरक्षा को लेकर चिंतित हैं। चंडीगढ़ में मीडिया से बातचीत के दौरान सुनील जाखड़ ने कहा कि पंजाब में कोई भी सुरक्षित नहीं है।

आम लोगों की तो बात ही छोड़िए, खुद पुलिस वाले भी असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। उन्होंने दावा किया कि पुलिस मुख्यालय और सरकार की ओर से जारी एक एडवाइजरी में पुलिस अधिकारियों को अकेले पुलिस स्टेशन से निकलने, यात्रा के दौरान वर्दी न पहनने, साथ में जवान रखने, हथियार लेकर चलने और दोपहिया वाहनों से यात्रा करने से बचने जैसी बातें कही गई हैं। अगर कानून-व्यवस्था संभालने वाले पुलिसकर्मी ही असुरक्षित महसूस कर रहे हैं, तो आम लोगों की सुरक्षा को लेकर सवाल उठना स्वाभाविक है।

मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ विपक्ष के विरोध और एसआईआर से जुड़े विवाद पर सुनील जाखड़ ने कहा कि पंजाब में कंप्यूटर प्रणाली के जरिए करीब 22.70 लाख आपत्तियां दर्ज की गई थीं। इनमें नाम, जन्मतिथि या माता-पिता की उम्र से जुड़ी विसंगतियां शामिल थीं और करीब 99 प्रतिशत मामलों को अधिकारियों ने निपटा दिया। करीब 20.66 लाख मतदाता ड्राफ्ट मतदाता सूची में शामिल नहीं किए गए थे। उन्होंने कुल मतदाताओं की संख्या करीब 2.14 करोड़ बताते हुए विपक्ष से सवाल किया कि हटाए गए नामों को लेकर कितनी आपत्तियां दर्ज कराई गईं।

न्यूज फ्लैश

झारखंड में लगातार हो रही बारिश से जनजीवन प्रभावित, रांची और जमशेदपुर में स्कूल बंद

रांची । तीन दिनों से राजधानी रांची सहित झारखंड के अन्य जिलों में हो रही बारिश से कई जगहों पर बाढ़ जैसे हालात हो गए हैं। शहर और गांवों में पानी भरने से आम जनजीवन प्रभावित है। बारिश को देखते हुए रांची और जमशेदपुर में प्रशासन ने शनिवार स्कूलों को बंद करने का निर्देश दिया है। मूसलाधार बारिश ने जमशेदपुर और आसपास के इलाकों में जनजीवन को बुरी तरह प्रभावित कर दिया है। लगातार वर्षा के कारण शहर की प्रमुख नदियां स्वर्णरेखा और खरकई खतरे के निशान को पार कर चुकी हैं, जिससे निचले क्षेत्रों में बाढ़ का खतरा बढ़ गया है।

कई इलाकों में नदी का पानी प्रवेश कर गया है और लोगों के सामने सुरक्षित स्थानों पर जाने की नौबत आ गई है। स्थिति की गंभीरता को देखते हुए जिला प्रशासन ने एहतियातन सभी सरकारी और निजी स्कूलों को बंद रखने का निर्देश जारी किया है। प्रशासन लगातार हालात पर नजर बनाए हुए है और संवेदनशील क्षेत्रों में निगरानी बढ़ा दी गई है। मानगो, बागबेड़ा, शास्त्रीनगर समेत नदी किनारे और निचले इलाकों में रहने वाले लोगों को सुरक्षित स्थानों पर जाने की सलाह दी गई है। प्रशासन की ओर से लोगों को सतर्क रहने और अनावश्यक रूप से घरों से बाहर नहीं निकलने की अपील की गई है।

शनिवार को बारिश की तीव्रता में कुछ कमी जरूर आई है, लेकिन खतरा अभी टला नहीं है। नदियों का जलस्तर लगातार ऊंचा बना हुआ है, जिससे प्रशासन अलर्ट मोड पर है। संभावित बाढ़ की स्थिति से निपटने के लिए राहत एवं बचाव दलों को तैयार रखा गया है।

लगातार बारिश के कारण कई सड़कों पर जलजमाव की स्थिति उत्पन्न हो गई है, जिससे यातायात भी प्रभावित हुआ है। प्रशासन ने लोगों से अफवाहों पर ध्यान नहीं देने तथा किसी भी आपात स्थिति में जिला नियंत्रण कक्ष और प्रशासनिक अधिकारियों से संपर्क करने की अपील की है।

केंद्रीय मंत्री बोलीं- कानून को लेकर जनता को गुमराह कर रहा विपक्ष, निवेश और रोजगार बढ़ने का दावा

रांची। खान एवं खनिज (विकास एवं विनियमन) संशोधन अधिनियम-2026 को लेकर झारखंड में सियासी घमासान तेज हो गया है। शनिवार को भाजपा प्रदेश कार्यालय में आयोजित प्रेस वार्ता में केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने संशोधित कानून को लेकर केंद्र सरकार का पक्ष रखा। उन्होंने झामुमो, कांग्रेस और राजद समेत विपक्षी दलों पर कानून के प्रावधानों को लेकर लोगों को गुमराह करने का आरोप लगाया। अन्नपूर्णा देवी ने कहा कि झारखंड खनिज संपदा से समृद्ध राज्य है और संशोधित कानून का उद्देश्य खनन क्षेत्र में स्थिरता, पारदर्शिता और निवेश को बढ़ावा देना है। उन्होंने कहा कि खनन क्षेत्र में निवेश बढ़ने से रोजगार के अवसर भी बढ़ सकते हैं और युवाओं को अपने राज्य में ही रोजगार मिलने की संभावना बनेगी।

कर और उपकर को लेकर क्या कहा

केंद्रीय मंत्री ने कहा कि खनन क्षेत्र में अलग-अलग स्तर पर कर, शुल्क और उपकर को लेकर कारोबारियों के सामने अनिश्चितता रहती थी। उनके मुताबिक, संशोधित कानून का उद्देश्य कर व्यवस्था में अधिक स्पष्टता और एकरूपता लाना है, जिससे उद्योगों को कारोबार करने में सहूलियत हो और कानूनी विवादों में कमी आए।केंद्र सरकार की ओर से भी कहा गया है कि संशोधन का उद्देश्य खनन क्षेत्र में दीर्घकालिक स्थिरता और पूर्वानुमेय वित्तीय व्यवस्था बनाना है। सरकार के अनुसार खनन से मिलने वाले राजस्व का करीब 90 प्रतिशत हिस्सा राज्यों को मिलता रहेगा। हालांकि, संशोधन में खनिज

अधिकारों और खनिज-युक्त भूमि पर राज्य सरकारों की ओर से कर, उपकर या अन्य शुल्क लगाने को लेकर नई सीमाएं निर्धारित की गई हैं।

ह्यझारखंड में ही कानून का विरोध क्यों

अन्नपूर्णा देवी ने सवाल उठाया कि जब संशोधित कानून पूरे देश में लागू है तो झारखंड में ही इसका विरोध क्यों किया जा रहा है। उन्होंने ओडिशा, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़, कर्नाटक और केरल समेत दूसरे राज्यों का भी उल्लेख किया और कहा कि कानून किसी एक राज्य को ध्यान में रखकर नहीं बनाया गया है। केंद्रीय मंत्री ने झारखंड सरकार पर खनन क्षेत्रों की नीलामी में देरी का आरोप लगाया। साथ ही उन्होंने दावा किया कि राज्य सरकार का कानून का विरोध करने का रुख अवैध खनन और कोयला चोरी पर कार्रवाई से जुड़े सवालों को भी जन्म देता है।

ये आरोप केंद्रीय मंत्री के राजनीतिक बयान का हिस्सा हैं; इन पर राज्य सरकार या विपक्ष की प्रतिक्रिया अलग हो सकती है।

राज्य के अधिकार को लेकर विवाद

टटउफ्र संशोधन को लेकर केंद्र और झारखंड सरकार के बीच मुख्य विवादों में से एक राज्य सरकारों की कर लगाने की शक्ति से जुड़ा है। संशोधन में नया प्रावधान राज्य सरकारों द्वारा खनिज अधिकारों और खनिज-युक्त भूमि पर कर, उपकर या अन्य शुल्क लगाने पर शर्तें निर्धारित करता है। वहीं, संशोधन की समीक्षा करने वाले पीआरएस के अनुसार यह प्रावधान राज्यों की कराधान शक्तियों को लेकर संवैधानिक सवाल भी खड़े करता है। झारखंड में विपक्षी दल इस कानून को लेकर लगातार विरोध दर्ज करा रहे हैं। कांग्रेस ने आंदोलन की घोषणा की है, जबकि झामुमो की ओर से भी संशोधन के विरोध में धरना-प्रदर्शन किए गए हैं। अन्नपूर्णा देवी ने कहा कि केंद्र सरकार का उद्देश्य खनन व्यवस्था में स्पष्टता और एकरूपता लाना है, ताकि खनन क्षेत्र में निवेश को बढ़ावा मिले और रोजगार के अवसर पैदा हों। उन्होंने इसे ह्यविकसित भारतह्न के साथ ह्यविकसित झारखंडह्न की दिशा में उठाया गया कदम बताया।

जमशेदपुर में बाढ़ का खतरा : खरकई नदी खतरे के निशान के ऊपर

जमशेदपुर । लगातार बारिश और विभिन्न जलाशयों से छोड़े जा रहे पानी के कारण जमशेदपुर में बाढ़ का खतरा बढ़ गया है। शुक्रवार को आदित्यपुर पुल के पास खरकई नदी का जलस्तर खतरे के निशान को पार कर गया। नदी 129.010 मीटर पर बह रही थी जबकि खतरे का निशान 129.00 मीटर निर्धारित है। जलस्तर बढ़ने से खरकई और स्वर्णरेखा नदी के किनारे बसे निचले इलाकों में लोगों की चिंता बढ़ गई है और कई स्थानों पर पानी पहुंचना शुरू हो गया है।

बंगाल की खाड़ी में बने गहरे दबाव और जलग्रहण क्षेत्रों में हुई भारी बारिश का असर क्षेत्र की नदियों और जलाशयों पर दिखाई दे रहा है। झारखंड और ओडिशा के जलाशयों से अतिरिक्त पानी छोड़े जाने के कारण जमशेदपुर के नदी तटीय इलाकों में जलस्तर बढ़ रहा है। प्रशासन ने संवेदनशील क्षेत्रों में निगरानी बढ़ा दी है। खरकई नदी का पानी बागबेड़ा नया बस्ती और बड़ौदा घाट, कदमा के शास्त्रीनगर, सोनारी और रामनगर, मानगो, जुगसलाई तथा भुइयांडीह के कल्याण नगर और इंदिरा नगर के निचले हिस्सों तक पहुंच गया है। कई जगह नालियों के रास्ते नदी का पानी पीछे आने से सड़क और घरों के आसपास जलजमाव की स्थिति बनी है।

भारत विकास की गंगा : 2047 तक विकसित भारत के लिए 100 प्रमुख क्षेत्र

आचार्य सी. ए., प्रा., डॉ. शंकर घनशामदास अंदानी
अहिल्या नगर

2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने के लिए केवल आर्थिक वृद्धि पर्याप्त नहीं होगी। शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, कृषि, उद्योग, विज्ञान, पर्यावरण, सुशासन, सामाजिक सुरक्षा और मानव विकास जैसे अनेक क्षेत्रों में समानांतर प्रगति आवश्यक होगी। इस दिशा में 100 प्रमुख क्षेत्र इस प्रकार हैं:

अर्थव्यवस्था और वित्त
सकल घरेलू उत्पाद में वृद्धि
प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि
रोजगार सृजन
बेरोजगारी में कमी
महंगाई नियंत्रण
बैंकिंग क्षेत्र का विस्तार
वित्तीय समावेशन
डिजिटल भुगतान व्यवस्था
पूंजी बाजार का विकास
कर व्यवस्था में सुधार
कृषि और ग्रामीण विकास
कृषि उत्पादकता
सिंचाई विस्तार
जल-संरक्षण आधारित खेती
जैविक एवं प्राकृतिक खेती
कृषि यंत्रीकरण
कृषि अनुसंधान
किसानों की आय में वृद्धि
किसान उत्पादक संगठन
कृषि भंडारण व्यवस्था
कृषि प्रसंस्करण उद्योग
उद्योग और व्यापार
विनिर्माण क्षेत्र
सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों का विकास
स्टार्टअप और उद्यमिता
निर्यात वृद्धि
वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला में भागीदारी
वस्त्र उद्योग
ऑटोमोबाइल उद्योग
इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण
रक्षा उत्पादन
खनिज एवं धातु उद्योग
शिक्षा और कौशल
प्राथमिक शिक्षा
माध्यमिक शिक्षा
उच्च शिक्षा
तकनीकी शिक्षा
व्यावसायिक शिक्षा
कौशल विकास
डिजिटल शिक्षा
अनुसंधान आधारित शिक्षा
शिक्षक प्रशिक्षण
शिक्षा में समान अवसर
स्वास्थ्य और मानव विकास
प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाएँ
सरकारी अस्पतालों का आधुनिकीकरण
चिकित्सा शिक्षा
नर्सिंग एवं पैरामेडिकल शिक्षा
आयुष एवं पारंपरिक चिकित्सा
मातृ स्वास्थ्य
शिशु स्वास्थ्य
पोषण
मानसिक स्वास्थ्य सेवाएँ
सस्ती एवं सुलभ दवाएँ
विज्ञान और तकनीक
वैज्ञानिक अनुसंधान
कृत्रिम बुद्धिमत्ता
सेमीकंडक्टर उद्योग
रोबोटिक्स
क्वांटम तकनीक
अंतरिक्ष अनुसंधान
जैव-प्रौद्योगिकी
साइबर सुरक्षा
5जी/6जी संचार
डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना
आधारभूत संरचना
सड़क नेटवर्क
रेलवे आधुनिकीकरण
हाई-स्पीड रेल
बंदरगाह विकास
हवाई अड्डे
शहरी परिवहन
ग्रामीण सड़कें
लॉजिस्टिक्स व्यवस्था
सस्ती एवं गुणवत्तापूर्ण आवास व्यवस्था
स्मार्ट एवं टिकाऊ शहर
ऊर्जा और पर्यावरण
सौर ऊर्जा
पवन ऊर्जा
जलविद्युत
परमाणु ऊर्जा
हरित हाइड्रोजन
ऊर्जा भंडारण
विद्युत वितरण सुधार
प्रदूषण नियंत्रण
वन एवं जैव-विविधता संरक्षण
जलवायु परिवर्तन से निपटना

फुटबॉल मैदान में अचानक गिरा खिलाड़ी, अस्पताल पहुंचते ही मौत

डे-नाइट टूनार्मेंट में खेलते-खेलते गई 37 वर्षीय खिलाड़ी की जान

रांची/बोकारो । बोकारो थर्मल थाना क्षेत्र के नई बस्ती मैदान में शनिवार को चल रहे डे-नाइट फुटबॉल टूनार्मेंट के दौरान उस समय अफरातफरी मच गई, जब खेल के बीच एक खिलाड़ी अचानक मैदान में गिर पड़ा। खिलाड़ी को तत्काल अस्पताल ले जाया गया, लेकिन चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। घटना के बाद खेल मैदान से लेकर अस्पताल तक मातम का माहौल बन गया।

न मृतक की पहचान गोमिया के खंभरा बस्ती निवासी 37 वर्षीय फुटबॉल खिलाड़ी कजरा मुर्मू के रूप में हुई है। बताया जाता है कि बजरंग क्लब की ओर से तीन दिवसीय डे-नाइट फुटबॉल टूनार्मेंट का आयोजन किया जा रहा था। शनिवार को मैच के दौरान कजरा गेंद लेकर विपक्षी टीम के खिलाड़ियों को छकाते हुए आगे बढ़ रहे थे। इसी दौरान गेंद छीनने की कोशिश में एक खिलाड़ी से उनकी मामूली टक्कर हुई और वह अचानक मैदान में गिर पड़े। शुरूआत में खिलाड़ियों और आयोजकों को लगा कि उन्हें सामान्य चोट लगी है।

लेकिन काफी देर तक कजरा के नहीं उठने पर साथी खिलाड़ी और आयोजक उनके पास पहुंचे। उन्हें तत्काल उठाकर इलाज के लिए डीवीसी अस्पताल, बोकारो थर्मल ले जाया गया। वहां चिकित्सकों ने जांच के बाद उन्हें मृत घोषित कर दिया। कजरा मुर्मू की अचानक मौत की खबर मिलते ही उनके परिजन, जनप्रतिनिधि और बड़ी संख्या में खेल प्रेमी अस्पताल पहुंच गए। परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल था। वहीं, कुछ लोगों ने मुआवजे की मांग को लेकर अस्पताल परिसर में विरोध भी जताया।

अचानक मौत ने खड़े किए कई सवाल

मैदान में मामूली टक्कर के बाद स्वस्थ नजर आ रहे खिलाड़ी की अचानक मौत ने सभी को हैरान कर दिया है। आखिर ऐसी क्या वजह रही कि मैदान में गिरने के बाद वह दोबारा उठ ही नहीं सके? इस सवाल का जवाब फिलहाल स्पष्ट नहीं है। चिकित्सकों के अनुसार मौत के वास्तविक कारण की पुष्टि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही हो सकेगी। इधर, घटना की सूचना मिलने के बाद बोकारो थर्मल थाना पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। पुलिस घटना के दौरान मौजूद खिलाड़ियों और प्रत्यक्षदर्शियों से जानकारी जुटा रही है। साथ ही मौत के कारणों की भी जांच की जा रही है।

कजरा मुर्मू अपने पीछे एक पुत्र और एक पुत्री छोड़ गए हैं। जिस मैदान में वह अपनी टीम के लिए खेलते हुए जीत की कोशिश कर रहे थे, वहीं से उनकी अर्थी उठने की खबर ने पूरे इलाके को झकझोर दिया है।

बारिश से गरीबों के कच्चे मकान ढहे, सरकार तत्काल राहत दे : विजय शंकर नायक

रांची । झारखंड के विभिन्न जिलों में लगातार हो रही बारिश के बीच गरीब परिवारों के कच्चे मकानों के ढहने और लोगों के बेघर होने की घटनाओं को लेकर कांग्रेस ने राज्य सरकार से तत्काल राहत एवं पुनर्वास की मांग की है। झारखंड प्रदेश कांग्रेस के प्रवक्ता विजय शंकर नायक ने कहा कि बारिश से जिन परिवारों के आशियाने उजड़ गए हैं, उनके सामने केवल मकान का नुकसान नहीं, बल्कि पूरी गृहस्थी बिखरने का संकट खड़ा हो गया है।

विजय शंकर नायक ने कहा कि भारी बारिश के कारण जिन गरीब परिवारों के घर ध्वस्त हुए हैं, उन्हें सरकारी प्रक्रिया में उलझाने के बजाय तत्काल मदद पहुंचाई जानी चाहिए। उन्होंने मांग की कि प्रभावित इलाकों में 72 घंटे के भीतर सर्वे कराकर क्षतिग्रस्त और पूरी तरह ध्वस्त मकानों का सत्यापन कराया जाए।

उन्होंने कहा कि बेघर परिवारों को तत्काल राहत राशि, राशन, तिरपाल, पेयजल, आवश्यक दवाइयां और सुरक्षित अस्थायी आश्रय उपलब्ध कराया जाए। जिन परिवारों के मकान पूरी तरह ध्वस्त हो गए हैं, उन्हें नियमानुसार मुआवजा देने के साथ प्राथमिकता के आधार पर पक्का आवास उपलब्ध कराने की भी व्यवस्था हो।

राहत कार्यों की निगरानी की मांग

कांग्रेस प्रवक्ता ने आपदा प्रबंधन विभाग और जिला प्रशासन से राहत कार्यों की सीधी निगरानी करने की मांग की। उन्होंने कहा कि प्रभावित परिवारों का सर्वे और सहायता वितरण पारदर्शी तरीके से होना चाहिए तथा राहत पाने वाले परिवारों की सूची सार्वजनिक की जानी चाहिए, ताकि जरूरतमंदों को सरकारी सहायता से वंचित न होना पड़े। नायक ने कहा कि बारिश और आपदा के समय गरीब परिवार सबसे अधिक प्रभावित होते हैं। ऐसे में प्रशासन को राहत पहुंचाने में किसी तरह की देरी नहीं करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि आपदा की घड़ी में प्रभावित परिवारों को राहत देना सरकार की जिम्मेदारी है और बेघर लोगों को सुरक्षित आश्रय तथा सम्मानजनक पुनर्वास मिलना चाहिए।

तालाबों के सौंदर्यीकरण के नाम पर खानापूर्ति का खेल क्या रहेगा जारी राजा तालाब के बाद पुरैन तालाब की बारी ..?

चतरा(संजीत मिश्रा)। नगरपालिका क्षेत्र में तालाबों के सौंदर्यीकरण के नाम पर काम की गुणवत्ता और खर्च को लेकर लगातार सवाल उठते रहे हैं। शिकायतों और मीडिया में खबरें प्रकाशित होने के बावजूद स्थिति में अपेक्षित बदलाव नहीं दिख रहा है। ऐसे में यह सवाल स्वाभाविक है कि आखिर सौंदर्यीकरण के नाम पर हो रहे कार्यों की निगरानी कौन कर रहा है? आपने यह कहावत तो सुनी ही होगी ह्रअंधेर नगरी, चौपट राजाह्व।

यह कहावत नगरपालिका क्षेत्र में सटीक है । चतरा के राजा तालाब के सौंदर्यीकरण को देखकर भी कुछ ऐसा ही सवाल उठने लगता है। जिस उद्देश्य से तालाब के सौंदर्यीकरण की योजना बनाई गई थी, क्या जमीन पर

वास्तव में उसी के अनुरूप काम हुआ? यदि हुआ है तो इसकी गुणवत्ता और उपयोगिता को लेकर सवाल क्यों उठ रहे हैं? चतरा नगरपालिका क्षेत्र ही नहीं, बल्कि नगरपालिका क्षेत्र से बाहर भी विकास योजनाओं में गुणवत्ता को लेकर सवाल समय-समय पर उठते रहे हैं।

शिकायत सामने आती है, जांच या कार्रवाई के नाम पर स्पष्टीकरण मांगा जाता है और इसके बाद मामला धीरे-धीरे ठंडे बस्ते में चला जाता है। ऐसे में सवाल यह भी है कि क्या केवल स्पष्टीकरण मांगना ही कार्रवाई की अंतिम सीमा बनकर रह गया है? अब पुरैन तालाब के सौंदर्यीकरण की चर्चा सामने आई है। एक वार्ड सदस्य के पति की ओर से सोशल मीडिया पर पुरैन तालाब के सौंदर्यीकरण से संबंधित डीपीआर की तस्वीर साझा की गई है। डीपीआर सामने आना अच्छी बात है, क्योंकि इससे लोगों को प्रस्तावित कार्यों की जानकारी मिल सकती है। लेकिन असली सवाल डीपीआर से ज्यादा जमीन पर होने वाले काम की गुणवत्ता और उसकी निगरानी का है। राजा तालाब के अनुभव को देखते हुए पुरैन तालाब के सौंदर्यीकरण में किसी तरह की खानापूर्ति न हो, इसके लिए शुरूआत से ही निगरानी जरूरी है। काम की गुणवत्ता, इस्तेमाल होने वाली सामग्री, स्वीकृत डीपीआर के अनुसार कार्य और खर्च होने वाली राशि इन सभी बिंदुओं को सार्वजनिक किया जाना चाहिए, ताकि बाद में सवाल खड़े होने की गुंजाइश कम हो। तालाब शहर की संपत्ति ही नहीं, बल्कि आम लोगों की सुविधा और पर्यावरण से भी जुड़ा विषय है। इसलिए बुद्धिजीवियों, सामाजिक संगठनों और आम नागरिकों को भी विकास कार्यों की निगरानी में अपनी भूमिका निभानी होगी। सवाल उठाना किसी के खिलाफ होना नहीं है, बल्कि सरकारी राशि से होने वाले काम को बेहतर तरीके से पूरा कराने की जिम्मेदारी का हिस्सा हैk

संरक्षक: संजय शुक्ला,(सत्यम शिवम शुभम पीजी व लां कॉलेज टिकरी)
सलाहकार संपादक:
रिजवान सैफ खान
सह सपांदक: मोहम्मद दानिश फारुकी ,
सह संपादक: राम सिंह यादव
उक्त सभी पद अवैतनिक है

दो दिन से रिम्स में पानी बंद, मरीजों के सामने बूंद-बूंद पानी का संकट

रांची। राजधानी के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल राजेंद्र आयुर्विज्ञान संस्थान (रिम्स) में पिछले दो दिनों से पानी की आपूर्ति बाधित रहने से मरीजों और उनके परिजनों की परेशानी बढ़ गई है। अस्पताल के विभिन्न वार्डों में भर्ती मरीजों के साथ-साथ उनके परिजनों को पीने के पानी और रोजमर्रा की जरूरतों के लिए पानी जुटाने में परेशानी का सामना करना पड़ रहा है।

दो शिक्षकों के भरोसे 101 बच्चे, जसपुर मध्य विद्यालय में पढ़ाई पर संकट

कान्हाचट्टी/चतरा। सरकार भले ही सरकारी विद्यालयों में शिक्षकों की कमी दूर करने और बच्चों को बेहतर शिक्षा उपलब्ध कराने के दावे कर रही हो, लेकिन जमीनी तस्वीर इन दावों पर सवाल खड़े कर रही है। कान्हाचट्टी प्रखंड के तुलबुल पंचायत स्थित जसपुर मध्य विद्यालय में करीब 101 बच्चे महज दो शिक्षकों के भरोसे पढ़ रहे हैं। सबसे बड़ा सवाल यह है कि जब विद्यालय में पहले से ही शिक्षकों की कमी है, तो यहां पदस्थापित एक शिक्षक को दूसरे विद्यालय में प्रतिनियोजन पर भेजने की जरूरत क्यों पड़ी?

जानकारी के अनुसार करीब पांच-छह माह पहले जसपुर मध्य विद्यालय में तीन शिक्षक पदस्थापित थे। इसके बाद एक शिक्षक को प्रतिनियोजन पर दूसरे विद्यालय भेज दिया गया। नतीजा यह हुआ कि 101 बच्चों वाले इस मध्य विद्यालय की पूरी शैक्षणिक जिम्मेदारी अब केवल दो शिक्षकों के कंधों पर आ गई है। अलग-अलग कक्षाओं और विषयों को संभालने के बीच दो शिक्षकों पर पड़ रहा अतिरिक्त दबाव बच्चों की पढ़ाई को सीधे प्रभावित कर सकता है।

सरकार के निर्देश के बाद भी हालात जस के तस

यह स्थिति इसलिए भी गंभीर है क्योंकि 26 मई 2026 को मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग की समीक्षा बैठक में स्पष्ट निर्देश दिया गया था कि अगले छह से आठ महीने में कोई भी विद्यालय सिंगल टीचर के भरोसे नहीं चले। साथ ही रिक्त शिक्षक पदों को भरने को सरकार ने प्राथमिकता बताया था।सरकार के निर्देश का उद्देश्य विद्यालयों में शिक्षकों की उपलब्धता सुनिश्चित करना है, लेकिन जसपुर जैसे विद्यालयों में पर्याप्त शिक्षक नहीं होना विभागीय स्तर पर समीक्षा की जरूरत को सामने लाता है।

यहां भले ही विद्यालय पूरी तरह एकल शिक्षक के भरोसे नहीं है, लेकिन 101 बच्चों के लिए केवल दो शिक्षकों की उपलब्धता को लेकर ग्रामीण और अभिभावक सवाल उठा रहे हैं।

शिक्षक कम, फिर भी तबादले और प्रतिनियोजन पर सवाल

ग्रामीणों का सवाल है कि जिन विद्यालयों में बच्चों की संख्या अधिक है और शिक्षक पहले से कम हैं, वहां से शिक्षकों को दूसरे विद्यालयों में प्रतिनियोजित या स्थानांतरित करने का निर्णय किस आधार पर लिया जा रहा है? क्या शिक्षक स्थानांतरण और पदस्थापन में विद्यालय की वास्तविक जरूरत, छात्र संख्या और शिक्षक-छात्र अनुपात को प्राथमिकता दी जा रही है या अधिकारियों के स्तर से मनमाने तरीके से निर्णय लिए जा रहे हैं? झारखंड में शिक्षक स्थानांतरण के लिए विभाग ने ऑनलाइन पोर्टल भी बनाया है, जिसमें प्रक्रिया को पारदर्शी, निष्पक्ष और नियम आधारित बनाने का उल्लेख है।

सबसे तेज प्रयागराज, मुद्रक, प्रकाशक, स्वामी संपादक हनुमान प्रसाद शुक्ल द्वारा विपिन इंटरप्राइजेस 1/6सी/1 मास्टर जरूहुल हसन रोड़, कटरा, प्रयागराज से मुद्रित कराकर, करीमुददीनपुर पोस्ट अटरामपुर नवाबगंज प्रयागराज से प्रकाशित। मो नं. 9452842169। इस अंक में प्रकाशित समस्त समाचारों के चयन एवं संपादन हेतु पी.आ.बी. एक्ट के अंतर्गत उत्तरदायी तथा इनसे उत्पन्न समस्त विवाद का निपटारा इलाहाबाद न्यायालय में होगा। आपत्तियां एक सप्ताह के अंदर ही स्वीकार की जाएगी। समाचार पत्र की जिम्मेदारी लेखक व संवाददाता की होगी